वर्ष 13 • अंक 7 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 24 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

दलहन के दाम एमएसपी से कम

सत्य नडेला पृष्ठ 2

तकनीक से कंपनी जगत और सरकार को लुभाएंगे नडेला

एक नज़र

इस सप्ताह बाजार में रह सकता है उतार-चढ़ाव

वायदा एवं विकल्प खंड में फरवरी के अनुबंध समाप्त होने से पहले घरेलू बाजार में इस सप्ताह उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सोमवार को शुरू यात्रा से नए संकेत मिलने का इंतजार है। इसके अलावा बाजार प्रतिभागियों की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमान तथा बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि के आंकड़े पर नजर होगी। ये आंकड़े शुक्रवार को जारी होंगे। विश्लेषकों को उम्मीद है कि घरेलू संस्थानों की लिवाली से निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले व्यापक बाजार का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। बाजार पर नजर रखने वाले लोगों के अनुसार चीन में भी स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

दूरसंचार उद्योग को राहत देने पर हुई बैठक

दूरसंचार उद्योग को संकट से उबारने के लिए दूरसंचार विभाग और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की रविवार को बैठक हुई। यह बैठक परेशान दूरसंचार उद्योग को राहत देने के उपायों पर चर्चा के लिए हुई। इस समय दूरसंचार कंपनियां सांविधिक बकाये के कारण अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह बैठक दूरसंचार विभाग में हुई और करीब एक घंटे चली। समझा जा रहा है कि बैठक में सरकार के समक्ष उपलब्ध उन विकल्पों पर विचार किया गया, जो समायोजित सकल आय (एजीआर) के बकाए से प्रभावित उद्योग को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। रविवार को हुई बैठक के बारे में अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। बैठक में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। पृष्ठ 4

ऑरकॉम के कर्जदाताओं की बैठक सोमवार को

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम)ने रविवार को कहा कि कंपनी के कर्जदाताओं की एक बैठक सोमवार को होगी। बैठक के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक सीओसी सोमवार को यूवी ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी और रिलायंस जियो से मिली परिसंपत्ति बोली पर विचार करेगी, जिससे उधारदाताओं को लगभग 23,000 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद है। ऐसी खबरें हैं कि कि यूपी ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी ने आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की परिसंपत्तियों के लिए करीब 14,700 करोड़ रुपये की बोली लगाई है, जबकि रिलायंस जियो ने रिलायंस इन्फाटेल लिमिटेड की टावर और फाइबर परिसंपत्तियों के लिए 4,700 करोड़ रुपये की पेशकश की है।

मालवाहक गलियारे से भाड़े में आएगी 50 प्रतिशत कमी

वर्ष 2021 में रेलवे का समर्पित मालवहन गलियारा शुरू होने के बाद माल भाड़े में 50 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के प्रबंध निदेशक अनुराग सचान ने रविवार को यह बात कही। समर्पित मालवहन गलियारा देश के चार महानगर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का ही हिस्सा है। समर्पित मालवहन गलियारा परियोजना के तहत महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहर बंदरगाह से हरियाणा के रेवाड़ी तक पश्चिमी और पंजाब में लुधियाना से पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट दानकुनी तक पूर्वी रेल गलियारों का निर्माण होना है।

चीन को स्वास्थ्य उत्पादों के निर्यात पर रोक नहीं

विदेश व्यापार महानिदेशलय (डीजीएफटी) ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत ने चीन को स्वास्थ्य उपकरणों एवं उत्पादों के निर्यात पर किसी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया है। डीजीएफटी ने कहा कि भारत ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। इससे पहले सोशल मीडिया सहित मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि भारत ने इन उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच, चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करेगा। चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद वहां सामान्य जन-जीवन एवं कारोबार बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है।

विदेश में सूचीबद्धता होगी सरल

कंपनियां घरेलू बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना भी विदेशी बाजार में दे सकती हैं दस्तक

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 23 फरवरी

आने वाले समय में भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना भी विदेशी बाजार में सूचीबद्ध हो पाएंगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी कानून में संशोधन लाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। कंपनी संशोधन विधेयक के मौजूदा बजट सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में अनुपालन नियमों में ढील दिए जाने संबंधी बदलाव भी होंगे।

अधिकारी ने बताया, 'हम उन देशों की फेहरिस्त बनाएंगे, जहां भारतीय कंपनियां विदेशी निवेश पाने के लिए सूचीबद्ध हो सकती हैं। ये देश परिपक्व एवं फाइनैंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नियमों का अनुपालन करने वाले होंगे।'

फिलहाल भारतीय कंपनियां विदेशी निवेश हासिल करने के लिए अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट (एडीआर) या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) विकल्प का इस्तेमाल करती हैं। इन्फोसिस अमेरिका के नामी एक्सचेंज नैसडैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय तकनीकी कंपनी थी। अधिकारी ने कहा, 'तकनीकी क्षेत्र की कई कंपनियां दूसरे देशों में सूचीबद्ध होना चाहती हैं, दूसरी तरफ हम उन्हें घरेलू बाजारों में सूचीबद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं।'

- प्रस्तावित प्रावधान में भारत में पहले सूचीबद्ध होने की जरूरत नहीं
- कंपनियां नए शेयर जारी कर मौजूदा शेयरधारिता के जरिये हो सकती हैं सूचीबद्ध
- इस समय एडीआर या जीडीआर के जरिये भारतीय कंपनियां होती हैं सूचीबद्ध
- अपराध से जुड़े प्रावधानों में भी होगा बदलाव

नैसडैक में सूचीबद्ध ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेकमाईट्रिप ने भी यही रास्ता अपनाया है। इस बारे में एक वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा,'कंपनियां विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध होना चाहती हैं, क्योंकि वहां निवेशक अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध होने से उनके शेयरों का लेनदेन भी बढ़ता है।' उन्होंने ओयो होटल्स ऐंड होम्स का उदाहरण दिया, जिसने अमेरिका में एक अलग इकाई बनाकर विदेश में कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

सलाहकार कंपनी इनगवर्न के प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यन ने कहा, 'कंपनियां लंबे से इस सुधार का इंतजार कर रही थी।' वर्ष 2018 में सेबी की एक समिति ने घरेलू कंपनियों को उन बाजारों में ही सूचीबद्ध होने की अनुमति देने की सिफारिश की थी, जिनके साथ सूचनाएं साझा करने की संधि की गई है और किसी जांच की नौबत आने पर वे सहयोग करेंगे।

कंपनी मामलों का मंत्रालय कानून में एक और प्रावधान लाने की योजना भी तैयार कर रहा है, जिससे बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को एमसीए 21 पोर्टल पर तिमाही नतीजे प्रकाशित करने होंगे। इस पर अधिकारी ने कहा, 'हम कंपनियों की एक ऐसी श्रेणी तैयार करेंगे, जो इस प्रस्तावित कानून के तहत आएगी।' हालांकि एमसीए निजी कंपनियों की कुछ खास श्रेणियों के लिए अनुपालन नियमों में ढील देगा, जो ऋण (डेट) प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करती हैं। इस समय डेट प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने के लिहाज से सभी निजी कंपनियों को एक समान दर्जा दिया जाता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार आपराधिक उपखंड हटाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करेगी। मंत्रालय हल्की-फुल्की श्रेणी में आने वाले 23 अपराधों को दोबारा सूचीबद्ध करेगी और इन पर कम जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही मंत्रालय 11 अपराधों को केवल जुर्माने की अदायगी तक ही सीमित रखेगा और कारावास का प्रावधान खत्म कर देगा।

वीआरएस से हुईं सेवाएं प्रभावित

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 23 फरवरी

अहमदाबाद के सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी विनोद देसाई अपने खराब पड़े लैंडलाइन टेलीफोन की शिकायत लेकर पिछले दो महीने से हर हफ्ते भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के स्थानीय कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। उनके मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस के कारण कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है जिससे कामकाज पर असर पड़ा है। देसाई अब निजी सेवा प्रदाता से लैंडलाइन कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं।

- बीएसएनएल के 55 फीसदी कर्मचारियों ने लिया वीआरएस
- एमटीएनएल के 75 फीसदी कर्मचारी भी वीआरएस लेकर निकले
- कर्मचारियों की कमी से लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रभावित

कई वर्षों से बीएसएनएल के समर्पित ग्राहक रहे देसाई अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इस सरकारी कंपनी ने निराश किया है। उनके ही शहर के कारोबारी जियो वर्गीज की भी शिकायत है कि उनके बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्पीड बहुत धीमी है। कंपनी के करीब 55 फीसदी कर्मचारी वीआरएस ले चुके हैं।

बीएसएनएल का लैंडलाइन इस्तेमाल करने वाले हैदराबाद के सुरेश कुमार का कहना है कि कंपनी शिकायतों का निपटारा करने में पहले से कहीं ज्यादा समय ले रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने देशभर में बीएसएनएल के कई लैंडलाइन और मोबाइल उपभोक्ताओं से संपर्क किया और उनमें से अधिकांश का ऐसा ही अनुभव था। इसकी वजह वीआरएस है।

देशभर में बीएसएनएल की सेवाओं से लोग परेशान हैं तो दिल्ली और मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की सेवाओं की भी कमोबेश यही स्थिति है। मुंबई में एमटीएनएल के एक नाराज उपभोक्ता ने कहा, 'मेरा लैंडलाइन कई हफ्तों से खराब पड़ा है और कई बार शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। मैंने इस बारे में एमटीएनएल के शीर्ष अधिकारियों को भी फोन किया लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसा लगता है कि शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी के पास कर्मचारी ही नहीं हैं।' मुंबई में लैंडलाइन के चार से छह हफ्ते तक खराब पड़े रहना आम बात है और ब्रॉडबैंड की भी यही स्थिति है। अगर कोई उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर दिल्ली या मुंबई में एमटीएनएल के ऑफिस पहुंचता है तो उसे शायद ही कोई मिलता है। एमटीएनएल के करीब 75 फीसदी कर्मचारी वीआरएस लेकर निकल चुके हैं।

आधिकारिक रुख

हालांकि नई दिल्ली के जनपथ स्थित बीएसएनएल का भव्य मुख्यालय चौतरफा फैली मायूसी को ठीक से बयां नहीं करता है। बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि मौजूदा कर्मचारियों ने आसन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में अनुकूल रुख दिखाया है। संख्या काफी बड़ी है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने एक झटके में ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के जरिये 93,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। वीआरएस लेने वालों में बीएसएनएल के 78,569 और एमटीएनएल के 14,300 कर्मचारी शामिल हैं। बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि इस सरकारी कंपनी में कर्मचारी जरूरत से अधिक थे लिहाजा इतनी बड़ी संख्या में वीआरएस लेने के बावजूद कंपनी के कामकाज पर नाममात्र का असर पड़ेगा। शेष पृष्ठ 9

ट्रंप के स्वागत के लिए तैयार भारत

एजेंसियां
नई दिल्ली, 23 फरवरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सामरिक संबंधों के प्रगाढ़ होने की उम्मीद है लेकिन व्यापार शुल्क जैसे जटिल मुद्दों पर प्रगति की संभावना नहीं है। भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को होने वाली वार्ता व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी, ऊर्जा सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ प्रस्तावित शांति समझौता और हिंद-प्रशांत की स्थिति सहित कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्त्व के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब देश में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहे हैं और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में तनाव है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सार्वजनिक और निजी बातचीत में लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की हमारी साझी परंपरा के बारे में बात करेंगे। वह इन मुद्दों को उठाएंगे। विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा इस प्रशासन के लिए अत्यंत अहम है। रिश्तों में सिलवटों के बावजूद, दोनों पक्ष ट्रंप की पहली भारत यात्रा को दो लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ती वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के प्रतिबिंब के तौर पर दिखाना चाहते हैं।

- दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सामरिक संबंध प्रगाढ़ होने की उम्मीद
- हालांकि व्यापार शुल्क जैसे जटिल मुद्दों पर प्रगति की संभावना नहीं
- देश में सीएए पर हो रहे विरोध के बीच ट्रंप आ रहे भारत

इस बीच मोदी ने रविवार को कहा कि भारत ट्रंप के स्वागत को लेकर उत्सुक है। मोदी ने ट्वीट किया, 'भारत डॉनल्ड ट्रप का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। यह सम्मान की बात होगी कि वह कल हमारे साथ होंगे, जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम से होगी।'

ट्रंप के साथ भारत आ रहे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में उनकी पुत्री इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ट्रंप 36 घंटे से कम समय की अपनी भारत यात्रा के तहत सोमवार को अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद से वह आगरा जाएंगे जहां वह ताजमहल का दीदार करेंगे। ट्रंप परिवार सूर्यास्त से पहले करीब एक घंटे ताजमहल में रुकेगा और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएगा।

(संबंधित खबरें पृष्ठ 12)

बड़े पैमाने पर जारी होंगे बॉन्ड

सरकार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में बड़े पैमाने पर विशेष श्रेणी के सरकारी बॉन्ड बाजार में जारी करने की योजना बना रही है। ये बॉन्ड करीब 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के होंगे। इसके बाद कई और हिस्सों में ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बॉन्ड वित्त वर्ष 2020-21 के उधारी लक्ष्य 8.1 लाख करोड़ रुपये के 10 प्रतिशत से अधिक (80,000 करोड़ रुपये) मूल्य के होंगे। इस बारे में एक शीर्ष अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'वित्त मंत्रालय का मानना है कि एक साल में विशेष श्रेणी के बॉन्ड का मूल्य कुल उधारी लक्ष्य का 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। मार्च अंत तक अप्रैल-सितंबर के उधारी कार्यक्रम की घोषणा होने तक सरकार आरबीआई के साथ सलाह-मशविरा के बाद बाजार में बॉन्ड और इनके अगले हिस्से के बारे में रणनीति तय करेगा। पृष्ठ 4

सस्ते में बैंकॉक की सैर कराएगा कोरोनावायरस

अनीश फडणीस
मुंबई, 23 फरवरी

कोरोनावायरस के प्रकोप से पर्यटकों की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तरह-तरह की छूट देने की योजना बना रहे हैं। इनमें उड़ानों में 10 किलो अतिरिक्त सामान मुफ्त ले जाने की छूट, मॉल और रेस्टोरेंट में रियायत तथा क्रूज से फारस की खाड़ी में यात्रा का विकल्प शामिल है।

इंडोनेशिया विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए भारी छूट देने की योजना बना रहा है जबकि सिंगापुर ने होटलों और ट्रैवल कंपनियों को राहत पैकेज की घोषणा की है।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की सरकारें ऐसे वक्त अपने यहां पर्यटन गतिविधियों को पटरी पर लाने के उपायों की योजना बना रही हैं जब शनिवार को भारत ने अपने नागरिकों को बेहद जरूरी न होने पर सिंगापुर न जाने की सलाह दी है।

कोरोनावायरस के संक्रमण से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पर्यटन उद्योग को भारी झटका लगा है। थाईलैंड में पिछले साल एक करोड़ से अधिक चीनी पर्यटक आए थे जो देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या का एक तिहाई हैं। चीन और रूस से थाईलैंड आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है लेकिन अमेरिका और यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। थाई सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छूट और विशेष पेशकश कर रही है।

थाईलैंड के पर्यटन विभाग के अंतरराष्ट्रीय विपणन के डिप्टी गवर्नर चट्टन कुंजरा ना अयोध्या ने कहा, 'हम होटलों, डिपार्टमेंट स्टोरों और विमानन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी योजना अप्रैल से नई पेशकश लाने की है। लेकिन हम केवल छूट नहीं देना चाहते हैं। हम विश्वास बढ़ाने के उपाय कर रहे हैं। हम खुले दिल से पर्यटकों का स्वागत करने को तैयार हैं। हमारे यहां स्थिति सामान्य है।'

इनमें से एक प्रस्तावित पेशकश को 'गिव मी टेन' नाम दिया गया है। इसके तहत थाईलैंड से स्वदेश वापसी की उड़ान में 10 किलो अतिरिक्त सामान मुफ्त में ले जाने की सुविधा दी जाएगी। पर्यटन विभाग इस पर अपने देश की विमानन कंपनियों को सब्सिडी देगा। अयोध्या ने कहा, 'यह पर्यटकों, स्टोरों और विमानन कंपनियों, सबके लिए अच्छी पेशकश है।' इसके तहत प्रति टिकट के आधार पर अतिरिक्त सामान पर फीस नहीं वसूली जाएगी और यह योजना अप्रैल से शुरू होगी।

- थाईलैंड और इंडोनेशिया देंगे कई तरह की छूट
- उड़ानों में ला सकेंगे 10 किलो अतिरिक्त सामान मुफ्त
- क्रूज के जरिये यात्रा का विकल्प
- मॉल में खरीदारी और रेस्टोरेंट में रियायत

जकार्ता पोस्ट अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया टूर पैकेज में छूट देने की योजना बना रहा है। साथ ही विमानन कंपनियों को स्थानीय हवाईअड्डों पर सेवा शुल्क भी माफ किया जा रहा है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मंत्रिमंडल की एक बैठक में इस योजना का खुलासा किया।

सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक जी बी श्रीधर ने कहा, 'हम भारत में अपने साझेदारों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें देश की ताजा स्थिति तथा कोरोनावायरस को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत करा रहे हैं। हमारा पर्यटन उद्योग कारोबार के लिए पूरी तरह तैयार है और हमने सिंगापुर आने वाले पर्यटकों को एहतियात के बारे में सुझाव दिए हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमारा अनुमान है कि 2020 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 25 से 30 फीसदी तक की कमी आएगी। क्रूज पर्यटन पर इसके असर के बारे में अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि हमें उम्मीद है कि हमारा क्रूज पर्यटन इससे निपटने में सक्षम है और उसके पास वृद्धि के लिए ठोस नीव है।'

हालांकि दिग्गज क्रूज कंपनी रॉयल कैरीबियन क्रूजेज अपनी तरफ से मार्च के मध्य तक सिंगापुर से अपनी यात्रा स्थगित करा रहे पर्यटकों को फ्यूचर क्रेडिट दे रही है और उसी कीमत पर उन्हें दुबई से वैकल्पिक यात्रा का विकल्प दे रही है।

रॉयल कैरीबियन क्रूजेज के भारतीय प्रतिनिधि तिरुन की सह-संस्थापक और चेयरपर्सन रत्ना चड्ढा ने कहा, 'हम एशिया से बाहर क्रूज भेजने का विकल्प तराश रहे हैं। उदाहरण के लिए दुबई में हमारे सात नाइट क्रूज हैं। हम भारतीयों के लिए खास पेशकश कर रहे हैं। यह पेशकश खासकर भारतीय बाजार के लिए की जा रही है क्योंकि हम आसपास ही क्रूज यात्रा को वरीयता देते हैं। इन यात्राओं के लिए केवल एक वीजा की जरूरत है।'

एशिया में इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि कितने बंदरगाह क्रूज को आने की अनुमति देंगे। इसके कारण हॉलैंड अमेरिका लाइन ने वेस्टरडैम क्रूज शिप की मार्च और अप्रैल में होने वाली एशिया यात्रा रद्द कर दी है। कंपनी ने कहा कि सभी मेहमानों को पूरा पैसा वापस किया जाएगा।

संक्षेप में

पांच नए स्टोर शुरू करेगी मेट्रो कैश ऐंड कैरी

जर्मनी की खुदरा कंपनी मेट्रो कैश ऐंड कैरी की योजना भारत में इस साल पांच नए स्टोर खोलने तथा ई-वाणिज्य में स्थिति मजबूत करने के साथ ही किराना दुकानों के साथ गठजोड़ बढ़ाने की है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। कंपनी बेंगलूरु, हैदराबाद और दिल्ली में अभी तक दो हजार किराना दुकानों के साथ गठजोड़ कर चुकी है। मेट्रो कैश ऐंड कैरी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अरविंद मेदिरत्ता ने कहा, कंपनी को लगता है कि भारत वृद्धि के लिए एक मुख्य बाजार है। भारत में किराना दुकानों तथा ई-वाणिज्य दोनों के लिए वृद्धि के अपार अवसर हैं। उन्होंने कंपनी की विस्तार की योजनाओं के बारे में कहा कि इस साल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पांच नए स्टोर शुरू किए जाएंगे। कंपनी के अभी 17 भारतीय शहरों में 27 स्टोर हैं। *भाषा*

भारतीय स्टेट बैंक करेगा परिसंपत्तियां नीलाम

अपना बकाया वसूलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक 26 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों की ई-नीलामी करेगा। इन परिसंपत्तियों में कर्ज न चुकाने वालों के मकान, औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं। ये दबाव वाली परिसंपत्तियां हैं और बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार इस बाबत प्रावधान किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रावधान से नियामकीय अनिवार्यताएं कवर होती हैं, लेकिन बैंक के पास कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपना बकाया वापस पाने का अधिकार है। एसबीआई ने एक बयान में कहा कि जब अचल परिसंपत्तियां (चाहे हमारे पास जमानत रखी गई हो या अदालत के आदेश से जब्त की गई हो) नीलामी के लिए रखी जाती है तो यह काफी पारदर्शी होती है। *बीएस*

तकनीक से कंपनी जगत, सरकार को लुभाएंगे सत्य नडेला

पीरजादा अबरार और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 23 फरवरी

पांच साल पहले माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य कार्याधिकारी बनने के बाद जब सत्य नडेला पहली बार भारत आए थे तो कंपनी थोड़ी परेशानी में थी और वित्तीय स्थिति पर दबाव था। तब से काफी कुछ बदला है। एंटरप्राइज क्लाउड के मजबूत क्रियान्वयन से माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण करीब पांच गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ डॉलर के पार चला गया।

हैदराबाद में जन्मे नडेला इस हफ्ते तीन दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं और उनका अहम मिशन कंपनियों के अलावा सरकार को ऐसे समय में लुभाने का होगा जब भारत कंपनी के लिए काफी अहम रणनीतिक बाजार बन गया है। हालांकि भारत के संशोधित नागरिकता कानून पर नडेला की विवादास्पद टिप्पणी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दौरे के समय उनकी यात्रा से काफी अटकलें लगाई जा रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की आखिर क्या योजना है।

कुछ का मानना है कि बड़े आईटी सौदे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बड़ा सरकारी सौदा या रणनीतिक साझेदारी देखने को मिल सकती है। कंपनी की नजर 100 अरब डॉलर के डिजिटल कायापलट के मौकों पर है, और वह भारत में एमेजॉन व गूगल को सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी के तौर पर देख रही है। माइक्रोसॉफ्ट की भारतीय रणनीति पर नजर रखने वालों का ऐसा मानना है।

वित्त वर्ष 2019 में माइक्रोसॉफ्ट का राजस्व 13 फीसदी बढ़कर 7,301 करोड़ रुपये रहा, वहीं शुद्ध लाभ 8 फीसदी बढ़कर 386 करोड़ रुपये रहा क्योंकि फर्म अपने क्लाउड कारोबार अजूरे व ऑफिस 365 प्रॉडक्ट का विस्तार जारी रखे हुए है।

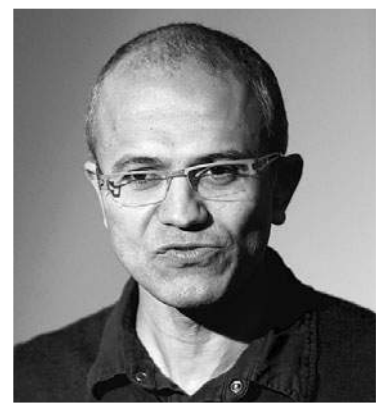

सत्य नडेला, सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट

कंपनी बड़ी साझेदारी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, रिलायंस जियो और बी2बी मार्केटप्लेस उड़ान को गिनती है। कंपनी इस देश में कुछ लाख एमएसएमई व हजारों स्टार्टअप को ग्राहक मानती है।

ग्रेहाउन्ड रिसर्च के मुख्य विश्लेषक व सीईओ संचित वीर गोगिया ने कहा, भारत दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक है।

इस महीने माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में डेवलपमेंट सेंटर खोलने का ऐलान किया, जो हैदराबाद व बेंगलूरु के बाद देश का तीसरा केंद्र है। दौरे से ठीक पहले उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि निवेश राजनीतिक तौर पर अहम है क्योंकि यूपी व केंद्र पर एक ही पार्टी की सरकार है।

नडेला का सबसे ज्यादा ध्यान हालांकि मौजूदा कारोबारी साझेदारों व बड़े समुदायों के बीच भरोसा बनाने पर हो सकता है।

ईवाई इंडिया के पार्टनर व नैशनल लीडर (ई-कॉमर्स व उपभोक्ता हित) अंकुर पाहवा ने कहा, नडेला के दौरे से उम्मीद यह है कि कंपनी भारत में किए निवेश पर प्रतिबद्धता बनाए रखा जाएगा, खास तौर से उन क्षेत्रों में जो डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बौद्धिकता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग अपनाने और स्मार्ट सिटी के विकास में।

इस फर्म का काफी ध्यान कृत्रिम बौद्धिकता, स्टार्टअप व डेवलपर कम्युनिटी पर है। कंपनी ने इस महीने भारतीय कार्यालय में जीआईटी हब शुरू करने की घोषणा की है। जीआईटीहब ओपन सोर्स की सबसे बड़ी रिपॉजिटरी है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2018 में 7.5 अरब डॉलर में अधिग्रहीत किया था।

आखिर में सबकी नजर इस पर होगी कि सरकार के साथ नडेला की बातचीत कैसी रहती है क्योंकि एमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ आम लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। एक सूत्र ने कहा, हालांकि एमेजॉन के जेफ बेजोस के मुकाबले नडेला का भारत सरका के साथ बेहतर संबंध है।

परियोजना साझेदार तलाश रही टीसीजी

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 23 फरवरी

ओडिशा और तमिलनाडु की आगामी पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं में इक्विटी साझेदार व रणनीतिक निवेशक बनाने के लिए के लिए द चटर्जी ग्रुप (टीसीजी) वैश्विक तेल व पेट्रोकेमिकल कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है।

सूत्रों ने कहा, इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टीसीजी 2:1 कर्ज-इक्विटी अनुपात पर विचार कर रहा है, साथ ही समूह अगले छह महीने में पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों व बैंकों से संपर्क करेगा।

इस समूह का स्वामित्व एनआरआई कारोबारी पूर्णेंदु चटर्जी के पास है और वह ओडिशा व तमिलनाडु में क्रमश: 78,000 करोड़ रुपये व 50,000 करोड़ रुपये निवेश करेंगे। हालांकि वह अकेले पूरा निवेश नहीं करेंगे।

सूत्रों ने कहा, अनुमानित निवेश पांच साल में होगा और परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ रकम की जरूरत होगी। टीसीजी इक्विटी साझेदार व रणनीतिक निवेशकों के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है।

तमिलनाडु में कड्डलोर की परियोजना सबसे पहले आएगी। टीसीजी की मुख्य कंपनी हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एनसीएलटी से मंजूरी के बाद नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 2,100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर सकती है।

नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड परिसमापन का सामना कर रही है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के अलावा एकॉर्ड डिस्टिलर्स और अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन ने भी परिसमापन प्रक्रिया के दौरान बोली जमा कराई थी।

एक सूत्र ने कहा, नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जमीन आसानी से उपलब्ध है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण सबसे पहले ओडिशा में करना होगा, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में उम्मीद है कि तमिलनाडु में पेट्रोकेमिकल परियोजना ओडिशा से पहले शुरू होगी।

सूत्रों ने कहा कि नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिफाइनरी का निर्माण शुरू किए जाने के तुरंत बाद कंपनी को एनसीएलटी भेज दिया गया ता, ऐसे में ज्यादातर जमीन खाली है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी के बजाय पेट्रोकेमिकल परियोजना लाएगी।

ओडिशा में राज्य सरकार ने बालासोर में 3320 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है, जो आगामी सुवर्णरेखा बंदरगाह के पास है। इस परियोजना में 1.08 पॉलिथिलीन यूनिट, पैराक्सिलीन की 1.6 एमटीपीए इकाई और 1.25 एमटीपीए प्यूरिफाइड टेरेफ्थलिक एसिड की होगी। साथ ही लाइट कच्चे तेल की रिफाइनरी भी होगी। एरोमैटिक्स कॉम्पलेक्स और एथिलीन कॉम्पलेक्स की भी स्थापना होगी।

सूत्रों के मुताबिक, एनसीएलटी की मंजूरी के बाद तमिलनाडु में काम छह महीने के भीतर शुरू हो सकता है, लेकिन ओडिशा की परियोजना में काम शुरू होने में दो साल लग सकते हैं क्योंकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले पूरी करनी होगी और पर्यावरण आदि की मंजूरी हासिल करनी होगी।

ओडिशा में अधिग्रहीत होने वाली कुल जमीन में 900 एकड़ निजी क्षेत्र की है जबकि 700 एकड़ जंगल की जमीन है। राज्य सरकार के पास करीब 800 एकड़ जमीन है जबकि बाकी भूदान वाली जमीन व अन्य जमीन है।

उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि राज्य में इस अनुपात में जमीन का अधिग्रहण संवेदनशील मामला है क्योंकि विगत में दक्षिण कोरियाई फर्म पोस्को को जमीन के मसले के कारण पीछे हटना पड़ा था।

इस बारे में पूछे जाने पर टीसीजी के अधिकारी ने टिप्पणी से मना कर दिया। टीसीजी ने हालांकि तमिलनाडु व ओडिशा में बड़े निवेश का फैसला लिया है, लेकिन हल्दिया के परिचालन में यथास्थिति बनाए रखने का भी फैसला लिया है।

विदेशी फर्मों से हो रही बातचीत

- टीसीजी समूह ओडिशा व तमिलनाडु में क्रमशः 78,000 करोड़ रुपये व 50,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा
- इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टीसीजी 2:1 कर्ज-इक्विटी अनुपात पर विचार कर रहा है
- समूह अगले छह महीने में पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों व बैंकों से संपर्क करेगा
- अनुमानित निवेश पांच साल में होगा और परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ रकम की जरूरत होगी
- टीसीजी इक्विटी साझेदार और रणनीतिक निवेशकों के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ कर रहा बातचीत

एसीसी, अंबुजा सीमेंट में नई नियुक्तियों से होगा फायदा

अमृता पिल्लई
मुंबई, 23 फरवरी

लाफार्जहोल्सिम नियंत्रित एसीसी और अंबुजा सीमेंट में पिछले हफ्ते नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से समूह में रिपोर्टिंग का ढांचा बेहतर होने की उम्मीद है और इससे परिचालन भी बेहतर हो पाएगा।

एसीसी ने गुरुवार को कहा कि कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी नीरज अखौरी ने करियर में अन्य संभावना तलाशने के लिए इस्तीफा दे दिया, जो गुरुवार से ही प्रभावी हुआ। एक अलग घोषणा में अंबुजा सीमेंट ने कहा कि अखौरी कंपनी के नए प्रबंध निदेशक व सीईओ हैं और दूसरी जगह काम करने के लिए इस पद से विमलेंद्र झा ने इस्तीफा दे दिया।

एसीसी में पूर्व मुख्य वाणिज्य अधिकारी श्रीधर बालाकृष्णन को नया सीईओ व एमडी नियुक्त किया गया है, वहीं अखौरी एसीसी बोर्ड के निदेशक मंडल में बने रहेंगे।

दोनों कंपनियों ने एक्सचेंजों को भेजे बयान में कहा है कि इस घटनाक्रम की कोई अन्य वजह नहीं है। विश्लेषकों को हालांकि लग रहा है कि नई नियुक्ति से लाफार्जहोल्सिम को भारत में दोनों सीमेंट कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल में मदद मिलेगी।

दोनों भारतीय सीमेंट दिग्गज के संभावित विलय ने बाजार को करीब एक दशक से अटकल लगाने को छोड़ रखा है। चूंकि विलय की कोई योजना सामने नहीं है, ऐसे में उद्योग के विशेषज्ञ नई नियुक्तियों को उनकी रिपोर्टिंग के ढांचे को बेहतर बनाने में मददगार के तौर पर देख रहे हैं।

एंबिट कैपिटल के शोध प्रमुख (संस्थागत इक्विटीज) नितिन भसीन ने कहा, एसीसी और अंबुजा में नई नियुक्तियों को दो कंपनियों में रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के एक और कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद अंबुजा व एसीसी के बीच बेहतर जुड़ाव होगा।

उद्योग के सूत्रों ने कहा, एसीसी के प्रबंध निदेशक के तौर पर अखौरी ने सीधे लाफार्जहोल्सिम के भारतीय प्रमुख को रिपोर्ट किया। नई नियुक्ति के साथ एसीसी के नए एमडी अब अंबुजा के नए एमडी अखौरी को रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे अंबुजा सीमेंट व एसीसी के बीच रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस बारे में जानकारी के लिए शुक्रवार को अंबुजा सीमेंट को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला।

साल 2016 में समूह की होल्डिंग के पुनर्गठन के तहत एसीसी को अंबुजा सीमेंट की सहायक बनाया गया, जिसकी हिस्सेदारी एसीसी में अभी 50.05 फीसदी है। दूसरी ओर लाफार्जहोल्सिम समूह के पास अंबुजा सीमेंट की 63.39 फीसदी हिस्सेदारी है।

एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स ने साल 2017 में विलय का विकल्प तलाशा, हालांकि बाद में यह फैसला टाल दिया गया। मार्च 2018 में इसके बजाय दोनों कंपनियों ने मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट का फैसला लिया, जो दोनों कंपनियों के बीच परिचालन को और बेहतर बनाने के लिए था। एक विश्लेषक ने कहा, नई नियुक्तियां मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट को जारी रखने के लिए है, जिसका अभी तक कोई असर नहीं दिखा है।

अखौरी ने फरवरी 2017 में एमडी व सीईओ का पद संभाला था, हालांकि लाफार्जहोल्सिम समूह के साथ इनका जुड़ाव लंबा रहा है। एसीसी में नियुक्ति से पहले अखौरी लाफार्ज सुरमा सीमेंट के सीईओ थे और बांग्लादेश में लाफार्जहोल्सिम के प्रतिनिधि। लाफार्ज व होल्सिम के वैश्विक विलय के बाद उन्हें एसीसी में लाया गया।

उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि अखौरी एसीसी के प्रति लाफार्ज समूह की आक्रामकता लाने में सक्षम रहे हैं और नई नियुक्ति के साथ अंबुजा सीमेंट में भी ऐसी ही रणनीति देखने को मिल सकती है।

एसीसी, अंबुजा के कदम

- 2015 : लाफार्जहोल्सिम वैश्विक विलय का ऐलान
- 2016 : एसीसी को अंबुजा सीमेंट का सहायक बनाया गया
- 2017 : लाफार्ज सुरमा सीमेंट से नीरज अखौरी आए एसीसी
- 2018 : श्रीधर बालाकृष्णन बने एसीसी में सीसीओ
- 2020 : अखौरी को अंबुजा सीमेंट का सीईओ व एमडी नियुक्त किया गया

दलहन के दाम एमएसपी से कम

डब्बा कारोबार और मटर की तस्करी से मिला दामों में इस गिरावट को बढ़ावा। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से की जा रही बड़ी मात्रा में मटर की तस्करी, इनमें से कोई नहीं करता मटर की खेती

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 23 फरवरी

दलहन

- कनाडा और अन्य देशों से आयात की जाती है तस्करी वाली यह मटर
- इस तस्करी से होती है 50 प्रतिशत की भारी कर चोरी,
- सस्ती दर पर बिकता है ऐसा माल, इस कारण भारत में कम हो रहे हैं दलहन के दाम
- रबी की कटाई में रह गया है कुछ ही सप्ताह का समय
- रबी के कटाई सत्र से पहले दलहन के दामों में यह गिरावट किसानों के लिए साबित हो सकती है बड़ा झटका

रबी की कटाई में कुछ ही सप्ताह का समय रहने के कारण चुनिंदा मंडियों में दलहन के दाम गिरकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी कम स्तर पर चल रहे हैं। एमएसपी वह सीमा होती है जिस पर सरकार जिंस की खरीद करती है।

जहां एक ओर कर्नाटक के गडग में चना अपने एमएसपी 4,620 रुपये प्रति क्विंटल से 11 प्रतिशत कम 4,122 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के नसरूल्लागंज में मूंग के दाम अपने एमएसपी 7,050 रुपये प्रति क्विंटल से 26 प्रतिशत फिसलकर 5,201 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। इसी तरह तुअर (अरहर), मसूर और उड़द भी फिलहाल अपने एमएसपी की तुलना में काफी कम दामों पर बिक रही हैं।

रबी के कटाई सत्र से पहले दलहन के दामों में यह गिरावट उन किसानों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, जो इस साल कम रकबे के कारण बेहतर आमदनी की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि दलहन के दामों में गिरावट पर विशेषज्ञों की अलग राय है।

मुंबई के दलहन कारोबारी पंचम इंटरनैशनल के प्रबंध निदेशक विमल कोठारी ने कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से सड़क परिवहन के जरिये मटर की बड़ी मात्रा में भारत में तस्करी की जा रही है। इनमें से कोई भी देश मटर की खेती नहीं करता है। यह मटर कनाडा और अन्य देशों से आयात की जाती है। चूंकि इस तस्करी से 50 प्रतिशत की भारी कर चोरी होती है, इसलिए ऐसे आयात में सस्ती दर पर अपना माल बेचने की गुंजाइश रहती है। इससे भारत में दलहन के दाम कम हो रहे हैं।

निजी कंपनी नैशनल कोलैटेरल मैनेजमेंट सर्विसेज (एनसीएमएल) ने पूर्वानुमान जताया है कि इस साल देश में रबी का दलहन उत्पादन 2.1 प्रतिशत तक गिरकर 1.448 करोड़ टन रहेगा, जबकि पिछले साल इस सत्र में 1.48 करोड़ टन उत्पादन दर्ज किया गया था। देश के दलहन उत्पादन में रबी सत्र का योगदान करीब 60 प्रतिशत रहता है। शेष योगदान खरीफ सत्र का रहता है।

इसकी नवीनतम रिपोर्ट में रबी कटाई के आगामी सत्र के दौरान चने का उत्पादन 5.4 प्रतिशत गिरकर 95.8 लाख टन रहने का पूर्वानुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल 1.013 करोड़ टन उत्पादन दर्ज किया गया था।

मटर आयात को हतोत्साहित करने और देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मटर पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आयात मूल्य के रूप में प्रति किलोग्राम 200 रुपये निर्धारित किए गए थे। इससे कनाडा, रूस या यूक्रेन से मटर की आयात लागत 325 रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। करोबारियों के लिए कुछ लाभ के साथ न्यूनतम खुदरा दाम 350 से 375 रुपये रहना आदर्श स्थिति होती है।

कोठारी ने कहा कि चना मटर का विकल्प होता है और इस कारण कारोबारी घरेलू किसानों को नुकसान पहुंचाते हुए अवैध तरीके से विदेशों से इसकी आपूर्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा अवैध कारोबार तत्काल रोकने की जरूरत है।

इस बीच राजस्थान दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूलाल गोयल ने दलहन के दामों में गिरावट पर अलग दास्तान बयां की। गोयल ने कहा कि डब्बा कारोबारी (जो द्विपक्षीय कारोबार में बोली के लिए जिंस एक्सचेंजों पर प्रचलित दामों को रेफ्रेंस प्वाइंट के रूप में प्रयोग करते हैं) मौजूदा कटाई सत्र के दौरान अपना स्टॉक तैयार करने और भविष्य में इसके दाम बढ़ने पर मुनाफा पाने का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए चने के दाम कम बोल रहे हैं। इसलिए डब्बा कारोबार पर रोक लगाई जानी चाहिए।

गोयल के अनुसार सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यापार के लिए उपलब्ध दलहन की पूरी मात्रा की खरीद करनी चाहिए। खास तौर पर ऐसे समय में जब दाम एमएसपी से नीचे चले जाएं।

गोयल ने कहा कि सरकार ने पिछले साल कमजोर सत्र में बेचने के लिए एमएसपी पर करीब 20 लाख टन दलहन खरीदी थी। लेकिन बिक्री ऐसे समय में की जाती है, जब दलहन के दाम एमएसपी से नीचे जा चुके हैं। इससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। गोयल ने कहा कि कटाई सत्र में दलहन के दामों में गिरावट से किसानों की आमदनी कम होने वाली है। इससे उन्हें दबाव में आकर बिक्री करनी होगी और इसके परिणामस्वरूप उनका कर्ज बढ़ेगा।

चाय कंपनियों को उबारने की हो रही तैयारी

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 23 फरवरी

केंद्र सरकार बीमारू चाय कंपनियों में जान फूंकने के लिए पुनरुद्धार पैकेज लाने की योजना बना रही है। ये वे कंपनियां हैं जिन्हें बढ़ती लागत के कारण काफी नुकसान हुआ है और ऋणदाता इन कंपनियों को ऋण देने के इच्छुक नहीं है। इस पैकेज का उद्देश्य कुछ हद तक वित्तीय दबाव कम करने के साथ-साथ नकदी प्रवाह की स्थिति में सुधार करना है।

इस पैकेज में सभी कंपनियों के लिए 300 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान शामिल हो सकता है। परंपरागत बुआई और कुछ मामलों में दोबारा की जाने वाली बुआई की जो सब्सिडी पांच सालों से लटकी हुई है, वह भी चाय कंपनियों को दी जा सकती है। इसके अलावा संसद द्वारा पारित श्रम संहिता लागू करने के लिए बागान कंपनियों को एक से डेढ़ साल की छूट भी दी जा सकती है।

भारतीय चाय बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन एके रे ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार होने वाला है और हम उद्योग से भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। श्रम संहिता के परिणामस्वरूप मजदूरी में इजाफा होने के कारण पहले से तनावग्रस्त चाय कंपनियों के लिए मामला और उलझ जाएगा। इसलिए कुछ मदद की आवश्यकता है। इस पैकेज को इस साल अप्रैल से मई के दौरान मंजूरी मिलने की संभावना है। यह पैकेज ऐसे समय में लाया जा रहा है जब मैकलॉयड रसेल, वारेन टी, जय श्री टी जैसी कई बड़ी कंपनियां कर्ज कम करने के लिए अपने बागान बेच रही हैं और लागत बढ़ने की भी संभावना है।

थर्मल कोयला आयात में गिरावट

देश में बिजलीघरों के लिए थर्मल कोल का आयात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के दौरान 14.98 प्रतिशत घट कर 746 लाख टन रहा। भारतीय बंदरगाह संगठन (आईपीए) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। देश के 12 प्रमुख बंरगाहों पर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में आयातित थर्मल कोल की आवक 877.4 लाख टन थी। कोकिंग कोयले और अन्य कोयले का आयात इस दौरान पिछले वित्त वर्ष के 465.7 लाख टन की तुलना में 1.10 प्रतिशत बढ़कर इस वित्त वर्ष में 470.8 लाख टन पर पहुंच गया। *भाषा*

अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा खाद्य तेल-तिलहन बाजार

देश में खाद्य तेल-तिलहन बाजार इन दिनों अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। खाद्य तेलों की कमी और आयात पर भारी निर्भरता के बावजूद इस समय स्थानीय तेल तिलहन बाजार टूटा हुआ है, जबकि कुछ महीने से विदेशों में भाव ऊंचे चल रहे थे। इस स्थिति से आयातक और कारोबारी उलझन में हैं। उनका कहना है कि स्थानीय वायदा कारोबार में तेल तिलहन के भाव टूटे हुए हैं। उद्योग का कहना है कि सरकार को तुरंत स्थति का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह स्थति घरेलू तिलहन किसानों के हित में भी नहीं है। तेल उद्योग के सूत्रों का कहना है कि तेल का घरेलू उत्पादन जरूरत से 70 प्रतिशत तक रहता है। इस कारण विदेशों से कच्चे पाम आयल और सोयाबीन तेल का भारी मात्रा में आयात किया जाता है।

पॉम तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश मलेशिया और इंडोनेशिया में तेल का भाव इस समय 650 डॉलर प्रति टन से ज्यादा बोला जा रहा है। भारत में आरबीडी पामोलिन की पहुंच लागत करीब 720 डॉलर प्रति टन के आसपास पड़ती है। रुपये के हिसाब से यह 8,100 रुपये प्रति क्विंटल तक पड़ता है, जबकि घरेलू बाजार में पामोलिन का भाव 7,500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। इस प्रकार आयातकों के लिए कारोबार में बने रहना संकट वाली स्थिति बन गई है। यही हाल सोयाबीन डीगम तेल का है। विदेशों में सोयाबीन डीगम का भाव 795 डॉलर प्रति टन तक है। आयात शुल्क और खर्चे के साथ भारतीय बंदरगाह पर यह 8,150 रुपये प्रति क्विंटल तक पड़ता है। जबकि घरेलू हाजिर बाजार में सोयाबीन डीगम 7,700 रुपये प्रति क्विंटल बोला जा रहा है। इसमें भी पांच रुपये तक का नुकसान आयातकों को हो रहा है।

नरमी

- खाद्य तेलों की कमी और आयात पर भारी निर्भरता के बावजूद तेल तिलहन बाजार में नरमी
- कुछ महीने से विदेशों में भाव चल रहा था अधिक

वहीं घरेलू वायदा बाजार में कच्चे पॉम तेल का फरवरी वायदा भाव 7,050 रुपये और मार्च का भाव 7,000 रुपये क्विंटल पर बोला जा रहा है, जबकि विदेशों से भारतीय बंदरगाह पर कच्चा पॉम तेल आयात 7,420 रुपये तक पड़ता है। आयातकों को यहां भी मौजूदा भाव पर पांच रुपये का नुकसान है। बाजार जानकारों का कहना है कि सरकार ने 11 लाख टन पामोलिन आयात के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। हालांकि देश में आयात व्यवहारिक नहीं है। इसके बावजूद आयात लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। कारोबारी सवाल करते हैं कि भारी अंतर के बावजूद यह आयात कौन कर रहा है। उनका कहना है कि बैंकों को भी इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

जानकारों का कहना है कि एक तरफ सरकार घरेलू स्तर पर तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हर साल सरसों, मूंगफली और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाती है लेकिन दूसरी तरफ सट्टा बाजार में इन तिलहनों के भाव लगातार टूटते जा रहे हैं। इसमें सरसों की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। *भाषा*

पूर्वी भारत जा रहीं सीमेंट कंपनियां

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 23 फरवरी

विशेष रूप से आवासीय निर्माण और बुनियादी ढांचा खंड की मांग में तेजी आने से सीमेंट कंपनियों की पूर्वी भारत में नई और पुरानी परियोजनाओं को काफी विस्तार मिल रहा है। हाल के दिनों में उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत में तीन से पांच प्रतिशत के साथ मांग में नरमी रही है और दक्षिण भारत में बिक्री वृद्धि में करीब पांच प्रतिशत तक की गिरावट आई है। हालांकि देश के पूर्वी हिस्से में मांग लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ गई जिससे कीमतों में इजाफा हुआ है।

बिड़ला कॉरपोरेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी संदीप घोष के अनुसार पूर्वी क्षेत्र सीमेंट कंपनियों के लिए अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है क्योंकि वहां कच्चे घर (मिट्टी के घरों) छोड़कर पक्के घरों का निर्माण करने वाले लोगों की काफी संभावना है।

उद्योग के अधिकारियों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 50 प्रतिशत आवासों का निर्माण पूर्वी क्षेत्र में किया जा रहा है। कारोबारियों के अनुमान से पता चलता है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मांग 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ी है और ओडिशा में मांग में आठ से 10 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। इस मांग वृद्धि को लपकने के लिए सीमेंट कंपनियों में होड़ लगी है।येस सिक्योरिटीज के विश्लेषक कुणाल शाह ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में मांग मुख्य रूप से निजी आवासीय बिल्डरों और कुछ हद तक बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। अगल दो सालों में इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 1.7 करोड़ टन की नई क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में डालमिया भारत पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 22 लाख टन सालाना क्षमता की दो इकाइयां शुरू कर सकती है, जबकि बिहार में वर्ष 2021-2022 के दौरान इसकी 25 लाख टन सालाना क्षमता वाली इकाई शुरू होने वाली है।

श्री सीमेंट को उम्मीद है कि वह ओडिशा में अपनी 30 लाख टन सालाना क्षमता वाली इकाई शुरू करेगी, जबकि रामको सीमेंट ओडिशा में भी अपनी 10 लाख टन सालाना क्षमता तैयार कर रही है। इसके अलावा एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सागर सीमेंट्स और नुवोको विस्टा भी ग्राइंडिंग क्षमता में इजाफा कर रही हैं। इससे वर्ष 2022 तक पूर्वी क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता बढ़कर करीब 10.5 करोड़ टन हो जाएगी। दूसरी तरफ अधिग्रहण भी बाजार में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसके बाद बाजार में कुछ ही कंपनियों का वर्चस्व होगा। हाल ही में नुवोको विस्टा द्वारा इमामी सीमेंट का अधिग्रहण किए जाने के बाद यह इस क्षेत्र में श्री सीमेंट को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट विनिर्माता बन गई है।

बाजार के इस बदले हुए परिदृश्य के तहत पूर्वी क्षेत्र की कुल 9.2 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता में छह बड़ी कंपनियों - डालमिया भारत, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, नुवोको, एसीसी और अंबुजा सीमेंट का योगदान 80 प्रतिशत से अधिक है। 19 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ डालमिया भारत सबसे आगे है।

संक्षेप में

खदानों की नीलामी के पहले हो पर्यावरण मंजूरी

टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और अदाणी पावर जैसी प्रमुख कंपनियों ने सरकार से वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए प्रस्तावित ब्लॉको को नीलामी से पहले ही पर्यावरण मंजूरी देना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ताकि इन खदानों में खनन के दौरान संरक्षित क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठे। संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अहम होते हैं। इन इलाकों में से पारिस्थितिकी के लिए महत्त्व रखने वाले कई तरह के तरह तरह के जीव-जंतु, पेड़-पौधे और वनस्पतियां इत्यादि होते हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने वाणिज्यिक कोयला खनन की प्रक्रिया को लेकर हितधारकों के साथ एक बैठक हुई। इसमें बैठक में शामिल अधिकतर प्रतिनिधियों ने कहा कि इन खानों के लिए संबंधित पर्यावरण मंजूरियां पहले से होनी चाहिए ताकि खनन के लिए इन पर काम शुरू करने के बाद सुरक्षा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि जैसे मुद्दे न उभरें। *भाषा*

लॉटरी पर 1 मार्च से 28 प्रतिशत जीएसटी

लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था। राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया। इसके अनुसार, लॉटरी की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गई है और राज्य सरकारें भी इतना ही कर वसूलेंगी। *भाषा*

फास्टैग लेन में घुसने वालों पर 20 करोड़ रु जुर्माना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि उसने टोल प्लाजा पर फास्टैग वाले लेन में घुसने वाले बिना टैग के 18 लाख वाहनों से 20 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली के लिए फास्टैग की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने तब कहा था कि यदि कोई वाहन बिना टैग के समर्पित लेन में घुसता है तो उससे दो गुना टोल वसूल किया जाएगा। *भाषा*

कराची से अफगानिस्तान के लिए मालगाड़ी शुरु

पाकिस्तान रेलवे ने कराची से अफगानिस्तान में कंधार के लिए मालगाड़ी सेवाएं शुरू की है। यह कराची से अफगानिस्तान के लिए पहली मालगाड़ी सेवा है जिसमें माल पाकिस्तान के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन से ट्रकों के जरिए अफगानिस्तान में पहुंचाया जाएगा। पहली ट्रेन कराची के पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल से 35 कंटेनरों के साथ रवाना हुई। यह ट्रेन अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी शहर चमन तक जाएगी। *भाषा*

बड़े पैमाने पर बॉन्ड लाने की तैयारी

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 23 फरवरी

सरकार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में बड़े पैमाने पर विशेष श्रेणी के सरकारी बॉन्ड बाजार में जारी करने की योजना बना रही है। ये बॉन्ड करीब 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के होंगे। इसके बाद कई और हिस्सों में ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बॉन्ड वित्त वर्ष 2020-21 के उधारी लक्ष्य 8.1 लाख करोड़ रुपये के 10 प्रतिशत से अधिक (80,000 करोड़ रुपये) मूल्य के होंगे। वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने के बाद यह उल्लेखनीय मात्रा होगी।

एक शीर्ष अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'वित्त मंत्रालय का विचार यह है कि एक साल के दौरान कुल उधारी जरूरतों में स्पेशल सिरीज बॉन्ड की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से ज्यादा हो सकती है। सरकार के साथ सलाह के बाद रिजर्व बैंक पहले बड़े चक्र और उसके बाद की पेशकश के बारे में फैसला करेगा।'

मार्च के अंत तक पहले चक्र व उसके बाद की पेशकश के बारे में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक फैसला कर लेंगे, जिसकी घोषणा अप्रैल-सितंबर उधारी कैलेंडर के लिए होगी।

बजट में वित्त मंत्री ने की थी इसकी घोषणा

- वित्त वर्ष 21 के सकल उधारी लक्ष्य का 10 प्रतिशत होगा 11 अरब डॉलर के करीब
- विशेष श्रृंखला के बॉन्ड वित्त वर्ष 21 के उधारी के लक्ष्य का 10 प्रतिशत या इससे ज्यादा के हो सकते हैं
- केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मार्च के अंत तक जारी करेंगे विस्तृत ब्योरा
- आगामी सप्ताहों में सरकार मार्केट मेकर्स से करेगी बात
- केंद्र, रिजर्व बैंक की बड़े पैमाने पर बॉन्ड की पहली किस्त लाने की योजना

जैसा कि पहले खबर दी गई थी, केंद्र सरकार जी-सेक की विशेष श्रृंखला जारी करेगी, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए कोई सीमा नहीं होगी। यह वैश्विक बॉन्ड सूचकांक में शामिल भारतीय जी-सेक लेने का पहला मौका होगा, जिसके माध्यम से विदेशी पूंजी आकर्षित होगी। जी-सैक में एफपीआई सीमा 6 प्रतिशत है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के केंद्रीय बजट में इस योजना की रूपरेखा पेश की थी। सीतारमण ने कहा था, 'सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ चिह्नित श्रेणी को पूरी तरह से प्रवासी निवेशकों के लिए खोला जाएगा, जो घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होगा।' ब्लूमबर्ग बार्कलेज ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स, एफटीएसई रसेल एशिया पैसिफिक गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट और अनन्य सहित वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों की सभी शर्तें अगर पूरी की जाती हैं तो भारतीय जी-सैक आकर्षक हो सकता है। इससे संबंधित बातचीत में शामिल दूसरे अधिकारी ने कहा, 'इन सूचकांगों में मात्रा व आकार को लेकर शर्तें होती हैं. उदाहरण के लिए हर इश्यू कम से कम 40 करोड़ डॉलर का होना चाहिए और बॉन्डों की कुल मात्रा कम से कम 5 अरब होनी चाहिए। हमारे लिए यह आसानी से किए जाने योग्य है।' वित्त वर्ष 21 के कुल उधारी लक्ष्य का 10 प्रतिशत मोटे तौर पर 11 अरब डॉलर होता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने रिजर्व बैंक और वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों के प्रशासकों के साथ कई बैठकें की हैं। दूसरे अधिकारी ने कहा कि आने वाले सप्ताहों में निवेश बैंकों के साथ बैठक होगी, जो पोटेंशियल मार्केट मेकर्स के रूप में काम कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों व बॉन्ड बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों का हिस्सा होने से भारतीय जी-सेक को बड़े पैमाने पर पेंशन फंडों सहित प्रमुख वैश्विक निवेशकों से धन जुटाने में मदद मिलेगी।

दूरसंचार क्षेत्र को राहत देने के लिए मंथन

भाषा
नई दिल्ली, 23 फरवरी

दूरसंचार विभाग और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की रविवार को बैठक हुई। यह बैठक कंपनियों पर सांविधिक बकायों मामले से परेशान दूरसंचार उद्योग को राहत देने के उपायों पर चर्चा के लिए हुई। दूरसंचार उद्योग बड़े पैमाने पर सांविधिक बकाए के कारण अप्रत्यशित संकट से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है।

अधिकारियों की बैठक

यह बैठक दूरसंचार विभाग में हुई और करीब एक घंटे चली। ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में सरकार के समक्ष उपलब्ध उन विकल्पों पर विचार किया गया जो समायोजित सकल आय के बकाए से प्रभावित उद्योग को उपलब्ध करया जा सकता है।

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने पिछले सप्ताह सरकार से शुल्क और करों में छूट देने की अपील की ताकि अप्रत्याशित संकट से क्षेत्र को उबारा जा सके। रविवार को हुई बैठक के बारे में अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। दूरसंचार विभाग के सचिव अंशु प्रकाश से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है।

यह बैठक ऐसे समय हुई है जब दूरसंचार कंपनियां 1.47 लाख करोड़ रुपये के सांविधिक बकाया लौटाने से जूझ रहे हैं। इसमें 92,642 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में तथा 55,054 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में बकाया है। इस बकाए में ब्याज ओर जुर्माना शामिल हैं। कुल बकाए में करीब 60 प्रतिशत एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया इन दो कंपनियों पर बकाया है। सरकार एजीआर के बकाया मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के साथ क्षेत्र की सेहत तथा ग्राहकों के हितों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है।

अकेले महंगाई नहीं रोक सकता रिजर्व बैंक : रंगराजन

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा है कि आरबीआई अकेले महंगाई दर को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि आपूर्ति मामलों को सरकार द्वारा प्रबंधित करने की जरूरत है। नई मौद्रिक नीति रूपरेखा-इसका मतलब शीर्षक से जारी एक पत्र में रंगराजन ने आरबीआई की महंगाई को काबू में रखने की सीमाओं के बारे में चर्चा की है।

उन्होंने कहा, 'मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य दिया गया है, उसका एक एक दायरा होना चाहिए और उसके समायोजन को लेकर समय सीमा होनी चाहिए तथा यह बहुत अल्प अवधि का नहीं होना चाहिए।' रंगराजन ने कहा, 'इन सबके बावजूद मौद्रिक नीति को

उन बातों पर ध्यान दिए बिना काम करना चाहिए जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाले हों। स्पष्ट तौर पर आपूर्ति संबंधी मसले में आपूर्ति प्रबंधन की जरूरत होती है और यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।'

उन्होंने कहा कि देश में मुद्रास्फीति लक्ष्य को जो विचार अपनाया गया है, उससे कई संदेह और चिंताएं बढ़ी हैं। नई मौद्रिक नीति रूपरेखा के तहत रिर्जव बैंक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता है।

रंगराजन ने कहा, 'इस प्रकार एक तरह से यह लचीला लक्ष्य है। आरबीआई कानून में संशोधन कर मौद्रिक नीति समिति के गठन की व्यवस्था की गई जो मुद्रास्फीति लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दर का निर्धारण करेगी।' *भाषा*

पीएमओ ने बैंकों से मांगा विलय के बाद का अनुमान

सोमेश झा
नई दिल्ली, 23 फरवरी

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 10 सरकारी बैंकों के प्रस्तावित विलय के फायदों को लेकर कुछ अहम ब्योरों की मांग की है, जबकि बैंक सरकार से जरूरी मंजूरियों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

योजना के मुताबिक प्रमुख बैंक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक को 6 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसयू) का अधिग्रहण करना है। इन प्रमुख बैंकों से कहा गया है कि वे अगले 3 से 5 साल के वित्तीय अनुमान का काम पूरा करके वित्तीय सेवा विभाग को सौंपे।

एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा कि सरकार ने बैंकों से कहा है कि पूंजी और बॉन्ड बाजारों से धन जुटाने की अपनी योजनाओं की जानकारी दें। अधिकारी ने कहा, 'प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैंकों से शाखाएं व एटीएम बंद करने की योजना और विलय की प्रक्रिया के बाद अगले तीन साल में होने वाली बचत के बारे में जानकारी मांगी है।'

बैंकों से कहा गया है कि वे विलय प्रक्रिया के बाद कॉर्पोरेट, एमएसएमई, कृषि और खुदरा क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज के अनुमान के आंकड़े तैयार रखें। इसके अलावा पिछले 2 साल के क्षेत्रवार कर्ज के आंकड़े तैयार करें। इसके साथ ही बैंकों को अपने तकनीकी और तकनीकी एकता का खाका सौंपना होगा। एक और सरकारी बैंक के अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'प्रमुख बैंकों से एकीकरण प्रक्रिया के लाभों की जानकारी मांगी गई है।'

पिछले हफ्ते बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर दी थी कि केंद्र सरकार सरकारी बैंकों के विलय की राह पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है, जबकि इन बैंकों की बैलेंस सीट विलय की तय तिथि 1 अप्रैल है और अब बहुत कम वक्त बचा है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सरकारी बैंकों के विलय पर अंतिम फैसला करने केपहले बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) के विलय के परिणामों को देखना चाहते हैं। वित्त मंत्रालय जल्द ही अंतिम फैसले के पहले प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति दे सकता है।

उपरोक्त उल्लिखित एक बैंक अधिकारी ने कहा, 'इन बैंकों को मिलाए जाने की प्रक्रिया का तात्कालिक लाभ लागत को तार्किक बनाना बताया गया है, जो इसका अहम पहलू है। लेकिन हम सरकारी बैंक हैं ऐसे में कर्मचारी घटाने के लिए तत्काल शाखाओं को बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने सरकार से इस कवायद के दीर्घकालिक लाभों के बारे में बताया है।'

मांगी गईं ये जानकारियां

- हर साल के वित्तीय अनुमान, जमा, कर्ज, पूंजी पर्याप्तता, मुनाफा और एनपीए को लेकर अगले 3-5 साल का अनुमान
- विलय के बाद से 3 साल में बैंकों की सालाना बचत
- शाखाएं व एटीएम बंद करने को लेकर योजना
- इक्विटी और बॉन्ड बाजारों के माध्यम से पूंजी जुटाने की योजना
- पिछले 2 साल में दिए गए सेक्टर वार कर्ज के आंकड़े

बैंकों द्वारा विलय का एक लाभ यह बताया गया है कि उनकी पूंजी का आधार ज्यादा हो जाएगा, जिससे उन्हें बड़े कर्ज देने में सहूलियत होगी।

बैंक आफ बड़ौदा के हाल के वित्तीय परिणाम से सरकार की चिंता बढ़ी है, जिसने 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का अधिग्रहण कर लिया था। बैंक को तीसरी तिमाही में 1,407 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ है, जो मुख्य रूप से ज्यादा प्रावधान की वजह से है। बैंक की ताजा चूक बढ़कर करीब 10,387 करोड़ रुपये हो गई है, यह अच्छे से खराब कर्ज में बदल गई राशि है।

दिसंबर अंत की तिमाही में कर्ज की वृद्धि का अनुमान 10 प्रतिशत की तुलना में स्थिर रहा। विलय योजना से जुड़ी सरकार की अधिसूचना में देरी हो रही है, जो बैंकों के बोर्डों की चिंता बढ़ा रही है। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 तक विलय प्रक्रिया पूरी होने की संभावना थी।

बहरहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें देरी की कोई वजह नजर नहीं आती। शनिवार को वित्त मंत्री ने कहा था, 'जब फैसला हो जाएगा तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी।' सीतारमण ने पिछले साल 30 अप्रैल को 10 बैंकों के इस बड़े विलय की घोषणा की थी।

राजस्व में कमी से वित्त वर्ष 20 में घटा बुनियादी ढांचे पर खर्च, सामाजिक व्यय रहेगा कम

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 23 फरवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए वृद्धि को गति देने के लिए ज्यादा खर्च करने व राजस्व में आई गिरावट की वजह से खर्च की सीमाओं के बीच संतुलन बनाने की कवायद की। खर्च का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखे जाने के बावजूद मंदी के कारण राजस्व कम होने से कुछ अहम योजनाओं की वृद्धि सुस्त रह सकती है या उनका वित्तपोषण घट सकता है।

कुछ योजनाओं को अतिरिक्त कोष के हिसाब से राहत मिली है, हालांकि वह बजट या संचति निधि से नहीं मुहैया कराया जाएगा, बल्कि उनके लिए बॉन्ड से धन जुटाया जाएगा और सरकार आगामी वर्षों में मूलधन और ब्याज का भुगतान करेगी।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने 22 प्रमुख योजनाओं पर व्यय व आवंटन का विश्लेषण किया है, जिनमें किसानों की आमदनी का समर्थन से लेकर स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा से लेकर महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों को वित्तीय सहायता तक शामिल हैं। इससे पता चलता है कि ग्रामीण सड़कों, शहरी विकास, स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन, कौशल विकास की परियोजनाएं वित्त वर्ष 2020 में प्रभावित होंगी। वहीं ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता सहायता के फंड में वित्त वर्ष 21 के दौरान स्थिरता रहने की संभावना है। साथ ही कुल मिलाकर साथ रखी गई 22 अहम योजनाओं के आवंटन में 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो सकल कर राजस्व में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में ज्यादा है।

विश्लेषणों से पता चलता है कि 7 योजनाओं में 40 प्रतिशत धन बजट से इतर साधनों से मुहैया कराया जाएगा, जिससे आगामी वर्षों में ब्याज की राशि बढ़ेगी। बजट से इतर उधारी 7 योजनाओं में ज्यादा बढ़ी है। और आखिरकार सरकार ने इस साल की विशेष जरूरतों में थोड़ा बदलाव किया है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में सेवानिवृत्ति योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। बहरहाल बजट में वित्त वर्ष 21 के लिए 13,185 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020 में 530 करोड़ रुपये दिए गए थे।

प्रमुख योजनाओं में सबसे घाटे में स्मार्ट सिटी मिशन रहा। वित्त वर्ष 20 में इसका संशोधित व्यय पहले के वर्ष 19 की तुलना में 20 प्रतिशत कम रहा। इसी तरह से ग्रामीण सड़कों की स्थिति देखें तो वित्त वर्ष 2020 में इस पर आवंटन 15,414 करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत घटकर 14,070 करोड़ रुपये रह गया है।

कौशल विकास प्रमुख योजना है, जिसके तहत अनौपचारिक कामगारों को संगठित उद्योगों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। इस पर वित्त वर्ष 20 में पहले के साल की तुलना में बजट में 3 प्रतिशत कटौती कर आवंटन 2,619 करोड़ रुपये से घटाकर 2,531 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 21 में मनरेगा का आवंटन 71,000 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत घटकर 61,500 करोड़ रुपये हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसमें वित्त वर्ष 21 में सुधार होगा। उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्रालय सामान्यतया जब मनरेगा का सवाल आता है ति दूसरी छमाही के दौरान अनुदान के लिए पूरक मांग स्वीकार कर लेता है।' इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा और बच्चों के स्वास्थ्य, विभिन्न बीमारियों से बचाने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना का व्यय भी वित्त वर्ष 21 में 33,000 करोड़ रुपये पर स्थिर बना हुआ है।

बजट के आंकड़ों का विश्लेषण

व्यय के लिए उधारी पर बढ़ी निर्भरता, ग्रामीण स्वच्छता और बिजली आपूर्ति योजनाओं को मिला कम धन, मनरेगा के हिस्से भी आई कम राशि

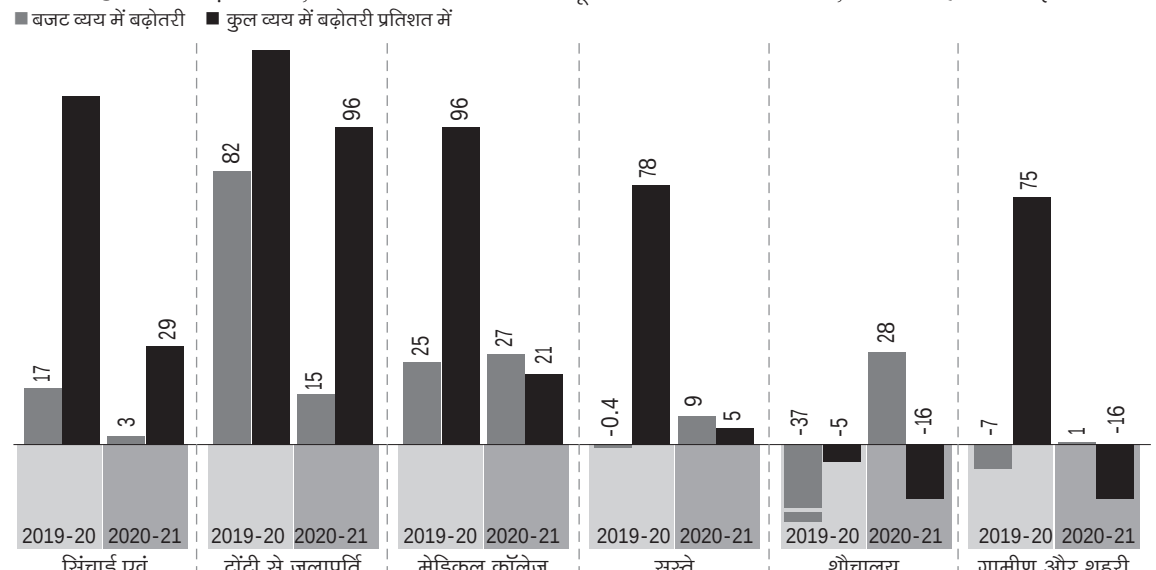

नोटः वित्त वर्ष 2019-20 के सभी आंकड़े संशोधित अनुमान हैं, वित्त वर्ष 202-21 के आंकड़े बजट अनुमान हैं

स्रोतः केंद्रीय बजट

स्ट्रीमिंग पर कुछ सेंसरशिप का समर्थन करते हैं भारतीय

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 23 फरवरी

ऑनलाइन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सेंसरसिप पर चल रही बहस के बीच एक ताजा सर्वे में पाया गया है कि प्रतिक्रिया देने वाले ज्यादातर भारतीय इस तरह के शो और मूवी पर कुछ सेंसरशिप या निगरानी को इच्छुक हैं।

भारत में मौजूद ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के बारे में नागरिकों की धारणा की जांच के लिए कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकलसर्किल की ओर ओर से कराए गए सर्वे में देश भर के 40,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया ली गई।

नया सर्वे

- 63 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स एमेजॉन, हॉटस्टार जैसे ओटीटी की हो निगरानी
- सर्वे में शामिल 51 प्रतिशत लोग ओटीटी का इस्तेमाल नहीं करते

इससे एक निष्कर्ष यह निकलकर आया है कि प्रतिक्रिया देने वाले 63 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, जी5 और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर सरकार की आचार संहिता से जुड़े कुछ सेंसरशिप नियम लागू होने चाहिए, जबकि 32 प्रतिशत लोग इस बात से असहमत थे।

बहरहाल सर्वे में शामिल 51 प्रतिशत लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब तक मूवी या शो नहीं देखते।

सर्वे में यह भी पाया गया कि प्रतिक्रिया देने वाले 42 प्रतिशत लोगों ने सिर्फ एक ओटीपी प्लेटफॉर्म का सबस्क्रिप्शन लिया है, जबकि 25 प्रतिशत ने 2 ओटीटी प्लेटफॉर्मों का सबस्क्रिप्शन लिया है। वहीं 33 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके पास 3 या इससे ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्मों जैसे नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम हॉटस्टार आदि का सबस्क्रिप्शन है।

प्रतिक्रिया देने वाले 53 प्रतिशत लोगों ने सबस्क्रिप्शन लेने की वजह यह बताई कि इससे वे अपनी सुविधा के मुताबिक कार्यक्रम देख सकते हैं, जबकि 9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसका कंटेंट उच्च गुणवत्ता का होता है। वहीं 9 प्रतिशत ने कहा कि वे गैर सेंसर वाले कंटेंट पसंद करते हैं, जबकि 11 प्रतिशत ने कहा कि इसकी लागत अन्य की तुलना में कम है। करीब 18 प्रतिशत लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी।

इस महीने की शुरुआत में इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया ने डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (डीसीसीसीसी) की शुरुआत की थी, जहां ग्राहक स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन कंटेंट की कोई भी शिकायत कर सकते हैं और समय से उनका समाधान पा सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 7

टाले जाएं डेटा सर्वेक्षण

भारत विभिन्न स्तरों पर डेटा गुणवत्ता की समस्या का सामना करता है और इन आंकड़ों के अक्सर देर से आने से समुचित नीतिगत कदम उठाने में विलंब होता है। विश्वसनीय आर्थिक सांख्यिकी की समस्या अब अधिक गंभीर होने की आशंका है। अभी तक यह समस्या महज सरकार की स्वीकृति और सर्वे के परिणाम जारी करने तक ही सीमित थी लेकिन अब यह वहां तक पहुंच चुकी है जहां खुद डेटा संग्रह ही एक समस्या बनती जा रही है। इस समाचारपत्र में पिछले हफ्ते प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण टालना पड़ सकता है क्योंकि लोग इन सर्वेक्षणों के दौरान सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें डर यह है कि सरकार इस जानकारी का इस्तेमाल नागरिकता-निर्धारण के लिए कर सकती है। नतीजतन, एक विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव देने का फैसला किया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा घरेलू पर्यटन व्यय एवं अन्य संकेतकों के सर्वेक्षण का काम टाल दिया जाए। निश्चित रूप से सरकार के पास यह विकल्प है कि वह यह सलाह न माने। लेकिन इससे दो बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहली, परिवारों की समुचित भागीदारी न होने से सर्वे की अपेक्षित गुणवत्ता नहीं रह जाएगी जिससे इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। दूसरी, यह उस जगह पर सर्वेक्षकों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है जहां आबादी का एक बड़ा तबका नागरिकता प्रावधानों को लेकर परेशान है। कई राज्यों में सर्वे करने गए फील्ड अफसरों पर हमले की घटनाएं देखी गई हैं। मसलन, पश्चिम बंगाल में आर्थिक जनगणना और समय-समय पर होने वाले श्रमिक बल सर्वेक्षण रोक दिए जाने की खबरें हैं। इससे भी बुरा यह है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति न केवल इस समय जारी सर्वेक्षणों को प्रभावित कर रही है बल्कि आगामी जनगणना को भी खतरे में डाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका निहितार्थ अधिक व्यापक होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली समेत अलग-अलग हिस्सों में अब भी जारी हैं।

कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा की है कि वे सीएए को लागू नहीं करेंगी और वे राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी को अद्यतन करने के भी पक्ष में नहीं हैं। लोगों के बीच अविश्वास बढ़ने और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच मतभेद से जनगणना की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रणव सेन ने गत दिनों इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि अगर जनगणना का काम सही ढंग से नहीं किया जाता है तो अगले 10 वर्षों तक होने वाले सारे घरेलू सर्वेक्षण भरोसेमंद नहीं रहेंगे क्योंकि ये जनगणना ढांचे पर ही आधारित रहे हैं। इस तरह डेटा की विश्वसनीयता पर आगे और भी सवाल उठेंगे। इससे न केवल नीति-निर्माण प्रभावित होगा बल्कि यह पहले से ही संदेह में घिरी सांख्यिकीय प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता को भी चोट पहुंचाएगा। मसलन, जीडीपी से जुड़े आंकड़े पर कई अर्थशास्त्री सवाल उठा चुके हैं। रोजगार संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन टालने और उपभोग सर्वेक्षण बंद करने के सरकार के फैसलों ने भी हालत कमजोर की है। हालांकि मौजूदा समस्या कहीं अधिक बड़ी है और अगर सरकार जरूरी कदम उठाती है तो वह बेहतर होगा।

डेटा सर्वेक्षणों को लेकर विश्वसनीयता पैदा करने का दायित्व केंद्र सरकार का है क्योंकि यह समस्या नागरिकता कानून में बदलावों से शुरू हुई है। भारत एक खंडित सांख्यिकीय प्रणाली के साथ आगे बढ़ने की हालत में नहीं होगा। अगर असमंजस को जल्द दूर नहीं किया जाता है तो भारत की भी गिनती उन देशों में होने लगेगी जो अपनी आर्थिक स्थिति को वास्तविकता से बेहतर दिखाने के लिए आंकड़ों में फेरबदल करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारी सांख्यिकीय प्रणाली में बड़ी समस्याएं हैं और उन्हें दूर करने की जरूरत है। सरकार के लिए यह वक्त नीति को राजनीति के ऊपर रखने का है।

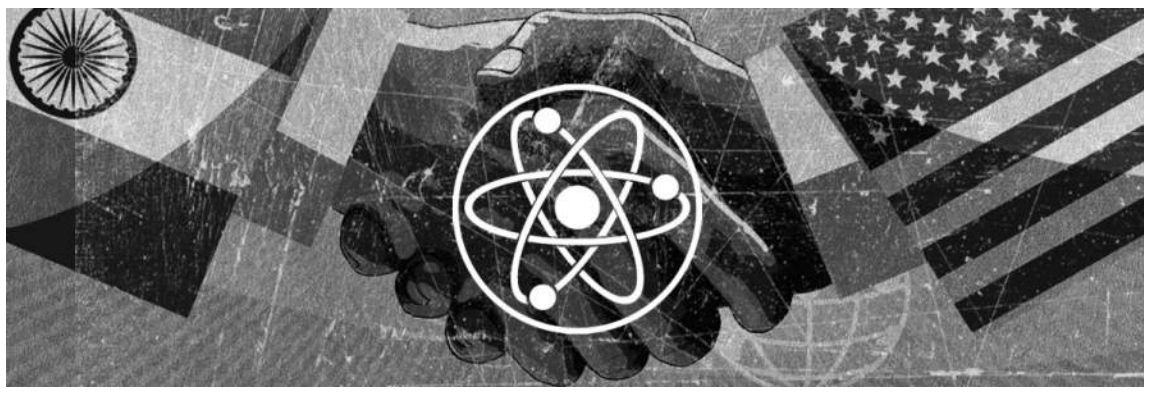

अजय मोहंती

एक बड़ा समझौता छह बड़े लाभ

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता वह सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने दोनों देशों के रिश्तों को बदल दिया।

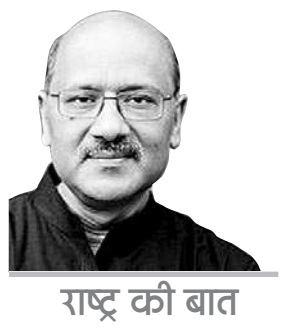

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

आजादी के बाद के शुरुआती 53 वर्ष में केवल तीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए: ड्वाइट आइजनहावर (1959), रिचर्ड निक्सन (1969) और जिमी कॉर्टर (1978)। सोमवार को भारत पहुंच रहे डॉनल्ड ट्रंप बीते 20 वर्ष में भारत की यात्रा पर आने वाले पांचवें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। दो बड़े देश जो आधी सदी तक सामरिक दृष्टि से विपरीत मोड़ पर रहे वे अब उस गंवाए समय की भरपाई कर रहे हैं।

यह संयोग ही है कि शीतयुद्ध का समापन और सोवियत संघ का विभाजन लगभग उस समय हुआ जब नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक सुधारों तथा भारत में आर्थिक वृद्धि के 25 वर्ष के चरण की शुरुआत की। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच नए रिश्तों की शुरुआत स्वाभाविक थी। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि रिश्तों में बदलाव से जुड़े एक तथ्य या एक उपलब्धि की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे?

मैं कहूंगा कि यह था भारत-अमेरिका परमाणु समझौता। मुझे पता है कि इसे लेकर दो अतिरंजित प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलेंगी। पहली प्रतिक्रिया, इसमें बड़ी बात क्या है, यह तो सबको पता है। दूसरी ओर ऐसा भी कहा जाएगा कि तब से अब तक एक मेगावॉट की परमाणु बिजली क्षमता भी शामिल तैयार नहीं हुई है और अमेरिकी रिएक्टर अगले 15 वर्ष तक कोई बिजली नहीं उत्पन्न करने वाले। यह सोचना कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौता द्विपक्षीय रिश्तों से संबंधित है या इसका संबंध केवल बिजली से है, गलत होगा। मनमोहन सिंह को इस संधि को अंजाम देने में जितनी कठिनाई हुई उससे पता चलता है कि यह कितना जटिल था और इसके कितने व्यापक निहितार्थ थे। आइए ऐसे छह बिंदुओं के बारे में बात करते हैं:

■ इस समझौते की पहली और सबसे बड़ी वजह वैचारिक थी। यह पहला मौका था जब भारत ने अमेरिका के साथ किसी ऐसी द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके गहरे सामरिक निहितार्थ थे। इससे न केवल शीतयुद्ध के बाद के भारत में 180 डिग्री का बदलाव आया बल्कि एक बड़े सार्वजनिक प्रश्न की परीक्षा भी हुई कि क्या दशकों की आशंका के बाद हम अमेरिकियों को मित्र मान सकते हैं?

इस सीमा तक तो यह उस वैचारिक राष्ट्रवाद के खिलाफ था जो कांग्रेस और वाम बौद्धिकों ने चतुराईपूर्वक तैयार किया था। यही कारण है कि वाम दलों के साथ-साथ तकरीबन समूची कांग्रेस इसके खिलाफ थी। इसके अलावा मुस्लिमों की नाराजगी जैसी मूर्खतापूर्ण बातें तो हो ही रही थीं।

चूंकि मनमोहन सिंह इसे प्रधानमंत्री के अपने कार्यकाल की उपलब्धि बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपनी सावधानीपूर्वक संजोई राजनीतिक पूंजी भी दांव पर लगा दी। उन्होंने अनिच्छुक सोनिया गांधी को इस पर सहमत किया भले ही पुराने सिपहसालार अनिच्छुक थे।

इसके बाद 2009 में हुए आम चुनाव ने साबित किया कि भारतीय मतदाता समझदार हैं और भारत के राष्ट्रीय हितों को बेहतर समझते हैं। वे पुराने वाम और दक्षिणपंथी धड़े से अधिक ईमानदार भी हैं। भाजपा जिसे पश्चिम समर्थक माना जाता रहा उसने इस संधि का और अधिक विरोध किया। वाम का विरोध सैद्धांतिक और दक्षिण का राष्ट्रवादी आधार पर था।

दोनों की हार हुई। संप्रग पहले से बेहतर सीटों के साथ सत्ता में आई और अमेरिका विरोध का वैचारिक भूत इतने गहरे दफन हुआ कि फिर नहीं उभरा। शीतयुद्ध के बाद के भारत का उदय हो चुका था।

■ दूसरा लाभ सामरिक सिद्धांत से जुड़ा था। हालांकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने हाल ही में मुझसे बातचीत के दौरान इसे शीर्ष पर रखा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह इस बात को लेकर गहरे तक चिंतित थे कि भारत को परमाणु भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि परमाणु हथियार क्षमता संपन्न होने के बावजूद उसे परमाणु कारोबार और तकनीकी हस्तांतरण व्यवस्था में शामिल होने लायक नहीं समझा जाता था। यह भेदभावकारी व्यवस्था भेदभाव वाली अप्रसार संधि से उपजी थी।

परमाणु संधि ने भारत को इसे तोड़ने का अवसर दिया। वह दौर इस लिहाज से भी बेहतर था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति के बीच रिश्ते अच्छे थे और वह उन्हें भारत के साथ सहजता के लिए प्रेरित कर सकते थे। भारत को अब परमाणु हथियार शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है बल्कि पाकिस्तान के उलट उसे एक जवाबदेह अप्रसार वाला देश माना जाता है।

■ तीसरा लाभ घरेलू महत्ता का है। अब तक भारत पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी कि वह खुद को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उपायों और पारदर्शिता मानकों का विषय बनाए। क्योंकि असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रम एक दूसरे में घालमेल वाले थे। ऐसा जानबूझकर था ताकि वे एक दूसरे का आवरण बने रहें। पारदर्शिता और निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें संसद भी शामिल थी।

इसके साथ ही चूंकि सैन्य और असैन्य कार्यक्रम मिलेजुले थे इसलिए देश की प्रयोगशालाओं के परमाणु वैज्ञानिक खुलकर काम नहीं कर पाते। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समकक्षों की समीक्षा का माहौल भी नहीं मिल पाता था। हर चीज को संदेह की नजर से देखा जाता था। ऐसे में परमाणु समझौते का एक बड़ा फायदा यह था कि देश का परमाणु कार्यक्रम, उसकी फंडिंग और उसका प्रदर्शन सब पारदर्शिता के दायरे में आ गए। इससे ज्यादा जवाबदेह और सुरक्षित कामकाज को बढ़ावा मिला।

■ अगला लाभ सामरिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में हासिल हुआ। इसे असैन्य समझौता कहा गया लेकिन हकीकत में यह गहरी सैन्य और सामरिक संधि थी। इससे अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान की पुरानी आशंका तेजी से कम हुई और भारत को संवेदनशील सैन्य तकनीक और उपकरण मिलने की राह आसान हुई।

सन 1980 के दशक के मध्य में भारत और अमेरिका के बीच इतना भी भरोसा नहीं था कि वह मॉनसून की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत को सुपर कंप्यूटर बेचे। ऐसा तब था जबकि राजीव गांधी और रोनाल्ड रीगन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। अब सर्वाधिक संवेदनशील सैन्य तकनीक, डेटा और खुफिया जानकारी साझा होने लगी है। इस सौदे ने जिसने दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद बदल दी, उसके बिना यह संभव नहीं था।

■ पांचवां लाभ क्षेत्रीय भू राजनीति से संबंधित है। शीतयुद्ध के समापन के बाद 15 वर्ष तक भारत के साथ अपनी नीति को पाकिस्तान से अलग करने की दिशा में बढ़ता रहा। परमाणु समझौते के बाद इसमें नाटकीय बदलाव आया।

पहली बार अमेरिका ने भारत के साथ ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसकी पेशकश उसने पाकिस्तान से नहीं की थी। यदि आप इसे पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पर तौलने के अंत के रूप में नहीं देखते तो किसी पाकिस्तानी रणनीतिकार से बात कीजिए। इस संधि के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को वापस साथ लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। केवल हम, खासतौर पर मोदी सरकार के अधीन उस पुराने झांसे के बार-बार शिकार बन रहे हैं। हमारी आंतरिक राजनीति में पाकिस्तान गैर जरूरी रूप से महत्त्वपूर्ण हो गया है।

■ छठा और अंतिम लाभ वह है जिसे मैं डरते-डरते अपना पसंदीदा कह रहा हूं। यह लाभ हमारी घरेलू राजनीति में अत्यधिक महत्त्व रखता है। परमाणु संधि ने और जिस तरह हमारे राजनीतिक वाम ने इसका विरोध किया और मुंह की खाई उसने हमारी राजनीतिक अर्थनीति के एक अभिशाप को समाप्त किया जिसका नाम है वामपंथ। सन 2008 में उसके पास लोकसभा की 60 से अधिक सीट थीं लेकिन आज वह दो अंकों में पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहा है।

मनमोहन सिंह की सरकार गिराने के लिए वाम ने संसद में भाजपा से हाथ मिलाया लेकिन पराजित हुआ। इससे सच सामने आया। वाम का अंध अमेरिका विरोध और राजनीतिक हिंदुत्व से साथ मिलाना दोनों सामने आए। जल्दी ही पश्चिम बंगाल से भी उसका पत्ता हमेशा के लिए साफ हो गया।

यह लाभ पीढ़ियों तक संभालकर रखने लायक है। भले ही इसे हासिल करने में थोड़ा सा विदेशी हाथ (अमेरिकी) शामिल था।

मौजूदा माहौल में खत्म हो रहा अराजनीतिक कंपनी का दौर

जिंदगीनामा
कनिका दत्ता

मौजूदा दौर में भारतीय कॉर्पोरेट जगत की उस स्थापित परंपरा को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है जिसमें वह किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा से जुड़े विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। ये गतिविधियां मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा समाज की वैचारिक लामबंदी का ही नतीजा हैं। हाल की तीन घटनाएं दिखाती हैं कि गहन राजनीतिक उपदेशवाद की इस प्रक्रिया का उपभोक्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं के आपसी संबंधों पर असर डालने के अनचाहे नतीजे रहे हैं। इस वजह से उन्हें अपने वैचारिक रंग दिखाने (या न दिखाने) के लिए मजबूर होना पड़ा है।

पहली घटना पिछले साल अगस्त की है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के निवासी अमित शुक्ला ने ट्विटर पर बताया था कि फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो की तरफ से एक गैर-हिंदू शख्स को डिलिवरी के लिए भेजे जाने पर उसने ऑर्डर लेने से मना कर दिया था। जोमैटो ने इस ऑर्डर का रिफंड करने से मना करते हुए कहा था कि 'भोजन का कोई धर्म नहीं होता है, यह खुद एक धर्म है।' जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने इस कदम को राजनीतिक तौर पर सही संदेश के साथ उचित बताया था। गोयल ने भारत की विविधता का जिक्र करते हुए कहा था, 'अपने मूल्यों की राह में आने वाले किसी भी कारोबार को खोने का हमें अफसोस नहीं है।' इस चतुराई भरे बयान से गोयल ने इसे पसंद करने या नकारने का जिम्मा ग्राहकों पर ही छोड़ दिया था।

शायद जोमैटो खुशकिस्मत थी कि यह वाकया एक गैर-भाजपा शासित राज्य में हुआ था। पुलिस ने फौरन शुक्ला को 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने का फरमान जारी कर दिया। पुलिस ने कहा था कि शुक्ला का ट्वीट जबलपुर जैसे संवेदनशील शहर में शांति को बाधित कर सकता था।

लेकिन कैब सेवा कंपनी उबर को इस महीने की शुरुआत में मुंबई की पुलिस से ऐसा साथ नहीं मिला। उबर के एक ड्राइवर ने अपनी टैक्सी में बैठे एक सवारी की शिकायत पुलिस से सिर्फ इसलिए कर दी थी कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बातें कर रहा था। ड्राइवर ने अपनी सवारी की बातें रिकॉर्ड कर ली थीं और उसे 'राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों' में लिप्त बता रहा था। टैक्सी में बैठे सवारी की निजता का हनन करने वाले इस काम पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उस युवक को ही पूछताछ के लिए बिठा लिया और इस चेतावनी के साथ छोड़ा कि ऐसे 'खराब समय' में लाल स्कार्फ न पहने। इस घटना पर उबर की प्रतिक्रिया नरम रही। उसने दोषी ड्राइवर को 72 घंटों के लिए सेवा से निलंबित कर दिया और बाद में बहाल करते हुए उसे फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेज दिया। उबर के साथ जुड़ने पर हरेक ड्राइवर को अपने सवारियों के साथ बरताव के तौर-तरीके सिखाने के लिए इस क्लास में हिस्सा लेना जरूरी होता है।

उबर के इस कदम से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या उबर को यह बात आपत्तिजनक नहीं लगी कि एक सेवा-प्रदाता किसी ग्राहक की बातचीत उसकी अनुमति के बगैर कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? दूसरा, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या सिखाया जाता है? क्या एक यात्री की जासूसी न करना और अपने काम से मतलब रखना ड्राइवरों के बुनियादी प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है? अगर ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इस ड्राइवर ने पहली बार इस सबक को नहीं सीखा था। क्या इस बार ऐसा होने की संभावना है, वो भी ऐसे वक्त में जब स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक 'जागरूक नागरिक' होने के लिए उसका सम्मान किया हो? अगर यही घटना अमेरिका में हुई रहती तब भी क्या उबर की प्रतिक्रिया यही रहती? गत जनवरी में भी ओला का एक ड्राइवर फोन पर हो रही बातचीत में मोदी सरकार की आलोचना करने वाले ग्राहक से झगड़ बैठा था।

जब सवारी ने ओला से इसकी शिकायत की तो प्रबंधन ने इस पर 'सुधारात्मक कदम' उठाने की बात कही लेकिन 'भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान और विचारों के स्वस्थ आदान-प्रदान को प्रोत्साहन' का हवाला देते हुए आरोपी ड्राइवर को सेवा से नहीं हटाया। सच है कि यह घटना ड्राइवर को हटाने लायक नहीं थी और भारत में हरेक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार भी होना चाहिए। ओला ने वर्ष 2018 में बड़े गर्व से अपने प्लेटफॉर्म के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का जिक्र किया था जब एक हिंदू सवारी ने एक मुस्लिम ड्राइवर की कैब में जाने से मना कर दिया था।

इस बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा के मामले में निजी विमानन कंपनियों के रवैये से कई सवाल खड़े होते हैं। कामरा ने इंडिगो की एक उड़ान के दौरान भाजपा का यशोगान करने वाले चैनल के एक मशहूर ऐंकर से कई व्यंग्यपूर्ण सवाल किए थे। इसके बाद कामरा को छह महीने के लिए फौरन प्रतिबंधित कर दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री के एक ट्वीट ने दूसरी निजी एवं सार्वजनिक एयरलाइंस को भी ऐसा ही कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। एक निजी एयरलाइन और उसके यात्रियों के बीच के विवाद में एक राजनीतिक नेता का दखल समझ से परे है।

जल्द ही साफ हो गया कि कामरा पर पाबंदी लगाने वाली सभी एयरलाइंस हद से ज्यादा सख्ती बरतने की दोषी हैं। ऐसी हरकत पर अधिकतम तीन माह की ही पाबंदी लगाने का प्रावधान है। वैसे यह हरकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती है लेकिन उन्होंने विमान सेवा में बाधा नहीं डाली और न ही उड़ान में उनकी वजह से देर हुई जैसा कि कुछ नेता अभी हाल में कर चुके हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि उस विमान के पायलट ने कोई कदम उठाने के पहले सलाह नहीं लिए जाने पर नाखुशी जताई। उड्डयन महानिदेशालय ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि इस घटना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उसके बाद कामरा ने एयरलाइन पर 'मानसिक प्रताड़ना' का मुकदमा कर दिया है। ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि नीरस एवं अराजनीतिक कंपनी के दिन बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। उनके रुख से ही आने वाले दिनों में राजनीतिक एवं कारोबारी गतिशीलता तय होगी।

कानाफूसी

बढ़ती नजदीकी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी पिछले पूरे सप्ताह अपने राज्य और दिल्ली के बीच आवाजाही करते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विशाखापत्तनम को राज्य की कार्यकारी राजधानी बनाने में उनका समर्थन भी मांगा। विधानसभा अमरावती में ही रहेगी और उच्च न्यायालय को कुर्नूल स्थानांतरित किया जाएगा। खबरों के मुताबिक मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वह गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करें। बुधवार को मोदी से मिलने के बाद रेड्डी शुक्रवार को फिर दिल्ली पहुंचे ताकि गृहमंत्री के सामने इस विषय में अपनी प्रस्तुति दे सकें। रेड्डी ने प्रधानमंत्री को अपनी उस मांग से भी अवगत कराया जो राज्य विधान परिषद को भंग करने तथा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में है। इसके बदले में वाईएसआर कांग्रेस के भाजपानीत राजग में शामिल होने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। हालांकि इस विषय पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा पहले ही पारित कर चुकी है और इसे संसदीय मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह भंग हो जाएगी। इस बीच रेड्डी ने 25 मार्च को तेलुगू उत्सव अगाड़ी के अवसर पर प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश आने का न्योता भी दिया है। उस मौके पर 25 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास योजना की शुरुआत की घोषणा भी की जाएगी।

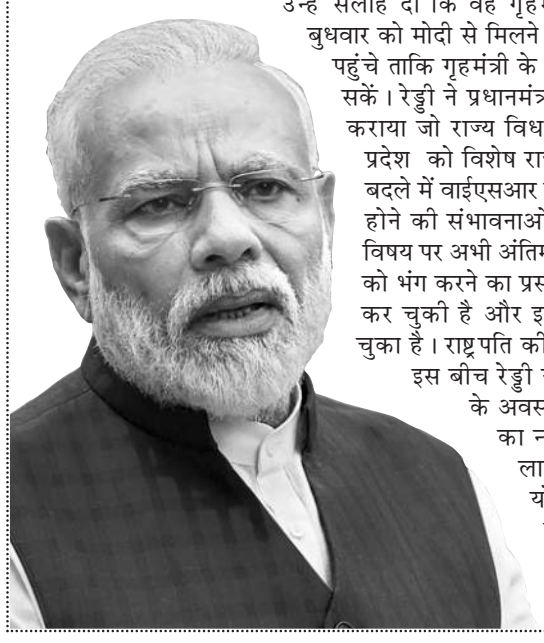

आपका पक्ष

देश में आर्द्र भूमि की रक्षा जरूरी

भारत में आर्द्र भूमि विश्व की तुलना में काफी कम है। इसका प्रतिशत तुलनात्मक रूप से विश्व के छोटे देशों से भी कम है। हाल में मानव के बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के कारण इसके खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। भारत में आर्द्र भूमि आर्थिक एवं पारिस्थितिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने होंगे। वर्तमान में भारत में कुल 37 प्रकार की आर्द्र भूमि का पता लगाया गया है। भारत में तकरीबन एक करोड़ हेक्टेयर में आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2 फरवरी, 1971 को आयोजित किया गया जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्र भूमि को बचाने का संकल्प लिया। इसमें जैव विविधता की अपील की गई है। विज्ञान और तकनीकी विकास, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप से इसे मुक्त रखने का संकल्प लिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के आर्द्र भूमि की सूची बनाई गई है। इस तरह की दो आर्द्र भूमि भारत में चिह्नित की गई हैं। इनमें केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान और लोकतक मणिपुर हैं। भारत सरकार ने आर्द्र भूमि के विनाश एवं समाप्त होने के खतरे को देखते हुए 1987 में एक नई योजना की शुरुआत की थी। इसके संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए 24 आर्द्र भूमि और 33 वन क्षेत्र का चयन किया गया था। केंद्र सरकार ने 2017 में आर्द्र भूमि के आसपास उद्योग, कचरा डंपिंग और प्रदूषणकारी पदार्थों के बहाव पर कड़े नियम बनाए हैं।

शैलेंद्र कुमार पांडेय, पटना

केंद्र सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2017 में कड़े कानून बनाए हैं

स्कूल प्रशासन की लापरवाही

पंजाब के संगरूर में सरकार, प्रशासन और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही मासूम बच्चों की जान पर भारी पड़ गई। हाल में यहां एक स्कूल वैन में आग लगने से कुछ मासूम बच्चों की मौत हो गई थी तथा कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगर सरकार, प्रशासन ने पहले ही स्कूलों की लापरवाही से हुए हादसों से सबक लिया होता और स्कूली वैन का निरीक्षण किया होता तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता था। इससे स्कूली बच्चों की दुर्घटना में मौत होने से बच भी सकती थी। सरकार और प्रशासन हर हादसे के बाद हरकत में आती हैं और जांच के आदेश तथा मुआवजे की घोषणा के बाद अपनी जिम्मेदारी पूर्ण समझते हैं। स्कूली बसों या वाहनों के लिए कुछ नियम बने हैं। स्कूली बसों में सीटों की संख्या से अधिक बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता है। वहीं सीट में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। अगर स्कूली वाहन परिवहन मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं तो ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाना चाहिए। कुछ स्कूल भी मोटी कमाई के चक्कर में इंसानियत की अनदेखी करते हुए बच्चों की सुरक्षा को भी दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करते हैं। कुछ निजी वाहन चालक भी बच्चों को स्कूल ले जाते हैं तथा सीटों की संख्या से अधिक बच्चों किसी तरह वाहन में ठूंस देते हैं। ऐसे वाहनों पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार तथा प्रशासन को ऐसे वाहनों की निरंतर जांच करनी चाहिए। आखिर लापरवाह स्कूलों पर कब लगाम लगेगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

दिल्ली चुनाव में राष्ट्रवाद पर मुफ्त सौगात भारी

दीपक शर्मा

अतिवाद को मिला जवाब

दिल्ली चुनाव नतीजों का संदेश भाजपा के राष्ट्रवाद का खारिज होना माना जा रहा है। इतने बड़े जनादेश के पीछे कहीं न कहीं मुफ्त और छूट की राजनीति की बेहद अहम भूमिका रही है। जनता ने राष्ट्रवाद एवं विकास के मुद्दे पर ही मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और वहीं क्षेत्रीय मुद्दों और विकास पर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को पसंद किया है। राष्ट्रवाद का मुद्दा क्षेत्रीय प्रादेशिक चुनाव को एक हद तक ही प्रभावित कर सकता है इसका संदेश जनता ने भाजपा को स्पष्ट रूप से दिया। संदेश है कि राष्ट्रवाद के अतिवाद से बचें और क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेताओं को मजबूती से सामने रखें।

अंकित कुमार त्रिपाठी

ई-मेल से

स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने का संदेश

दिल्ली चुनाव नतीजों पर दुनिया की नजर थी। यहां चुनाव में अर्थशास्त्र ने सफलता हासिल की है। अन्य बातें पृष्ठभूमि में चली गई। इन चुनाव नतीजों का संदेश भी यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद विधानसभा चुनावों में स्थानीय आर्थिक मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय आर्थिक मुद्दों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। स्थानीय आर्थिक समस्याओं का समाधान चुनाव में सफलता का मार्ग प्रस्तुत करता है। चुनाव के नतीजे भविष्य के लिए संदेश देते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान सहयोग से होता है संघर्ष से नहीं।

डॉ. एम एस सिद्दीकी

फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

जाति-धर्म छूटे पीछे, अब काम पर वोट

जिस तरह से केजरीवाल ने आखिरी के छह महीनों में एक नई रणनीति के तहत दिल्लीवासियों का भरोसा जीता और मुख्य विपक्षी दल भाजपा की राजनीति और आलोचनाओं का कड़ा जवाब दिया उसे देखकर सभी सकते में हैं। हर तरफ केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में देखा भी जा रहा है। दिल्ली में वैसे हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की पर विधानसभा में उसका प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा। दिल्ली के चुनावी नतीजे इशारा कर रहें कि अब चुनाव में जनता को जात, पात और धर्म से नहीं जमीन पर हुए काम को देखना है।

डॉ रसिकेश नवजात

जौनपुर, उत्तर प्रदेश

केजरीवाल तीसरे विकल्प की ओर

दिल्ली चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुफ्त में सब कुछ देने की राजनीति उनकी रणनीतिक पहल है। इस पर सफाई देते हुए केजरीवाल ने मरीजों, गरीबों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्ग से किसी प्रकार का भुगतान लेने को सही नहीं ठहराया। भले ही उनके विरोधी आलोचना कर रहे हों पर सामाजिक समरसता और सामाजिक उत्थान का उनका यह विचार दिल्ली जैसी ज्यादा पढ़ी लिखी जनता में भी कारगर रहा। केजरीवाल ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना भी छोड़ दिया। केजरीवाल फिर से एक तीसरे विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं।

दिव्या प्रीत सेठी

नोएडा, उत्तर प्रदेश

भाजपा को मिला कड़ा संदेश

दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए वह हमारी राजनीति का एक बहुत बड़ा स्याह सच है। वह यह है कि जिसने भी अपने लुभावने नारों और वादों से जनता का दिल जीत लिया, जनता उसको वोट दे देती है। जिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की एक भी सीट नहीं जीत पाई वह विधानसभा के चुनावों में प्रचंड बहुमत पाकर दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज हो गई। लेकिन अफसोस तब होता है जब जिस जनता को बरगला कर ऐसे नेता सरकार बनाते हैं उसी की समस्याओं की तरफ झांकते भी नहीं। वैसे आप ने बहुत से काम दिल्ली में किए और अरविंद केजरीवाल ने जो लक्ष्य लेकर नरेंद्र मोदी को हराया उससे मोदी के प्रसंशक भी केजरीवाल के हो गए। दिल्ली चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए कड़ा संदेश है कि उन्हें भी अपनी कार्य पद्धति सुधारनी पड़ेगी।

डॉ आंजनेय गुप्ता

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रवाद पर हावी विकास की राजनीति

हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ तौर पर पता चलता है कि लोकतंत्र में देश की जनता ही सर्वोपरि होती है। यह चुनाव परिणाम दर्शाता है कि राजनीतिक दलों के हर स्तर के चुनाव में ज्वलंत मुद्दे, धार्मिक भेदभाव, जातिवाद के जरिये अपना हित साधने की रणनीति रहती है। इसे दिल्ली की जनता ने साफतौर पर नकार कर अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का अनुभव कराया है। विपक्षी पार्टियां पूरे चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के विकास के फॉर्मूले की कोई ठोस कारगर तोड़ जनता के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाईं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने आप को विवादित मसलों से दूर रखकर दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बना ली।

प्रांशुल श्रीवास्तव

भोपाल, मध्य प्रदेश

विकास को तरजीह

दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2012 में स्थापित आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आप ने कहा था उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ, बिजली एवं पानी से जुड़े जो काम किए हैं जनता उसके आधार पर उन्हें वोट दे। वहीं भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटाने एवं नागरिकता संशोधन कानून को अपने प्रचार अभियान का आधार बनाया। इस चुनाव परिणाम ने यह दर्शाया है कि अब लोग जागरूक एवं समझदार हो रहे हैं। नतीजों से स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने विकास और कल्याण को तरजीह दी एवं धार्मिक उन्माद वाले मुद्दे और बंटवारे की राजनीति को खारिज किया है। इससे यह संदेश भी मिला है कि विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे ही सर्वोपरि है यहां राष्ट्रीय मुद्दे अप्रासंगिक हैं। पार्टी के बड़े चेहरों के बल-बूते चुनाव जीतने की रणनीति हर बार काम नहीं करेगी। इससे यह भी इंगित होता है की मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल अपने विवेक के अनुसार करता है।

चंदन केशरी

जमशेदपुर, झारखंड

अन्य प्रदेशों में जाएगी यह लहर

प्रधानमंत्री अपने कई कार्यों जैसे धारा 370, तीन तलाक विधेयक, राम जन्मभूमि निर्माण, सर्जिकल स्ट्राइक को अपने चुनावी मुद्दों के रूप में प्रस्तुत कर चुनाव जीतने की रणनीति बनाए हुए थे। इतना ही नहीं भाजपा ने शाहीन बाग को एक बड़े मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया। अरविंद केजरीवाल भाजपा के ठीक उलट दिल्ली की जनता को अपने चुनाव के केंद्र में रखकर निम्न वर्ग से लेकर मध्य वर्ग तक की जनता की चिंता की। दिल्ली चुनाव की बातें देशव्यापी प्रभाव डालने वाली है। देश के बाकी प्रदेशों की जनता भी अपने-अपने प्रदेशों में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता की तलाश में हैं और यह चाह रही है कि हमारे प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो। दिल्ली चुनाव का संदेश प्रदेशों में पहुंचने लगा है।

रूबी सिंह

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

विपक्षी दल करें आत्म निरीक्षण

दिल्ली के चुनाव नतीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव सत्तारूढ़ दल और बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर पड़ा है। कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को ही खत्म कर लिया है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को अपनी गलत नीतियों के कारण ही उबरने में काफी परेशानी होगी। भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को भुनाने, जनता के मध्य जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करने, चुनाव में गलत नारे लगाने, जनमुद्दों को छोड़ने आदि के कारण हुआ है। वहीं केजरीवाल को शिक्षा में सुधार, मोहल्ला क्लिनिक खोलने आदि के कारण फायदा मिला। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की परेशानियों को हल करने में जो भूमिका निभाई उसे नकारा नहीं जा सकता है।

दिनेश गुप्ता

पिलखुवा, उत्तर प्रदेश

जनमुद्दों पर ध्यान देना होगा

दिल्ली चुनाव परिणाम का संदेश यह कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा का पूरा दलबल लगने के बाद भी जनता का समर्थन एक ऐसी पार्टी को रहा जो जनता के मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से जुड़ी रही और स्वयं को जाति, धर्म, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों से दूर रखने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट है कि अब मतदाता ऐसे विकल्प की ओर देख रहा है जो उसको झूठे मनगढंत मुद्दों में उलझाए नहीं बल्कि जनता के समान्य मुद्दों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे। लोगों को सिर्फ बड़े-बड़े सपने न दिखाएं बल्कि उनकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करे। मतदाता राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों में स्पष्टता से अंतर करके मतदान कर रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस दिशा में बढ़ने के संकेत दिए हैं।

अतिन कुमार दुबे

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

भाजपा को उसी शैली में मिला जवाब

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का प्रमुख कारण यह रहा कि अरविंद केजरीवाल का नरम हिंदुत्व भाजपा की जुमलेबाजी पर भारी पड़ गया। इस चुनाव के नतीजों से स्पष्ट संदेश गया कि यह महज मुफ्त के मनोविज्ञान का नतीजा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल से ज्यादा मुफ्त सौगातों की घोषणा की थी। इस चुनावी जीत को लेकर एक राय यह भी बनी है कि आक्रामक रणनीति और रोबोटिक प्रबंधन की बदौलत किसी को भी वोट अपने पक्ष में डालने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मतदाताओं को राजनीतिक पार्टियों द्वारा मंदबुद्धि समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए।

इंदु सोमानी

देवास, मध्य प्रदेश

दिल्ली मॉडल की देश को जरूरत

दिल्ली चुनाव परिणाम के नतीजे बताते हैं कि जनता धर्म और जाति पर आधारित राजनीति से ऊब चुकी है। जनता को धरातल पर रहकर काम करने वालों को सत्ता सौंपने में गुरेज नहीं। इस प्रकार दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए कार्य किए गए हैं वैसे ही कार्य देशभर में किए जाने की आवश्यकता है। अगर देशभर में विकास का दिल्ली मॉडल अपनाया जाए तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीत सकता है। दिल्ली चुनाव के परिणाम बताते हैं कि जनता अब नेताओं के लुभावने प्रलोभनों के झांसे में नहीं आने वाली है। वह चाहती है कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार हो। राजनीतिक दलों को अनर्गल बयानबाजी से बचते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे में बदलाव लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

आशीष श्रीवास्तव

भोपाल, मध्य प्रदेश

अनर्गल बातों को सख्त संदेश

दिल्ली चुनाव के नतीजे राजनीतिज्ञों के लिए संदेश स्पष्ट है कि उनको अनर्गल बातों से, व्यर्थ के विवादों से और आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। काम पर ध्यान देना हर एक नेता को समझना होगा। शाहीन बाग के मुद्दे को उछाल कर भाजपा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला दी। उसे आखिर तक जीत की खुशफहमी बनी रही। जिस पार्टी ने विजय हासिल की उसकी एक खासियत माननी पड़ेगी कि उसने कम से कम अपशब्दों का प्रयोग किया। सत्ता पाने के बाद वह हनुमान जी की शरण आई और उनका धन्यवाद माना।

हिम्मत जोशी

ई-मेल से

काम के दम पर दिल्ली फिर आप की

राजनीति में चुनाव जीतने का पक्का फार्मूला सिर्फ काम होता है बाकी तो काठ की हांडी होती है जो एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने लोकसभा चुनावों के मुद्दों को आगे कर लड़ाई लड़ी। आप की जीत में कांग्रेस के अच्छे से चुनाव नहीं लड़ने का भी योगदान रहा। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों को आगे करने के साथ आप नेताओं के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया, जबकि आप नेताओं ने शालीनता का परिचय दिया और शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए गए शानदार कामों, मुफ्त बिजली-पानी और महिलाओं के बस यात्रा आदि का बखान किया। दिल्ली में भाजपा के परंपरागत मतदाता मसलन कारोबारी जीएसटी की जटिल प्रणाली का सरलीकरण नहीं होने से छिटक गए।

अनिल कोथुलकर

इंदौर, मध्य प्रदेश

बकौल विश्लेषक

स्थानीय समस्याओं का समाधान करने वालों को मौका का संदेश

दिल्ली विधानसभा के चुनावों के नतीजों से स्पष्ट है कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी भाजपा आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत को नष्ट नहीं कर पाई। भले ही उसे ज्यादा मत और सीटें मिली हों। चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर बाजी पलटने में असमर्थ साबित हुए और उन्हें आत्ममंथन के बाद यह भी स्वीकार करना पड़ा कि चुनाव अभियान के दौरान सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाले, समुदाय विशेष के प्रति घृणा और गुस्सा दिलाने वाले बेलगाम बयानों ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया। ध्रुवीकरण की रणनीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति बनाम गद्दारी को आर्थिक मुद्दों पर तरजीह देना भी आत्मघातक साबित हुआ। आम आदमी पार्टी ने भले ही 4 सीटें गंवाई। पर यह साबित कर दिया कि आम आदमी का समर्थन उनके पास है। दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर, आलसी, गैर जिम्मेदार घोषित करने वालों की कमी नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल ने खुद को सब्जबाग दिखाने में सबसे माहिर प्रमाणित कर दिया। साथ ही जनता की नजर में केंद्र की दखलअंदाजी के कारण ही वह अपने सभी चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाए थे, इसलिए एक और मौका दिया जाना चाहिए। केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों को हनुमान चालीसा के पाठ से पटकनी दे डाली। बिजली, पानी, अस्पताल और रोजागार-कारोबार को ही आम आदमी पार्टी ने अपने अभियान में प्राथमिकता दी। केजरीवाल के दावों को खोखला कह बदनाम करने के प्रयास विश्वसनीय नहीं बन सके। इसका मतलब यह है कि मतदाता आज न तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले नेताओं के पीछे चलने को तैयार है और न ही उग्र, आक्रामक अंध देशभक्ति की नारेबाजी उसे गुमराह कर सकती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान तलाशने वाले को एक और मौका देने के लिए नई पीढ़ी के बहुसंख्यक मतदाता हिचकते नहीं। देखने लायक यह होगा कि क्या यही प्रवृत्ति उन दूसरे राज्यों के चुनावों में देखने को मिलेगी जहां आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं और जहां चुनाव निकट भविष्य में आसन्न नहीं वहां भी।

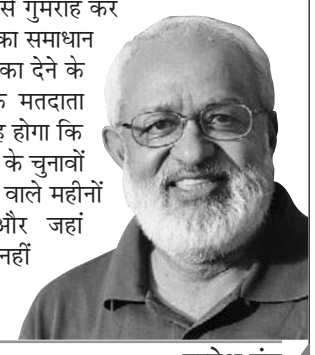

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

पुष्पेश पंत

पूर्व प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनैशनल स्टडीज, जेएनयू

सरकार की आय के दायरे में हो मुफ्त की योजनाएं

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इस जीत में केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को दी गई मुफ्त व रियायती दर पर सेवाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है। अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या मुफ्त की योजनाएं देश के अन्य राज्यों में भी लागू की जा सकती है। मुफ्त की योजनाओं को राज्यों में लागू करना उक्त राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। दिल्ली के संदर्भ में भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं हमेशा लागू कर पाना संभव है। आज हो सकता है कि दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति इन योजनाओं का खर्च उठाने में सक्षम हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि आगे सरकार खर्च उठाने में सक्षम न हों। एक बार मुफ्त में सेवाएं मिलने के बाद लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है। फिर किसी सरकार के लिए मुफ्त की योजनाओं को बंद कर पाना आसान नहीं होगा और हमेशा मुफ्त की योजनाएं चालू रखना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन पर खर्च सरकार के लिए प्रतिबद्ध खर्च के रूप में बरकरार रहेगा। हालांकि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, बिजली-पानी आय की दृष्टि से निचले तबके के लिए फायदेमंद है। लोगों की सामाजिक सुरक्षा के रियायती दर पर सुविधाएं देना ठीक है। लेकिन सरकारों को अपनी आय के दायरे में ही मुफ्त और रियायती दर वाली योजनाओं को लागू करना चाहिए। सरकारों को रियायती दर पर सुविधाएं देने के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि उसे इनके लिए बाजार से कर्ज लेना पड़े। इससे सरकारों के राजकोषीय घाटे की स्थिति बिगड़ सकती है जो किसी भी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। भले ही दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद देश के अन्य राज्यों में मुफ्त की योजनाएं लागू करने की बात उठ रही है, लेकिन सरकारों को रियायती दरों या मुफ्त में लोगों को सुविधाएं अपनी आय के दायरे में रहकर ही देना चाहिए।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

सुनील कुमार सिन्हा

प्रधान अर्थशास्त्री, इंडिया रेटिंग

पुरस्कृत पत्र

वादों को हकीकत में बदलने की शुरुआत

आम आदमी पार्टी की जीत को पूरे देश में राजनीतिक मुद्दों में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। काम पर वोट मांगने और वादों को हकीकत में बदलने की एक नई शुरुआत हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिला सुरक्षा आदि पर जनता ने दूसरी बार भी आप को भारी बहुमत दिया। दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने बड़े-बड़े वादे किए लेकिन मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने का आरोप जनता पर लगाया गया। परंतु समग्र तौर पर देखें तो राजनीति में यह बिल्कुल नया मोड़ है। विश्वविद्यालय से लेकर सड़क तक विद्यार्थियों और जनता के साथ आप पार्टी खुलकर सामने नहीं आई। इसके पीछे शायद वोट कटने का डर रहा होगा। साथ ही हिंदुत्व की राजनीति में आप पार्टी भी शामिल होती दिखी। इस चुनाव को विधानसभा स्तर पर जनता के समझौते के तौर पर भी देखा जा रहा है।

1

विशाल कुमार शर्मा
मोतिहारी, बिहार

पुरस्कार राशि
500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

डॉ. दीप्ति विश्वास
भोपाल, मध्य प्रदेश

जनता काम देखती है

दिल्ली चुनाव के परिणामों से यह स्पष्ट है कि आम जनता अब परंपरागत राजनीति से त्रस्त हो चुकी है और वह राजनीतिक संस्कृति को बदलना चाहती है। वह स्थानीय मुद्दों, नागरिक सुविधाओं, जनकल्याणकारी कार्यों में हुए सुधारों को अधिक महत्त्व देती हैं। यद्यपि देश की सुरक्षा व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी भावनाएं उद्वेलित होती हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में अब काम व विकास की राजनीति ही सफल होगी, न कि धर्म के आधार पर की गई राजनीति। निम्न आय वर्ग को मुफ्त में सुविधाएं भी आकर्षित करती है। आम जनता अब मतदान करते समय बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, शासकीय कार्यालयों में नित्य प्रति के कार्यों के लिए उसके संघर्ष, महंगाई जैसे मुद्दों को प्रधानता देने लगी है।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

काम को मिला जनादेश

भाजपा जीत के प्रति अतिआत्मविश्वास में रही और उसने केजरीवाल पर प्रहार करते हुए उन्हें आतंकवादी तक कहा, जो दिल्ली की जनता के गले नहीं उतरा। धारा 370 और सीएए के खिलाफ आंदोलनों की धुंध ने भाजपा की छवि को भी धूमिल किया। जनता के बीच संदेश यह गया कि दिल्ली को राहत आप पार्टी ही पहुंचाएगी न कि भाजपा। अपने विगत कार्यकाल में आप पार्टी ने खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार किए। दिल्ली में फ्री व सस्ती बिजली-पानी की सुविधा ने निम्न और मध्य आय वर्ग को भारी राहत प्रदान की है, जो आप के फिर से चयन का प्रमुख कारण रहा। दिल्ली चुनाव के नतीजे केंद्र व दूसरे राज्यों की सरकारों के लिए अनुकरणीय इस रूप में भी है कि मुफ्त सुविधाएं जनता को देने के बाद भी सरकार घाटे में नहीं है।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

आम मुद्दों को महत्त्व

दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की मुख्य वजह इसका आम आदमी के आधार से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन कुछ लोग आप की जीत को मुफ्तखोरी की जीत भी बता रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलने, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने और मोदी राज में अयोध्या विवाद का हल निकलने के बावजूद भी 2019 में हुए महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आदि राज्यों में भाजपा को उसकी उम्मीद के अनुसार जीत हासिल न होना यह सिद्ध करता है कि देश का मतदाता राजनीतिक तौर पर जागरूक होकर तानाशाही, जीत के घमंड को वोट देते समय अनदेखा करने लगे हैं।

साक्षी पांडे
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

अपेक्षाओं का बोझ

आम आदमी पार्टी की जीत ने यह साबित किया है कि वह जनता की नब्ज को पकड़ने में सफल रही। वहीं भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में असफल रही। एक वर्ग ऐसा भी है जो दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहने में भी जुटा हुआ है। लेकिन जीत की वजह सिर्फ मुफ्तखोरी है कहना भी ठीक नहीं रहेगा। अब दिल्ली मॉडल को गुजरात मॉडल से तुलना करके केजरीवाल को मोदी का दूसरा विकल्प दिखाया जा रहा है। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले केजरीवाल मध्य वर्ग की आकांक्षा वाले भारत के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बने हुए हैं। केजरीवाल ने जनता को मुफ्त बिजली पानी और महिलाओं को बस यात्रा की सुविधा से आकर्षित तो किया है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह केवल इसी के बलबूते पर चुनाव जीते हैं।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है –
ट्रंप की यात्रा भारत के लिए कितनी फायदेमंद?

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

काल्पनिक मुकदमेबाजी पर अदालत की फटकार

एमजे एंटनी

अदालत से

उच्चतम न्यायालय ने विदेशी मध्यस्थता पंचाट के फैसले के खिलाफ दायर दो अपीलों को खारिज करते हुए मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पर प्रतिकूल टिप्पणी की और एक संयुक्त उपक्रम के शेयरधारकों के समूह पर लागत के रूप में 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। ये अपील बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि लंदन में एकल मध्यस्थ पंचाट द्वारा दिए गए चार अंतिम फैसले भारत में लागू करने योग्य हैं। उच्चतम न्यायालय ने विजय करिया बनाम प्रिसमियन सिस्तेमी वाद में कहा, 'हमें लगता है कि अपीलकर्ता काल्पनिक मुकदमेबाजी में शामिल हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे विदेशी पंचाट के फैसले पर कीचड़ उछालेंगे तो इसकी कुछ छींट वहां तक जरूर पहुंचेगी। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि वास्तव में उनकी सारी दलीलें पंचाट के निष्कर्षों के खिलाफ हैं। पंचाट ने मामले के गुणदोष के आधार पर फैसला सुनाया है।'

बाउंस चेक के मामले में सबूतों का बोझ

उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि अगर चेक जारी कर दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो यह माना जाता है कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या देनदारी को चुकाने के लिए इसे जारी किया गया है। न्यायालय ने ऐप्स फोरेक्स सर्विसेज लिमिटेड बनाम शक्ति इंटरनैशनल फैशन लिंकर्स वाद में अपील को स्वीकार करते हुए यह बात कही। निचली अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फर्म के साझेदारों को आरोपमुक्त कर दिया था लेकिन अपील पर उन्हें दोषी करार दिया गया और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। आरोपियों की दलील थी कि उन्होंने अपने कारोबारी लेनदेन में सुरक्षा राशि के तौर पर चेक जारी किया था और इसमें कोई कर्ज शामिल नहीं था। निचली अदालतों ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बार-बार चेक काटे जाने से पता चलता है कि कोई देनदारी जरूर थी।

केवल स्वैच्छिक संस्थाएं उपभोक्ता

उच्चतम न्यायालय ने शोभा हिबिस्कस कंडोमिनियम बनाम शोभा डेवलपर्स वाद में कहा कि कंपनी कानून या अन्य कानूनों के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था ही उपभोक्ता फोरम में जा सकती है। इस मामले में कंडोमिनियम कर्नाटक अपार्टमेंट ऑनरशिप ऐक्ट के प्रावधानों के तहत एक विधायी संस्था थी। कानून के तहत अनिवार्य आधार पर इसका गठन किया गया था। जब उसने डेवलपर्स के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया तो उसकी शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून की परिभाषा के मुताबिक न तो उपभोक्ता है और न ही पंजीकृत स्वैच्छिक संघ। कंडोमिनियम ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था कई लोगों के समूह द्वारा बनाई गई संस्था होगी। इसका गठन बिना किसी दबाव या प्रभाव के और कानून के किसी अन्य प्रावधान द्वारा अनिवार्य किए बिना होगा। अगर कोई संस्था किसी इमारत के फ्लैट मालिकों द्वारा बनाई गई है जो उसे स्वैच्छिक संस्था नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह राज्य कानून के अनिवार्य प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आई है।

गैस आपूर्ति निविदा में अपीलें खारिज

उच्चतम न्यायालय ने चार दक्षिण भारतीय जिलों में प्राकृतिक गैस के वितरण की निविदा के संबंध में पेट्रोलियम ऐंड नैचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड के फैसले के खिलाफ अदाणी गैस लिमिटेड और आईएमसी लिमिटेड की अपील को पिछले सप्ताह खारिज कर दिया। चेन्नई, पुदुच्चेरी, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, चलाने या विस्तार करने की परियोजना का ठेका देने पर विवाद पैदा हुआ। यह मामला बिजली अपील पंचाट में पहुंचा लेकिन उसने खंडित फैसला सुनाया। चेयरमैन और तकनीकी सदस्य की राय अलग-अलग थी। मामले को न्यायिक सदस्य के पास भेजा गया लेकिन उसने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए उच्चतम न्यायालय को अपनी असाधारण शक्तियों के तहत इस विवाद का फैसला करना पड़ा। गैस वितरण का काम करने वाली संस्था को बोर्ड से मंजूरी लेनी होती है। नियमों में 2018 में बदलाव किए गए जिससे यह विवाद पैदा हुआ। गैस कंपनियों की दलील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि बोली सही है या नहीं, इसका आकलन करने का अधिकार केवल सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी और बोर्ड को है। न्यायालय ने कहा कि इसमें एकमात्र सवाल यह था कि क्या सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की बोली सही थी? इसका निर्धारण करने का अधिकार पूरी तरह से बोर्ड के पास है। इसमें दूसरे बोलीकर्ताओं की मौजूदगी और सुनवाई जरूरी नहीं है। बोर्ड के आकलन से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले सैकड़ों बोलीकर्ताओं और उनके बरअक्स सैकड़ों दूसरे बोलीकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कामगार के दावों में धारणा

नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मौत का मुआवजा तय करते समय कर्मचारी मुआवजा कानून में उसका मासिक वेतन 8,000 रुपये माना गया है। 2010 से पहले यह 4,000 रुपये था। के शिवरामन बनाम पी सतीशकुमार वाद में जब 2008 में 26 वर्षीय कर्मचारी की मौत हुई थी तो यह सीमा 4,000 रुपये थी। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने संशोधित नियम के मुताबिक मुआवजा तय किया और मृतक के आश्रितों को 8.86 लाख रुपये का मुआवजा दिया। नियोक्ता की अपील पर न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना के दिन मुआवजे का भुगतान प्रासंगिक है, संशोधन के बाद नहीं। इस मामले में मृतक कर्मचारी का वेतन 32,000 रुपये था। लेकिन इसे प्रासंगिक नहीं माना गया क्योंकि सरकार की अधिसूचना के मुताबिक चाहे वेतन हो भी हो, उसकी तय सीमा ही लागू होगी। कानून बनाने वालों में महंगाई की दर को इसमें शामिल नहीं किया है।

रुख में बदलाव से नहीं खुलेगा कर आकलन

आय कर अधिकारी आकलन के चार साल बाद उसे इस आधार पर फिर से नहीं खोल सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने बाद के फैसले में अपनी राय बदल दी है। राजस्व अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि करदाता पूरी तरह अपनी संपत्तियों का खुलासा करने में नाकाम रहा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता क्लब लिमिटेड बनाम आईटीओ वाद में रिट याचिका को सही ठहराते हुए यह बात कही। इस याचिका में कर के फिर से आकलन के लिए नोटिस को चुनौती दी गई थी। 2007-08 के आकलन में इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि किसी क्लब के कॉरपोरेट सदस्य के रूप में ब्याज से हुई कमाई पर कर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 2013 में उच्चतम न्यायालय ने बेंगलूरु क्लब मामले में इसके उलट फैसला दिया और साथ ही कहा कि यह आय परस्परता के सिद्धांत के दायरे में नहीं आती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय बाद में अपने रुख में कोई बदलाव करता है तो इसे क्लब की गलती नहीं माना जा सकता है।

समयबद्ध मंजूरी से निवेशकों पर डोरे

मध्य प्रदेश ने औद्योगिक मंजूरियों में देरी के लिए अधिकारियों को दंडित करने का प्रस्ताव दिया है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पारदर्शिता पर होना चाहिए जोर

सुदीप्त दे

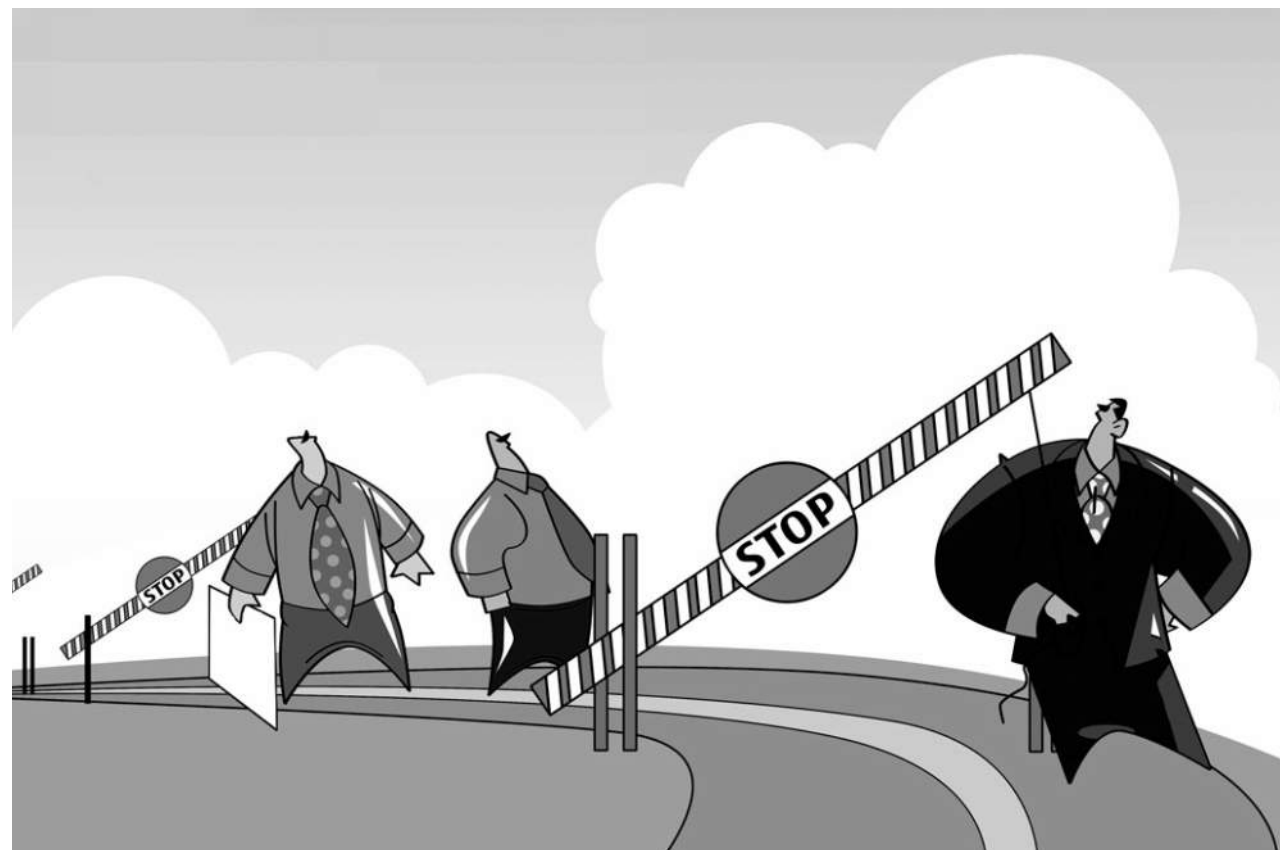

औद्योगिक मंजूरियों में एक वैधानिक समय-सीमा से अधिक देरी किए जाने पर सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के प्रावधान वाले कानून को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नई अवधारणा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि समयबद्ध मंजूरी प्रक्रिया के लिए राज्यों द्वारा कई कानून और नियम बनाए गए हैं लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपायों के नतीजे मिश्रित रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताजा पहल- मध्य प्रदेश टाइम-बाउंड क्लीयरेंस बिल 2020- यानी मध्य प्रदेश समयबद्ध मंजूरी विधेयक कितना कारगर होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस नए कानून को किस तरीके से लागू किया जाता है।

एसऐंडआर एसोसिएट्स के पार्टनर रजत सेठी ने कहते हैं, 'परमिट प्रकिया लंबे समय से भारतीय उद्योग अभिशाप रही है।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ऐसी किसी भी पहल से मौजूदा परमिट प्रक्रिया में बदलाव लाने में मदद मिलेगी जहां व्यवस्थागत समस्याएं अपनी जड़ें जमा चुकी हैं।

हाल में इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और आगामी बजट सत्र के दौरान उसे विधान सभा में पेश किया जाएगा। इसके तहत औद्योगिक निवेश के लिए आवेदन को समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने की बात कही गई है। इसमें उद्योग के लिए 25 प्रकार की मंजूरियों और लाइसेंस को एक ही दिन में जारी करने, 10 प्रकार की अन्य मंजूरियां सात दिनों में जारी करने और पांच अन्य मंजूरियां 15 दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये देने की बात कही गई है।

कुल मिलाकर, यदि कोई अधिकृत अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्य करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सर्विस गारंटी ऐक्ट 2010 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ऑर्टिस लॉ ऑफिस के पार्टनर संदीप ग्रोवर ने कहा कि कई राज्यों में सरकारी विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से मंजूरियां दी जा रही हैं। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए समयबद्ध तरीके से मंजूरी एवं अनुमोदन उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग संवर्द्धन समिति की स्थापना की है। इसी प्रकार, 2018 में केरल इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन ऐंड फैसिलिटेशन ऐक्ट को पारित किया गया था। राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग ऐंड क्लीयरेंस ऐक्ट 2011 के तहत कहा गया है कि यदि कोई विभाग एक निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो उस आवेदन को मंजूर मान लिया जाएगा।

हालांकि विश्लेषकों ने सहमति जताई कि प्रस्तावित कानून की मंशा राज्य में लाइसेंसिंग व्यवस्था में सुधार लाना और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करना है। लेकिन कुछ विश्लेषकों ने आशंका जताई कि यदि इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो इससे अड़चन पैदा हो सकता है। अद्वय लीगल के मैनेजिंग पार्टनर रमेश वैद्यनाथन कहते हैं, 'इससे अधिकारियों द्वारा अनावश्यक पूछताछ और मामूली कारणों से आवेदन को खारिज करने के मामले बढ़ सकते हैं।'

सेठी ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करने की जरूरत है क्योंकि इससे सही निर्णय लेने को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, 'यदि उन पर अभियोजन का संभावित खतरा लगातार मंडराता रहेगा तो उससे त्वरित और कुशल निर्णय लेने में बाधा आएगी।' वैद्यनाथन का मानना है कि मंजूरी देने का ढांचा जवाबदेही पर आधारित होना चाहिए जहां आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन माध्यम से साझा किया जाए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की जाए और लापरवाह अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के वार्षिक मूल्यांकन में खमियाजा भुगतना पड़े।

वैद्यनाथन कहते हैं, 'सभी विभागों को यह भी कहा जाना चाहिए कि वे मंजूरियों और उसमें लगने वाले समय आदि की जानकारी अनिवार्य तौर पर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। संक्षेप में कहें तो दंडात्मक कार्रवाई के बजाय बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना कहीं अधिक कारगार उपाय साबित हो सकता है।'

यदि कमजोर प्रदर्शन के लिए सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाता है तो क्या लाइसेंस अथवा परमिट हासिल करने की शर्तों को पूरा न करने के लिए कारोबारियों को जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए?

ग्रोवर के अनुसार, इस विधेयक की धारा 6 (2) (क) के तहत लाइसेंस हासिल करने के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए आवेदक को जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, 'हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि आवेदक द्वारा किस तरीके से सूचनाएं मुहैया कराई जाए और अनुपालन न करने सूरत में उसे किन परिस्थितियों एवं जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा जैसे मामलों में सरकार किस प्रकार के विशेष नियम-कानून बनाती है अथवा।'

अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि लाइसेंस व्यवस्था में कहीं अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे ताजा उपायों का तालमेल निर्णय लेने में सहायता के लिए सरकारी अधिकारियों की सूचनाओं और संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दबाव से निपटने के लिए कहीं अधिक समर्थ बनाने के साथ होना चाहिए।

मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू करने पर अन्य राज्यों की भी करीबी नजर रहेगी।

निवेशकों को आकर्षिक करने पर नजर

मध्य प्रदेश समयबद्ध मंजूरी विधेयक मसौदा

- औद्योगिक, एमएसएमई, आईटी और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के लिए आवेदनों को समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन मंजूरी
- प्रस्तावित कानून के तहत उद्योगों के लिए 25 प्रकार की मंजूरियों एवं लाइसेंस को एक ही दिन में जारी करने, 10 प्रकार की मंजूरियां सात दिनों में और पांच अन्य मंजूरियां 15 दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये देने का प्रावधान
- यदि कोई अधिकृत अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्य करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सर्विस गारंटी ऐक्ट 2010 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी

अन्य राज्यों में

- आंध्र प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए समयबद्ध तरीके से मंजूरी एवं अनुमोदन उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग संवर्द्धन समिति की स्थापना की है
- केरल ने 2018 में इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन ऐंड फैसिलिटेशन ऐक्ट को पारित किया था
- राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग ऐंड क्लीयरेंस ऐक्ट 2011 के तहत कहा गया है कि यदि कोई विभाग एक निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने में विफल रहता है तो उस आवेदन को मंजूर मान लिया जाएगा

ऑडिट की स्वतंत्रता का नया मानदंड

गैर-ऑडिट सेवाओं पर लगाम के एमसीए के प्रस्ताव से छोटी फर्मों पर असर पड़ेगा

गीतिका श्रीवास्तव और सुदीप्त दे

ऑडिट की चुनौतियां

- अपने ग्राहकों से लिए जाने वाले शुल्क पर ऑडिटरों की निर्भरता के नाते उनके हितों को खतरा रहता है
- स्व-मूल्यांकन ऑडिटरों की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है अगर वे उसी फर्म में दूसरों के किए काम या खुद अपने काम को ऑडिट कर रहे हैं
- जब कोई ऑडिटर ग्राहक को इस हद तक प्रोत्साहित करता है कि उसकी वस्तुनिष्ठता भी संदिग्ध हो जाती है तो उसकी सलाह खतरे की जद में आ जाती है
- अगर ऑडिटर अपने ग्राहक के कर्मचारियों, अधिकारियों या निदेशकों को नजदीक से जानता है या लंबे समय तक कारोबारी रिश्ता रखता है तो पहचान-जनित खतरा पैदा हो जाता है
- अगर ऑडिटर को कंपनी प्रबंधन या उसके निदेशकों की तरफ से डराया-धमकाया जाता है तो स्वतंत्र ऑडिट की अवधारणा को खतरा पैदा हो जाता है

स्रोतः ऑडिट की स्वतंत्रता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा लाया गया विमर्श पत्र

इस महीने की शुरुआत में ऑडिट व्यवसाय की स्वनियामक संस्था भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) का दिल्ली में 70वां वार्षिक समारोह आयोजित हुआ था जिसमें देश भर से आए सैकड़ों पेशेवरों एवं छात्रों ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की तरफ से हाल ही में जारी एक परामर्श पत्र ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। दरअसल इस परामर्श पत्र से ऑडिटरों की आजादी और जवाबदेही को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं।

पिछले वर्षों में तमाम जानकार ऑडिटरों की जवाबदेही बढ़ाने की बात करते रहे हैं। इस बार कंपनी मंत्रालय के परामर्श पत्र में इस मुद्दे को अधिक कड़ाई से उठाया गया है। इसके मुताबिक, 'हाल के समय में आईएलऐंडएफएस जैसे मामलों में ऑडिटरों की नाकामी के कई वाकये देखे गए हैं। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्टों की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में आई हैं। अधिकांश मामलों में ऑडिटर कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर काम करते नजर आते हैं लिहाजा उनकी स्वतंत्रता एवं जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े होते हैं।'

देश की चार बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, 'असल में इस परामर्श पत्र का लहजा चिंता की बात है। इसकी भाषा भी आरोप मढ़ने वाली है।'

आईसीएआई ने इस परामर्श पत्र का स्वागत करने के साथ ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बना दी है। लेकिन इस समिति के सुझावों पर ऑडिट जगत में आम सहमति बना पाना काफी मुश्किल होगा।

परामर्श पत्र में रखे गए विभिन्न प्रस्तावों में से दो का असर छोटी एवं बड़ी दोनों तरह की ऑडिट एवं सलाहकार फर्मों पर पड़ेगा। पहला प्रस्ताव बिग 4 श्रेणी वाली ऑडिट फर्म के ग्राहकों की संख्या की अधिकतम सीमा तय करने का है। दूसरा प्रस्ताव ऑडिट ग्राहकों को दी जाने वाली गैर-ऑडिट सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने का है।

मंत्रालय ने इस परामर्श पत्र के जरिये घरेलू बाजार में ऑडिट कार्यों की आर्थिक संकेंद्रता और 'प्रतिस्पर्द्धा के अपर्याप्त स्तर' को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। ऐसा ऑडिट एवं लेखा क्षेत्र की बिग 4 फर्मों के अल्पाधिकार की वजह से है।

परामर्श पत्र के मुताबिक इस स्थिति से निपटने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, एक समूह की ऑडिटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले फर्मों की संख्या तय की जाए और दूसरा, घरेलू ऑडिट फर्मों को फलने-फूलने का मौका दिया जाए ताकि बिग 4 फर्मों पर उद्योग जगत की निर्भरता कम हो सके।

मौजूदा व्यवस्था के तहत एक ऑडिट फर्म 20 से अधिक कंपनियों के खातों का अंकेक्षण नहीं कर सकती है। लेकिन बड़ी ऑडिट फर्में स्थानीय फर्मों के साथ साझेदारी कर लेती हैं और उनके नाम का इस्तेमाल कर अधिक कंपनियों की ऑडिट करने लगती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि निफ्टी में सूचीबद्ध कंपनियों में से 70 फीसदी से भी अधिक कंपनियों का अंकेक्षण बिग 4 फर्मों से जुड़ी इकाइयां करती हैं। यह आंकड़ा प्राइम डेटाबेस का है। कंपनी मंत्रालय का विमर्श पत्र कहता है कि ऐसी स्थिति में ऑडिट की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाता है। यह समूची स्थिति बताती है कि एक समूह से जुड़ने वाली ऑडिट फर्मों की संख्या तय करने की जरूरत है। इसके अलावा एक फर्म में साझेदारों की संख्या भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर आवंटन हो सके।

बिग 4 फर्मों के आकार एवं असर को लेकर ऑडिट जगत में काफी चिंताएं देखी जाती रही हैं लेकिन आम धारणा यही है कि किसी फर्म को उसके आकार की वजह से दंडित करना अनुचित है। बिग 4 में शामिल एक अंकेक्षण एवं लेखा फर्म के पूर्व प्रमुख कहते हैं, 'आर्थिक संकेंद्रण को दुरूस्त करने के लिए बड़े आकार की कई ऑडिट फर्मों की जरूरत है न कि इनका आकार छोटा करना चाहिए।' उनका कहना है कि अगर कोई ऊपरी सीमा रखी जाती है तो वह केवल संक्रमणकालीन उपाय ही होना चाहिए।

अधिकतर ऑडिटर इस बात पर एकमत हैं कि छोटी एवं मझोले आकार की ऑडिट फर्मों को बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। खुद आईसीएआई भी अपनी सदस्य ऑडिट फर्मों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के बारे में सोच रहा है ताकि छोटे एवं मझोले आकार की फर्मों को एक दूसरे के साथ काम करने और आगे चलकर विलय के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आईसीएआई की नियामक परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य कहते हैं, 'हम संदेश प्रसारित करना चाहते हैं कि ऑडिट फर्मों को सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) ढांचे की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए।'

ऑडिट क्षेत्र से जुड़े कई सदस्यों का मानना है कि ऑडिट ग्राहकों को गैर-ऑडिट सेवाएं देने पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा छोटी फर्मों को चोट पहुंचाएगा। अधिकांश ऑडिट फर्में ऑडिट सेवाओं का पूरा पैकेज मुहैया कराती हैं जिनमें कर सलाह और उनके ग्राहकों की अनुपालन संबंधी जरूरतों का ख्याल रखना भी शामिल है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के इस विमर्श पत्र में रखी गई सोच को ध्यान में रखते हुए दो बड़ी ऑडिट फर्मों- ग्रांट थॉर्नटन इंडिया और पीडब्ल्यू इंडिया ने यह फैसला किया है कि वे अपने ऑडिट ग्राहकों को इतर सेवाएं नहीं देंगी। ब्रिटेन को छोड़कर कोई भी दूसरा देश ऑडिट ग्राहकों को गैर-ऑडिट सेवाएं देने पर रोक नहीं लगाता है।

कंपनी मामलों के वकील एस एल श्रीराम का सुझाव है कि मंत्रालय को आदर्श रूप में ऑडिट सेवाओं की गुणवत्ता के मानक तय करने चाहिए और हरेक ऑडिट कार्य में लगने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित कर देनी चाहिए।

हेल्थकेयर क्षेत्र में अस्पताल कंपनियां सुरक्षित दांव

बाजार को इन कंपनियों की आय में अच्छी तेजी आने का अनुमान है, क्योंकि इनमें विकास से संबंधित संभावनाओं और लागत नियंत्रण उपायों का असर दिखना शुरू हो गया है

उज्ज्वल जौहरी

भले ही हेल्थकेयर क्षेत्र में अन्य सेगमेंट का प्रदर्शन शेयर बाजार पर कमजोर रहा हो, लेकिन अस्पताल कंपनियों ने अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, नारायणा हृदयालय और एस्टर डीएम ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अच्छी तेजी दर्ज की है और ये शेयर अपनी अल्पावधि ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं।

कोरोनावायरस की वजह से आई वैश्विक मंदी के जोखिम से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा है और ऐसी स्थिति में अस्पताल कंपनियों के शेयर सुरक्षित दांव बने हुए हैं। इन कंपनियों में विकास की रफ्तार बरकरार रहने और मुनाफे में सुधार आने की संभावना है। ऐक्सिस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि अस्पताल अब परिचालन में सुधार की वजह से नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिहाज से ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। बेहतर उत्पाद और लागत नियंत्रण से भी स्थिति में बदलाव आया है। विश्लेषकों का कहना है कि बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लिए, आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन का सीमित प्रभाव पड़ा है, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए, इससे उनकी पैठ बढ़ेगी।

इस क्षेत्र में सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स अपने अस्पताल तथा फार्मेसी व्यवसायों की मदद से शानदार प्रदर्शन करने में सफल रही है। इस कंपनी को गिरवी शेयरों में कमी लाए जाने से भी मदद मिली है। विस्तार के दौर से गुजर रही यह कंपनी अब प्रमुख परिचालन से मार्जिन वृद्धि का फायदा हासिल कर रही है और उसे नए अस्पतालों से भरपाई की स्थिति में आने में भी मदद मिल रही है।

दिसंबर तिमाही के दौरान समेकित परिचालन लाभ विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर रहा और यह सालाना आधार पर 27 प्रतिशत (आईएनडी एएस 116 लेखा मानकों के समायोजन) तक बढ़ा। विश्लेषकों का कहना है कि इसे मुख्य तौर पर नए अस्पतालों में वृद्धि, अन्य सेगमेंट के मजबूत प्रदर्शन से मदद मिली। नवी मुंबई के अस्पताल का विस्तार किया गया है और अगले साल से इससे अच्छा योगदान हासिल होने का अनुमान है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि हेल्थकेयर क्षेत्र में बिक्री वित्त वर्ष 2019-22 के दौरान सालाना 12 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

नई फार्मेसी जुड़ने और कमजोर प्रदर्शन वाली फार्मेसी को सही समय पर बंद किए जाने से पिछले पांच साल में फार्मेसी व्यवसाय (वित्त वर्ष 2019 के राजस्व में 40 प्रतिशत योगदान) सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इस सेगमेंट का राजस्व 800 आधार अंक की मार्जिन वृद्धि के साथ पहले 9 महीनों में 20.7 प्रतिशत बढ़ा। इलारा कैपिटल के विश्लेषकों को दोनों सेगमेंट में लगातार तेजी के साथ वित्त वर्ष 2020-22 के दौरान सालाना 16 प्रतिशत की परिचालन मुनाफा वृद्धि का अनुमान है।

हालांकि फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए दिसंबर तिमाही कमजोर रही, लेकिन उसके लिए कई चिंताएं दूर होने से उसके अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेगमेंट दोनों के लिए मजबूत विकास परिदृश्य बरकरार है। भविष्य में लागत नियंत्रण के उपायों से हालात में सुधार आने का अनुमान है।

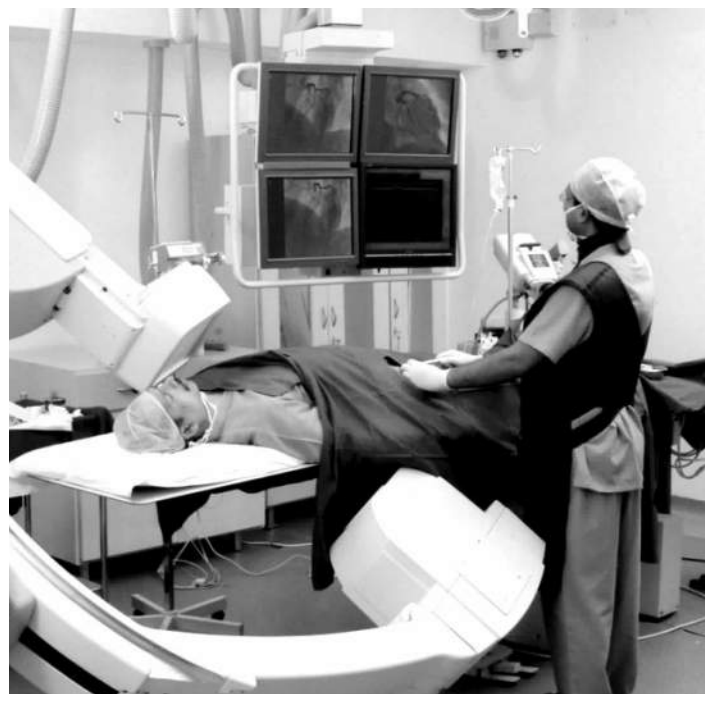

दिसंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन मुनाफा मार्जिन सालाना आधार पर 200 आधार अंक बढ़कर 13 प्रतिशत पर रहा और इसे लागत घटाने के उपायों से मदद मिली।

कंपनी ने वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान विस्तार बरकरार रखा और लगभग 180 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया। कंपनी के लिए प्रमुख सकारात्मक कारकों में अस्पताल में आने वाले मरीजों की दर में सुधार मुख्य रूप से शामिल है। विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी ने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और ऑनकोलॉजी जैसी स्पेशियलिटीज को शामिल किया है। कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020 में बड़ी लागत बचत किए जाने की संभावना है और उसे अगले चार वर्षों के दौरान 1,200-1,300 बिस्तरों के जुड़ने से भी मदद मिलेगी। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने हाल में कंपनी के लिए अपने 12 के कीमत लक्ष्य को पहले के 150 रुपये से बढ़ाकर 176 रुपये किया है।

विश्लेषकों का मानना है कि नारायणा हृदयालय ने पिछली चार-पांच तिमाहियों के दौरान मजबूत परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया है, जो आगे भी बरकरार रहने की संभावना है। दिसंबर तिमाही में भी कंपनी के परिचालन लाभ में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, भले ही बाहरी मरीजों का प्रवाह सीएए विरोध प्रदर्शनों की वजह से धीमा रहा। अपने धरमशिला हॉस्पिटल के भरपाई की स्थिति में आने से कंपनी को गुरुग्राम और मुंबई अस्पतालों के भी वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 तक भरपाई की स्थिति में आ जाने की संभावना है। कंपनी ने कम मुनाफे वाले केंद्रों पर परिचालन लागत में कमी (व्हाइटफील्ड, बेंगलूरु हॉस्पिटल और दुर्गापुर में एक केंद्र को बंद किया है) की है। हालांकि वह वित्त वर्ष 2020-22 के दौरान अपने मौजूदा केंद्रों पर 150-200 बिस्तर जोड़ रही है। इलारा कैपिटल के विश्लेषकों को वर्ष 2020-22 के दौरान परिचालन लाभ 20 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

एस्टर डीएम भी 15 प्रतिशत की मजबूत बिक्री वृद्धि की उम्मीद जता रही है, जबकि उसका परिचालन मुनाफा अगले कुछ वर्षों के दौरान 27 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि जीसीसी अस्पतालों (पश्चिम एशिया परिचालन) में मजबूत बिक्री वृद्धि और भारत में अस्पताल व्यवसाय में तेजी पर निर्भर करेगी।

बाजार हलचल

आईपीओ के लिए एसबीआई पर नजर

कारोबारियों ने एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज के आईपीओ के वास्ते शेयरधारक कोटे में शेयरों के लिए आवेदन करने की योजना बनाई है। ब्रोकरों का कहना है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी में अपनी किस्मत आजमाने वाले कई कारोबारियों ने हाल के सप्ताहों में पैतृक कंपनी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के शेयर खरीदे हैं। इस आईपीओ में लगभग 1.3 करोड़ शेयर (900 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य) एसबीआई शेयरधारकों के लिए आरक्षित हैं। अक्सर, खुदरा बुक से शेयरधारक बुक की तुलना में ज्यादा सदस्यता का संकेत मिलता है, इसलिए शेयरधारक बुक के जरिये शेयर मिलने की संभावना ज्यादा है। शेयरधारक श्रेणी में आवेदन के लिए आखिरी तारीख पिछले सप्ताह समाप्त हो गई। ग्रे बाजार के कारोबारियों का कहना है कि एसबीआई कार्ड्स का शेयर 30 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। *– समी मोडक*

ईएसजी फंडों को नियम संहिता से मदद

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित नियम संहिता से ईएसजी फंडों को राहत मिल सकती है। ये फंड परिवेश, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) मानकों पर आधारित कंपनियों में निवेश करते हैं। एक फंड हाउस के मुख्य निवेश अधिकारी ने कहा, 'नियम संहिता ने म्युचुअल फंडों को निवेश से संबंधित कंपनियों में ईएसजी जोखिमों का आकलन करना अनिवार्य बनाया है।' फंड हाउसों को कंपनियों द्वारा अपनाए जा रहे ईएसजी मानकों पर नजर रखने के लिए एक ढांचा तैयार करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, 'धीरे धीरे फंड हाउस ईएसजी फंडों के प्रबंधन के लिए मजबूत आधार तैयार करने में सक्षम होंगे।' जहां ऐक्सिस एमएफ ने ईएसजी फंड पहले ही पेश कर दिया है, वहीं बिड़ला सनलाइफ एमएफ ने इसके लिए सेबी के साथ आवेदन किया है। – जश कृपलानी

निफ्टी में उतार-चढ़ाव घटने के आसार

नए बदलाव के बाद निफ्टी सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ हद तक घटने का अनुमान है। सितंबर में, 50 शेयर वाले इस सूचकांक में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस की जगह नेस्ले इंडिया को शामिल किया गया और अगले महीने श्री सीमेंट को येस बैंक की जगह शामिल किया जाएगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग और येस बैंक दोनों के शेयरों में अस्थिरता बनी रही जबकि नेस्ले इंडिया और श्री सीमेंट इस अनिश्चितता से दूर रहे। नेस्ले इंडिया का शेयर मौजूदा समय में 16,500 रुपये पर कारोबार कर रहा है जबकि श्री सीमेंट का शेयर 24,400 रुपये पर है। ये दोनों शेयर निफ्टी सूचकांक में प्रति शेयर आधार पर काफी महंगे हैं। *– समी मोडक*

पीरामल एंटरप्राइजेज पर थोक ऋणों से पड़ रहा दबाव

हंसिनी कार्तिक

कैलेंडर वर्ष 2019 में पीरामल एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 30 प्रतिशत लुढ़का और 2018 के मुकाबले इसका कारोबार लगभग सपाट रहा। हालांकि 1,531 रुपये पर इसका मूल्यांकन वित्त वर्ष 2021 के अनुमानित खाते के 1.1 गुना स्तर पर किया गया है, जो खासा आकर्षक है। अब सवाल यह है कि क्या यह खाते की गुणवत्ता को उचित तरीके से दर्शा पा रहा है।

मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर, 2019 तक इसके खाते में कुछ आवंटित ऋणों में थोक ऋण की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत थी, जबकि 47 प्रतिशत आवंटन थोक आवासीय रियल एस्टेट परियोजनाओं और 23 प्रतिशत थोक वाणिज्यिक रियल एस्टेट में किए गए थे। अपनी सूचीबद्ध प्रतिस्पर्द्धियों के मुकाबले मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर पीरामल के ये आंकड़े सहज नहीं माने जा सकते हैं। इसकी प्रतिस्पर्द्धी कंपनियां थोक ऋणों में 25 प्रतिशत से नीचे परिचालन कर रही हैं।

पीरामल एंटरप्राइजेज के वित्तीय सेवा कारोबार की कंपनी के राजस्व में करीब आधी हिस्सेदारी है, लेकिन हाल में ही कंपनी ने नए शेयर जारी कर करीब 3,650 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इन ऋणों का असर परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दिसंबर तिमाही में खास तौर पर दिखा। क्रमागत आधार पर तीसरी तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) लगभग दोगुनी होकर 1.8 प्रतिशत हो गईं, जबकि कमजोर परिसंपत्तियों का अनुपात वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया।

पीरामल एंटरप्राइजेज कई तरह के उपाय कर रही है। इनमें किसी एक खंड या एक ग्राहक को आवंटित ऋणों की मात्रा में कमी, सिक्योरिटाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा और खुदरा खंड में उपस्थिति बढ़ाना शामिल है। हालांकि इन उपायों का असर कंपनी के ऋण खातों में दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। उदाहरण के लिए कंपनी ने खुदरा ऋण की हिस्सेदारी दिसंबर 2018 में 7 प्रतिशत से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 12 प्रतिशत कर दी है।

आवास ऋण के अलावा कंपनी कंज्यूमर फाइनैंस (उपभोक्ता ऋण) कारोबार को भी मजबूत कर रही है। कंपनी की प्रतिस्पर्द्धी एचडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग की खुदरा ऋण में क्रमश: 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इस लिहाज से पीरामल को इस खंड में उपस्थिति बढ़ाने के लिए काफी काम करना होगा। विश्लेषकों का कहना है कि इससे पीरामल एंटरप्राइजेज और एडलवाइस फाइनैंशियल सर्विसेस के शेयरों के प्रति निवेशकों के घटते रुझान को भी दर्शाता है। इन दोनों कंपनियों का ऋण खाता थोक कारोबार पर अधिक केंद्रित है। विश्लेषकों और प्रमुख ब्रोकरेज कंपनियों में पीरामल एंटरप्राइजेज के शेयर को लेकर अधिक उत्साह नहीं दिखा है। हालांकि मोतीलाल फाइनैंशियल सर्विसेस शेयर खरीदने की सलाह दे रही है।

येस सिक्योरिटीज के राजीव मेहता के अनुसार ढांचागत जोखिम शेयर कीमतों में पूरी तरह नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर मांग और परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर अनिश्चितता इन दोनों चुनौतियों की वजह से रियल एस्टेट खंड पर केंद्रित एनबीएफसी कंपनियों के प्रति जोखिम की धारणा कम नहीं हुई है। इसी वजह से पीरामल एंटरप्राइजेज के लिए रकम जुटाना महंगा साबित हो रहा है। तीसरी तिमाही में कंपनी के लिए कोष जुटाना 11 प्रतिशत तक महंगा हो गया, जो सितंबर तिमाही के स्तर के बराबर ही है। कंपनी फिलहाल बढ़ी लागत का बोझ थोक ग्राहकों पर लाद रही है, जिससे इसे तीसरी तिमाही में औसत प्राप्ति 14.9 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रखने में मदद मिली। हालांकि कंपनी यह स्तर आगे भी बरकरार रख पाएगी या नहीं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। निवेशकों के लिहाज से मूल्यांकन अपेक्षाकृत आकर्षक जरूर है, लेकिन जोखिम भी अधिक है। यह बात पर बाजार की नजर होगी कि आने वाली तिमाही में कंपनी का थोक ऋण किस दिशा मं आगे बढ़ता है।

तेल में नरमी से कंपनियों को मदद

उज्ज्वल जौहरी

कच्चे तेल में कमजोरी बनी हुई है क्योंकि चीन में कोरोनावायरस के प्रभाव से वैश्विक मांग पर नकारात्मक असर दिख सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए इंटरनैशनल एनर्जी एजेंसी ने तेल मांग को लेकर अपना अनुमान घटा दिया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) ने 2020 की वैश्विक तेल मांग वृद्धि के लिए अपने अनुमान को कुछ दिन पहले 9.9 लाख बैरल प्रतिदिन तक घटा दिया।

अमेरिका के हाथों बाजार भागीदारी खोने की आशंका को देखते हुए भले ही मांग वृद्धि का अनुमान घटा दिया गया है, लेकिन ओपेक उत्पादन कटौती पर विचार नहीं कर सकता है जिससे तेल कीमतें कमजोर बनी रह सकती हैं। यह परिदृश्य हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) जैसी तेल विपणन कंपनियों के लिए सकारात्मक है।

तेल कीमतों में नरमी से भारत की प्रमुख ईंधन विक्रेता कंपनियों को अपनी कार्यशील पूंजी जरूरतें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपने विपणन मार्जिन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। कच्चे तेल की कीमत 2020 के शुरू में 69 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं, जो अब 59-60 डॉलर प्रति बैरल पर हैं और भविष्य में कमजोर बने रहने की संभावना है।

पिछले एक महीने के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बाजार धारणा प्रभावित हुई है क्योंकि सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) परिदृश्य भी कमजोर बना हुआ है।

आईओसी और एचपीसीएल के शेयरों में भी 2020 के शुरू से अब तक 11-18 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। कंपनी के निजीकरण की सरकार की योजना की वजह से बीपीसीएल काफी हद तक स्थिर (सिर्फ 4 प्रतिशत की गिरावट) बना रहा। हालांकि विश्लेषक इस शेयर में अवसर देख रहे हैं।

आईओसी और बीपीसीएल को कम कार्यशील पूंजी जरूरत और मजबूत विपणन मार्जिन से भी बढ़त मिली है, लेकिन कमजोर जीआरएम से यह बढ़त कमजोर साबित हो सकती है

भले ही अंतरराष्ट्रीय तेल मांग और कीमतें कमजोर बनी रह सकती हैं, लेकिन विश्लेषकों को भारत से मजबूत मांग की उम्मीद है। विश्लेषकों को ओएमसी के लिए मजबूत विपणन मार्जिन की उम्मीद है। विश्लेषकों को देश में मध्यावधि के दौरान 4-5 प्रतिशत की तेल मांग वृद्धि बरकरार रहने की संभावना है।

तेल कीमतों में कमजोरी के बीच तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और केरोसिन की कीमतों में बदलाव से मदद मिल सकती है और सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र में नुकसान से बच सकती है।

ओएमसी में एचपीसीएल एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नीलेश घुघे जैसे विश्लेषकों का पसंदीदा बना हुआ है। आईओसी और बीपीसीएल भी अपने विपणन व्यवसाय में वृद्धि दर्ज करेंगी और कार्यशील पूंजी के मोर्चे पर इनकी आय रिफाइनिंग मार्जिन में तेजी पर निर्भर है।

एचपीसीएल अपना 50 प्रतिशत से ज्यादा परिचालन लाभ तेल विपणन व्यवसाय से प्राप्त करती है जिससे मौजूदा कमजोर जीआरएम परिवेश में उसकी आय को मदद मिल सकती है। 222. रुपये पर, यह शेयर अपने ऐतिहासिक पांच वर्षीय औसत के मुकाबले 35 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है। 1.3 गुना के 2021-22 के अनुमानित पी/बी वैल्यू मल्टीपल के साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों ने इस शेयर के लिए 340 रुपये का कीमत लक्ष्य रखा है। वहीं एडलवाइस और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का कीमत लक्ष्य 322 रुपये और 315 रुपये पर है जिससे एचपीएलसी के लिए अच्छी तेजी का संकेत मिलता है।

आईओसी के लिए, मुख्य रिफाइनिंग मार्जिन, बीएस-6 अपग्रेड के लिए हल्दिया और मथुरा रिफाइनरियों में कामकाज बंद रहने और कमजोर पेट्रो रसायन मूल्य निर्धारण परिदृश्य अल्पावधि चिंताएं बनी हुई हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान, हल्दिया और मथुरा में बीएस-6 की वजह से परिचालन बंद रहने से आईओसी का रिफाइनिंग मार्जिन सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत तक घटा। हालांकि इन्वेंट्री बढ़ने से रिफाइनिंग मार्जिन को कुछ मदद मिली, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है कि लेकिन मार्च तिमाही में कंपनी इन्वेंट्री नुकसान दर्ज कर सकती है। कमजोर पेट्रो रसायन कीमत परिदृश्य भी प्रेरक नहीं है। हालांकि शेयर में कुछ सुधार देखा जा सकता है और इसे आईओसी के विपणन सेगमेंट में तेजी आने से मदद मिल सकती है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि मूल्यांकन सस्ता है।

बिक्री की खबरें भी एचपीसीएल में किसी तरह की तेजी के लिए महत्त्वपूर्ण होंगी। विश्लेषकों का कहना है कि किसी बड़े निवेशक/खरीदार को सफल बिक्री से इस शेयर के लिए उनके कीमत लक्ष्य में इजाफा हो सकता है।

वीआरएस से हुई सरकारी दूरसंचार कंपनियों की सेवा प्रभावित

पृष्ठ 1 का शेष

असल में, एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों के ही अधिकारियों का दावा है कि उनका परिचालन पहले जैसा ही चल रहा है। वीआरएस लेने वाले बीएसएनएल कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा यानी 55,000 कर्मचारी निचले स्तर पर तैनात थे। एमटीएनएल के भी मामले में गैर-कार्यकारी श्रेणी वाले कर्मचारी ही वीआरएस लेने में सबसे आगे हैं।

इस बारे में पूछे जाने पर पुरवार ने कहा, 'हमारी कंपनी में सभी स्तर के कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति योजना चुनी है। इस योजना का विकल्प रखते समय हमने कोई भी कैडर-आधारित भेद नहीं किया था।' इस योजना की इकलौती शर्त यही थी कि कर्मचारी की उम्र आवेदन करते समय 50 साल से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी आवेदन को खारिज नहीं किया गया है।

वैसे राज्य स्तर के अधिकारी वास्तविकता के अधिक करीब नजर आए। मसलन, बीएसएनएल के गुजरात सर्किल में कॉर्पोरेट ऑफिस से मिले निर्देशों के बाद आउटसोर्स साझेदारों की तलाश के लिए निविदा जारी किए जा रहे हैं। गुजरात के करीब 10,000 कर्मचारियों में से 6,468 ने वीआरएस का विकल्प चुना था जिसके बाद सर्किल में महज 3,532 नियमित कर्मचारी ही रह गए हैं।

गुजरात सर्किल के अधिकारी ने कहा, 'हम अपनी सेवाएं बेहतर करने पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन भावी निवेश को लेकर कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है। आउटसोर्स किए गए साझेदार लैंडलाइन कनेक्शनों के लिए हमारी कॉपर लाइन को संभालेंगे। इसकी वजह यह है कि वीआरएस लेने वाले अधिकतर कर्मचारी ग्रुप-सी के थे जो इन लाइंस की देखरेख करते थे।' इसके साथ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का रखरखाव भी आउटसोर्स किया जा सकता है।

कुछ ऐसा ही हाल बीएसएनएल के हैदराबाद स्थित कार्यालयों का है। वीआरएस योजना के बाद कामकाज संभालने में जुटे अधिकारियों ने दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्राहक सेवा कामों में लगा दिया है। वहां के एक अधिकारी कहते हैं, 'ग्राहक सेवा केंद्रों में तैनाती और खामियों को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी कोशिश यह है कि इस मुश्किल वक्त में कम-से-कम गतिरोध पैदा हो। आउटसोर्सिंग के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया उन्नत चरण में है।' उधर चेन्नई शहर और आसपास के करीब 200 से अधिक एक्सचेंज में से 33 एक्सचेंज में 1 फरवरी के बाद शायद ही कोई स्टाफ बचा है। राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सी के मथीवनन कहते हैं, 'हमारी यूनियन को कर्मचारियों के लिए तत्काल यहां के प्रबंधन से बात करनी पड़ी ताकि ये एक्सचेंज पूरी तरह बंद न हो जाएं।'

कर्मचारियों की कमी का असर बीएसएनएल की अनुषंगी इकाइयों पर भी देखा जा रहा है। दामोदर घाटी निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी भानु किरण चक्रवर्ती कलकत्ता टेलीफोन की सेवा गुणवत्ता में आई गिरावट से खासे परेशान हैं। राष्ट्रीयकृत इकाइयों के पक्षधर रहे चक्रवर्ती इस लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल 1972 से ही कर रहे हैं। लेकिन पिछले दो साल में वॉयस कॉल के साथ ही डेटा स्पीड की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है।

अनुबंधित श्रम पर निर्भरता

उत्तर प्रदेश (जहां कुछ सेवाओं को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया गया) में बीएसएनएल के एक अधिकारी ने कहा कि श्रम संकट गंभीर था। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के शेष स्टाफ को अब एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। राज्य में दो सर्किलों – उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में कर्मचारियों की संख्या 6,900 से घटकर लगभग 3,300 रह गई है और वहां मोबाइल फोन आधार 1.6 करोड़ पर अनुमानित है। वीआरएस के बाद भी उत्तर प्रदेश में जहां मोबाइल ग्राहक आधार बना हुआ है, वहीं लैंडलाइन सेवाओं को कर्मियों की संख्या में अचानक कमी होने सक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि कुछ केंद्र संविदा कर्मचारियों की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इन दोनों कंपनियों के विलय की कोशिश लंबे समय से हो रही है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों के विरोध की वजह से इस दिशा में सफलता नहीं मिली है।

वीआरएस पैकेज

अक्टूबर 2019 में दीवाली से कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विलय के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी। इस पैकेज में 15,000 करोड़ रुपये का सॉवरिन बॉन्ड भी शामिल था। इस बॉन्ड के लिए ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी इन दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों की थी।

बीएसएनएल और एमटीएनएल को 2016 की नीलामी मूल्य पर 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा और इन दोनों कंपनियों की रियल एस्टेट संपत्तियों को भुनाया जाएगा। इस योजना के विस्तृत ब्योरे को दोनों कंपनियां अंतिम रूप देंगी। संपत्ति का मुद्रीकरण और 4जी स्पेक्ट्रम की प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है।

वीआरएस पैकेज में सरकार ने 17,169 करोड़ रुपये को मुआवजे के तौर पर और 12,768 करोड़ रुपये पेंशनरों के लाभ के लिए मंजूर किए हैं। सरकार की योजना एमटीएनएल और बीएसएनएल की 37,500 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां का मुद्रीकरण तीन वर्षों में करने की है ताकि बकाया चुकाने, बॉन्ड का ब्याज देने, नेटवर्क का उन्नयन, विस्तार और परिचालन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाया जा सके। इन संपत्तियों में जमीन, भवन का किराया और पट्टा शामिल हैं। अकेले दिल्ली में एमटीएनएल के करीब 29 खुदरा आउटलेट हैं। वास्तविकता यह है कि ऐतिहासिक तौर पर निजी दूरसंचार कंपनियां अपने कर्मचारियों पर कुल खर्च का करीब 5 से 10 फीसदी रकम खर्च करती रही हैं जबकि बीएसएनएल और एमटीएनएल के मामले में यह आंकड़ा करीब 70 फीसदी है। ऐसे में इन दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों पर वीआरएस से उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों की संख्या कुछ महीने पहले 1,98,000 थी जो घटकर अब लगभग आधी रह गई है।

(साथ में अहमदाबाद से विनय उमरजी, कोलकाता से अभिषेक रक्षित, चेन्नई से गिरीश बाबू, हैदराबाद से दशरथ रेड्डी और लखनऊ से वीरेंद्र रावत)

तकनीक से घर पहुंच रही ताजी तरकारी

निंजाकार्ट किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं को एक मंच पर लाने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग कर रही है और रोजाना 1,400 टन ताजे फल-सब्जियां घरों तक पहुंचा रही

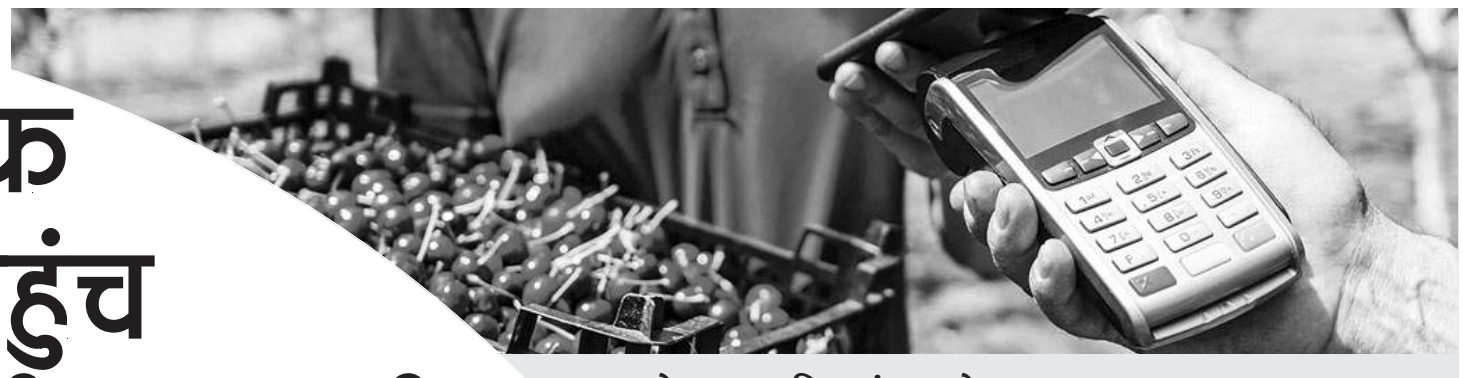

पीरजादा अबरार

अगली बार जब आप पड़ोस की दुकान से ताजी सब्जियां तथा फल खरीदेंगे तो इस बात की काफी संभावना है कि वे दूर स्थित किसी फार्म से बेंगलूरु स्थित आपूर्ति श्रृंखला आधारित तकनीकी फर्म की मदद से 12 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंचा दिए गए हों। इस कंपनी का नाम है निंजाकार्ट, जो बिग डेटा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मोबाइल ऐप्लिकेशंस तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि नवीन तकनीकों के माध्यम से कंपनी द्वारा विकसित सप्लाई चेन एल्गोरिद्म का उपयोग करती है।

निंजाकार्ट देश भर में 200 से अधिक संग्रह केंद्रो तथा 1,200 गोदामों के एक नेटवर्क के माध्यम से किसानों तथा खुदरा विक्रेताओं को जोड़ती है। यह प्रति दिन 1,400 टन से अधिक ताजे फल एवं सब्जियां लेती है और पिछले चार महीनों में यह मात्रा दोगुनी हो गई है। निंजाकार्ट के सह-संस्थापक तथा मुख्य कार्याधिकारी टी. नागराजन कहते हैं, 'प्रौद्योगिकी हमारे काम में अहम भूमिका निभाती है अन्यथा इस पैमाने पर यह काम करना संभव नहीं होगा। प्रत्येक प्रक्रिया तथा कार्रवाई को प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।' वह कहते हैं, 'आप हर मिनट कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते। सभी को ऐप दिया गया है और उन्हें ऐप में दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है।'नागराजन ने खाद्य वितरण बाजार में एक दूरी को महसूस किया और पाया कि तकनीक के माध्यम से इस बाजार में मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। इसलिए साल 2015 में उन्होंने चार साथियों के साथ मिलकर मांग-आधारित किराना सामान पहुंचाने वाली कंपनी निंजाकार्ट की स्थापना की। साथ ही, उन्हें जल्द खराब होने वाले उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता की कमी का अहसास हुआ और कंपनी ने ताजे उत्पाद के लिए बी2बी मंच उपलब्ध कराया।

निंजाकार्ट की पेपररहित आपूर्ति श्रृंखला ने सात शहरों में विस्तारित इसके 44,000 किसान आपूर्तिकर्ताओं तथा 60,000 किराना स्टोर एवं रेस्त्रां के बीच निर्बाध तंत्र विकसित किया। इन शहरों बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई तथा पुणे शामिल हैं। निर्बाध तंत्र तथा दक्षता के चलते खेत से दुकान तक सामान पहुंचने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है।

कंपनी का दावा है कि आपूर्ति श्रृंखला में 100 प्रतिशत पारदर्शिता के साथ साथ खाद्य अपशिष्ट को भी कम करके एक प्रतिशत पर ला दिया है जबकि किसी सामान्य खाद्य श्रृंखला में 35 प्रतिशत तक अपशिष्ट होता है। तकनीक के उपयोग से कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि फल एवं सब्जियां अपनी नमी न खोएं, वरना उनके वजन में भी कमी हो जाती है।

कंपनी में 4,000 से अधिक कर्मी काम करते हैं और करीब 700 वाहन सामान की डिलिवरी करते हैं। कंपनी देशभर के गांव से ताजे उत्पाद इकट्ठा करती है। 'फार्म हार्वेस्ट कैलेंडर' के अध्ययन के बाद कंपनी प्रत्येक सीजन में फल तथा सब्जियों की उपलब्धता की जानकारी जुटाती है। यह ग्राहकों द्वारा खरीदे गए सामान, उनकी संख्या तथा दूसरे आंकड़ों का भी अध्ययन करती है, जिससे आगामी सीजन में मांग का अंदाजा लगाया जा सके। इससे कंपनी को मांग तथा आपूर्ति की सही जानकारी मिलती है।

> कंपनी का दावा है कि पिछले दो वर्षों में किसानों की आय में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ

उत्पाद सेंटर तक आने के बाद इसे टोकरियों तथा कलेक्शन सेंटर में रखा जाता है। फल तथा सब्जियों का वजन करके उनमें संबंधित टैग लगाए जाते हैं। इसके बाद कुल आपूर्ति, कीमत तथा कुल राशि का एक संदेश किसान के मोबाइल पर भेज दिया जाता है तथा अगले ही दिन कुल राशि किसान के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। निंजाकार्ट ने कई नए तरीकों को भी अपनाया है। जैसे, टोकरी उतारने-चढ़ाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करना। इससे काम में तेजी आई है। टोकरी को डिलिवरी वाहन में रख दिया जाता है, जो सुबह काफी जल्दी सामान पहुंचाने के लिए रवाना हो जाती है। ऐप के जरिये इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन किया जाता है। प्रत्येक टोकरी में एक आरएफआईडी टैग लगा होता है जिससे कंपनी को पता चलता रहे कि कौन सी सब्जी तथा फल पहुंचा दिए गए हैं।

निंजाकार्ट सामान पहुंचाने के लिए वाहन चालकों को सही रास्ता भी बताता है। इसमें जीपीएस की मदद से वाहन को ट्रैक किया जाता है जिससे आगामी डिलिवरी वाली जगह के लिए सबसे छोटा तथा सही रास्ता खोजा जा सके। किसान सहयोगियों के साथ काफी करीब से काम करने वाली निंजाकार्ट उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। यह फसल उगाने से लेकर कटाई तक जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराती है। साथ ही, किसान की फसल कटने से पहले ही उसकी कीमत तथा मांग की जानकारी साझा की जाती है।

कंपनी का दावा है कि पिछले दो वर्षों में इसने किसानों की आय में 15 प्रतिशत का इजाफा किया है। नागराजन कहते हैं, 'हम एक बिक्री प्वाइंट उपलब्ध कराते हैं। इसलिए किसान बिक्री की चिंता किए बिना खेती पर अधिक से अधिक ध्यान दें। किसानों की फसल की कीमत सीधे उनके बैंक खाते में आ जाती है और उन्हें भुगतान में देरी की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा होने से उन्हें कर्ज लेने में भी परेशानी नहीं आएगी।' निंजाकार्ट ने अभी तक टाइगर ग्लोबल, एस्सेल, नंदन नीलेकणी समेत विभिन्न निवेशकों से 15 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। दिसंबर 2019 में विश्व की सबसे बड़ी रिटेल चेन वॉलमार्ट ने भी निंजाकार्ट में रणनीतिक निवेश की घोषणा की। नागराजन कहते हैं, 'ताजा भोजन 130 अरब डॉलर का बाजार है। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय ग्राहकों द्वारा खरीदे जाने वाली सब्जियों तथा फलों के बाजार में निंजाकार्ट अहम भूमिका का निर्वहन करे। यह इस लक्ष्य को सार्थक बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं।'

ताजे फल-सब्जियां आपके द्वार

- निंजाकार्ट देश के सबसे दूर के गांव से भी 12 घंटे में ताजे फल-सब्जियां उपलब्ध करा देती है
- कंपनी रोजाना 1,400 टन खाद्य पदार्थ का परिवहन करती है
- एल्गोरिद्म, बिग डेटा, प्रडीक्टिव एनालिसिस, मोबाइल ऐप्लिकेशंस तथा आईओटी जैसी नवीन तकनीकों का होता है इस्तेमाल
- कंपनी ने तकनीक की मदद से 44,000 किसान तथा 60,000 किराना स्टोर के बीच निर्बाध तंत्र विकसित किया
- सात प्रमुख शहरों बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई तथा पुणे में उपलब्ध हैं सेवाएं
- कंपनी का दावा, पिछले दो वर्षों में किसानों की आय में 15 प्रतिशत का हुआ इजाफा

साइबर हमलों से बचने के लिए बीमा

2017 में रैंसमवेयर हमले के बाद साइबर बीमा कवर की मांग बढ़ी

सुब्रत पांडा

भारतीय कंपनियां और संस्थाएं अपने कामकाज में डिजिटल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। इनमें से कई खुद को साइबर हमलों, डेटा चोरी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर बीमा कवर ले रही हैं।

मार्श इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स के कंट्री हेड और मुख्य कार्याधिकारी संजय केडिया ने कहा, 'शुरुआत में आईटी और आईटीईएस कंपनियों ने इस तरह की मांग आ रही थी लेकिन अब हर तरह की कंपनियां साइबर बीमा कवर ले रहे हैं। 2017 में रैंसमवेयर के हमले के बाद विनिर्माण क्षेत्र की ओर से साइबर बीमा की मांग बढ़ गई है।'

उन्होंने कहा, 'हम उम्मीद कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ ईयू का सामान्य डेटा संरक्षण कानून आने और भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की मंजूरी के बाद इसमें और तेजी जाएगी।' विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, 2019 के मुताबिक कंपनियों और संस्थाओं को डेटा की धोखाधड़ी और साइबर हमलों का बड़ा खतरा है। डेटा सुरक्षा सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी जेमाल्टो ब्रीच लेवल इंडेक्स ऐंड वैरोनिस के मुताबिक केवल भारत में 2013 से 2018 के बीच 39.4 करोड़ से अधिक डेटा रिकॉर्ड खो गए या चोरी हो गए। सिमैंटेक की इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2018 के बीच साइबर हमलों के मामले में भारत का दूसरा स्थान था।

> कंपनियों और संस्थाओं को डेटा की धोखाधड़ी और साइबर हमलों का बड़ा खतरा

उद्योग के जानकारों का कहना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के आने और फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, स्विगी, ओला और इस तरह की कई अन्य इंटरनेट आधारित कंपनियों के तेजी से बढ़ने के कारण डेटा सुरक्षा की जरूरत बहुत बढ़ गई है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रमुख (अंडरराइटिंग, दावा, पुनर्बीमा) संजय दत्ता ने कहा, 'अर्थव्यवस्थाओं के क्लाउड, ब्लॉक चेन और कृत्रिम मेधा के साथ जुड़ने से साइबर अपराध दुनिया के हर पेशे, उद्योग और कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है।' किसी भी अन्य बीमा उत्पाद की तरह साइबर बीमा एक आकस्मिक पूंजी है जो उस समय बीमाकर्ता के काम आती है जब उसे कोई नुकसान होता है। अमूमन, ये बीमा उत्पाद उपभोक्ता को डेटा के उल्लंघन, डेटा चोरी, मैलवेयर हमले आदि की स्थिति में कवर देते हैं। ऐसी पॉलिसी के तहत दूसरे कारणों से पैदा हुई देनदारी भी शामिल है। इनमें चूक, डेटा उल्लंघन, कारोबारी गोपनीयता के आंकड़ों की चोरी, अवमानना और संबंधित दुष्प्रचार शामिल है। इनमें घटना के बाद उसके प्रबंधन, जन संचार गतिविधियों, घटना से जुड़ी जांच आदि में आने वाले खर्च को भी कवर किया जा सकता है।

हालांकि साइबर बीमा श्रेणी अभी भारत में शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी अब तक की वृद्धि जबरदस्त रही है। 2014-15 में केवल एक साइबर बीमा पॉलिसी बेची गई थी। आज बीमा उद्योग 400 से अधिक साइबर बीमा पॉलिसी बेच चुका है। बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और भुगतान डेटा प्रोसेस करने वाली क्रेडिट कार्ड जैसी कंपनियों के बीच साइबर बीमा पॉलिसी की मांग बढ़ रही है। ऐसी कंपनियों पर साइबर हमले और डेटा चोरी का जोखिम अधिक रहता है। इतना ही नहीं, कई साधारण और जीवन बीमा कंपनियां भी साइबर बीमा कवर खरीद रही हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अंडरराइटिंग मैनेजर वैद्यनाथ बालासुब्रमण्यन ने कहा, 'साइबर बीमा कवर की ज्यादातर मांग आईटी और बीएफएसआई क्षेत्र से आ रही है लेकिन आईटी सॉफ्टवेयर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, बीपीओ और यूटिलिटी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं।'

> साइबर बीमा कवर की ज्यादातर मांग आईटी और बीएफएसआई क्षेत्र से आ रही है लेकिन आईटी सॉफ्टवेयर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, बीपीओ और यूटिलिटी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं
>
> **वैद्यनाथ बालासुब्रमण्यन**
> अंडरराइटिंग मैनेजर, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस

केवल कंपनियां ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर लोग भी साइबर सुरक्षा कवर ले रहे हैं। व्यक्तिगत साइबर जोखिम बीमा की मुख्य खूबियां यह है कि इनमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया हमले, डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी, जबरन वसूली आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के पास कमर्शियल साइबर नाम से एक उत्पाद है। इस पॉलिसी को किसी ऐसी कंपनी को जारी किया जा सकता है जिसके सदस्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म/वॉलेट पर ऑनलाइन लेनदेन में शामिल हैं। इसमें ये सदस्य व्यक्तिगत तौर पर बीमित होंगे। सूत्रों के मुताबिक मोबिक्विक और पेटीएम ने इस तरह की पॉलिसी ले रखी है।

लेकिन साइबर बीमा क्षेत्र को अब भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केडिया ने कहा, 'चूंकि साइबर बीमा भारत में अभी दूसरे बीमा क्षेत्रों के तरह विकसित नहीं है, इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं की इसमें सीमित दिलचस्पी है। ऐसी स्थिति में हम क्षमता के लिए विदेशी बीमा बाजारों का रुख करते हैं।'

इतना ही नहीं साइबर हमले से उपभोक्ता की संपत्ति को होने वाले नुकसान को अभी साइबर दायित्व बीमा में शामिल नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपना पहला प्रमुख डेटा संरक्षण नियम पारित करने को तैयार है। इसमें कंपनियों के व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने और इसके इस्तेमाल पर नई बंदिशें होंगी और इससे साइबर बीमा का विकल्प लेने वालों को सहूलियत होगी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बालासुब्रमण्यन ने कहा, 'पेशेवर सेवा क्षेत्रों (जैसे लीगल फर्म), विनिर्माण और मीडिया कंपनियों की तरफ से गतिविधियां बढ़ रही हैं। बाजार में क्षमता बढ़ने से हमें 3 से 5 साल में साइबर बीमा कारोबार के दोगुना होने की उम्मीद है।'

एल्गोरिद्म

डिजिटल पहल पर लगाया जा रहा दांव

डिजिटल बैंकिंग का आशय ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पिछले दशक में डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में तेज वृद्धि दर्ज की गई। विशेषकर, फिनटेक तथा नई तकनीक ला रही कंपनियां बैंकिंग सेवाओं से एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव देने के प्रयास में लगी हैं। इसके चलते पारंपरिक बैंकों के हाथ से निकलकर यह कारोबार नई कंपनियों को हाथों में चला गया, जो साल दर साल और बड़ी होती जा रही हैं। बेन ऐंड कंपनी द्वारा 22 देशों में सर्वे के बाद जारी एक रिपोर्ट 'रिटेल बैंकिंग में ग्राहक बैंकिंग रिपोर्ट' के अनुसार नई तकनीक के साथ आ रही कंपनियों में ग्राहकों का भरोसा बढ़ रहा है और इस भरोसे के चलते छोटी कंपनियां भी इधर आ रही हैं। इसके अनुसार, भारत से जवाब देने वाले 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले वर्ष पेटीएम का इस्तेमाल किया।

नई तकनीकों से समृद्ध हो रहे बैंक

- अमेरिका की नैटवेस्ट कंपनी का होम एजेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली बार घर खरीद रहे लोगों को संपत्ति का मूल्यांकन करने वालों के साथ साथ संबंधित सौदे कराने वाले, सामान पहुंचाने तथा सफाई सेवा उपलब्ध कराने वालों से जोड़ता है
- अमेरिका की कैपिटल वन कंपनी तत्काल कार खरीदने वालों को आर्थिक राशि तथा संसाधन के लिए ऑनलाइन वाहन जानकारी एवं दूसरे टूल उपलब्ध कराती है
- सिंगापुर की डीबीएस कंपनी देश में कार खरीदने के लिए विक्रेता-क्रेता आधारित सबसे बड़ा मंच उपलब्ध कराती है

अमेरिका की नैटवेस्ट कंपनी का होम एजेंट इकोसिस्टम घर संबंधी विभिन्न सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराता है

- घर की खोज, वित्तीय सुविधाएं
- जुपला पर अपना पसंदीदा घर खोजें
- वित्त सुविधाएं तथा भुगतान संबंधी कैलकुलेटर
- कर्ज आवेदनों के लिए आवेदन सुविधाएं
- होमट्रैक द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन

- सामान ले जाने की सुविधा
- ऐनीवैन द्वारा सामान पहुंचाने की सुविधा
- प्लेंटिफिक द्वारा घर की मरम्मत की सुविधा
- यूस्विच द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जरूरी सौदे
- एनीजंक द्वारा कचरा प्रबंधन की सुविधा

- वित्तीय उत्पाद एवं जानकारियां
- घर खरीदारों व विक्रेताओं के लिए खबरें, लेख
- कर्ज सेवा के लिए अतिरिक्त उधारी
- बैंक खाते
- बीमा

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुख्यधारा में शामिल हो रही फिनटेक

पिछले 12 महीनों में इन कंपनियों के मंच का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशतः

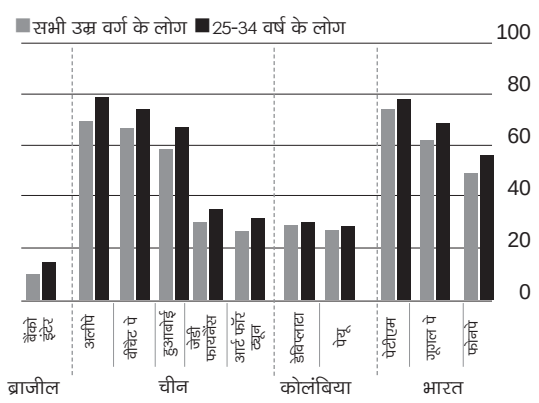

भारत में बिताए दिनों का रखें खास ध्यान

कर अधिकारियों के जाल से बचने के लिए उठाएं कदम, आपके द्वारा दिए गए ब्योरे और सरकारी रिकॉर्ड में मेल न होने पर फंस सकते हैं मुश्किल में

संजय कुमार सिंह

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में निवास के उन नियमों को बदला गया है, जिनसे व्यक्ति की आमदनी पर कर तय किया जाता है। ये नियम लागू होने के बाद हर साल भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और काम के सिलसिले में साल के काफी दिन विदेश में बिताने वाले कारोबारियों और पेशेवरों को देश में रहने के दिनों का ध्यान रखना होगा और अपने दर्जे के आधार पर अपना कर भरना होगा। ऐसा न करने पर वे आयकर प्राधिकरणों के जाल में फंस सकते हैं।

182 दिन की सीमा घटाई

निवास के नियम इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे ही यह तय होता है कि व्यक्ति पर किस तरह कर लगेगा। इस समय उस व्यक्ति को भारत का निवासी माना जाता है, जो देश में 182 दिन या उससे अधिक रहता है या एक साल में भारत में 60 दिन और पिछले चार वर्ष में कुल 365 दिन रहता है। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों शर्तों में किसी एक को भी पूरा करता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाता है। अगर कोई भारतीय नागरिक रोजगार के लिए देश से बाहर जाता है तो केवल 182 दिन की शर्त लागू होती है। उन पर 60 दिन और 365 दिन का मापदंड लागू नहीं होता है। यह नियम भारत से बाहर बसे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) पर भी भारत में आने पर लागू होता है।

बजट प्रस्ताव भारत आने वाले भारतीय नागरिकों और पीआईओ पर लागू होता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी वित्त वर्ष में 120 दिन या पिछले चार वर्षों में 365 दिन से अधिक रुकता है तो उसे कर के उद्देश्य के लिए भारत का निवासी माना जाता है।

निवास से तय होता है कर

- अनिवासियों पर भारत में केवल देश से प्राप्त आय पर कर लगता है न कि उनकी वैश्विक आमदनी पर
- आरएनओआर (भारत लौट रहे लोगों का अंतरिम चरण) पर कर उनकी भारत से होने वाली आमदनी पर लगता है न कि उनकी वैश्विक आमदनी पर
- आरओआर पर भारत से प्राप्त और वैश्विक आमदनी दोनों पर कर लगता है
- आरओआर को अपना आयकर रिटर्न भरते समय बैंक खातों और संपत्तियों जैसी विदेशी संपत्तियों के बारे में जानकारी देनी होती है
- जब व्यक्ति अपना अनिवासी का दर्जा गंवा देता है तो उसे अपने धन के प्रबंधन में बदलाव करना होता है
- आयकर दरों में बदलाव व्यक्ति के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो उसके निवास के देश पर निर्भर करता है
- कुछ यूरोपीय देशों में कर की दरें भारत से भी अधिक हैं, इसलिए व्यक्ति के भारत का निवासी बनने से फायदा होगा

यह नियम लागू होने के बाद अगर एनआरआई अपने अनिवासी के दर्जे को यथावत बनाए रखना चाहते हैं तो वे देश में कम दिन बिता पाएंगे। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग 182 दिन के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे थे। नांगिया एंडरसन कंसल्टिंग के निदेशक शैलेश कुमार ने कहा, 'बहुत से लोग किसी वर्ष में ज्यादातर समय भारत में बिताते थे और यहीं से अपना कारोबार करते थे। लेकिन वे भारत में अपने ठहराव का इस तरह से प्रबंधन कर रहे थे कि वे भारत में कर चुकाने से बच जाते थे। अब इस पर अंकुश लगाने के लिए समय-सीमा कम की गई है।'

कर प्राधिकरणों ने पिछले साल के आयकर फॉर्मों में एक कॉलम शुरू किया था। पीआईओ और भारतीय नागरिक जो अनिवासी हैं, उन्हें भारत में बिताए गए दिनों की जानकारी देनी होगी। आव्रजन विभाग ये सूचनाएं सहेजकर रखता है। पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर और लीडर (व्यक्तिगत कर) कुलदीप कुमार ने कहा, 'आप अपने आयकर फॉर्म में भारत में ठहरने की जो सूचनाएं भरते हैं, उनका आव्रजन विभाग के पास मौजूद सूचनाओं से सत्यापन किया जा सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप सही जानकारी मुहैया कराएं।'

730 दिन का खंड हटाया

जब यह फैसला हो जाता है कि कोई व्यक्ति निवासी है या नहीं तो यह पता करने की जरूरत होती है कि वह निवासी सामान्य निवासी (आरओआर) है या निवासी लेकिन सामान्य निवासी (आरएनओआर) है। इस समय उसे उस स्थिति में आरएनओआर माना जाता है, जब वह दो मापदंडों को पूरा करता है। ये मापदंड हैं- वह पिछले सात वित्त वर्षों में भारत में 730 दिन से कम रहा हो या वह पिछले 10 वर्षों में 9 वर्षों में अनिवासी रहा हो। बजट प्रस्तावों में 730 दिन के मापंदड को खत्म कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 वर्षों में सात वर्षों में भारत में अनिवासी रहा है तो वह आरएनओआर बन जाएगा। यह बदलाव उन प्रवासियों को प्रभावित करेगा, जो भारत में काम करने के लिए आते हैं।

पहले वे तीसरे या चौथे साल में आरओआर बन जाते थे। अब वे पांचवें साल में आरओआर बन पाएंगे। इसका मतलब है कि अब उनकी वैश्विक आमदनी पर भारत में कर लगने से पहले उन्हें एक साल अतिरिक्त मिलेगा। अरीटी कंसल्टेंट्स एलएलपी में पार्टनर रूपाली सिंघानिया ने कहा, 'असल में सरकार ने भारत में काम करने के लिए आने वाले प्रवासियों के लिए नियम आसान बनाए हैं।'

डीम्ड निवास का प्रावधान लागू

अगर कोई भारतीय नागरिक अन्य किसी बाहरी देश में अपने मूल निवास या निवास के चलते कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। नांगिया एंडरसन कंसल्टिंग के कुमार कहते हैं, 'यह प्रावधान उन लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए शुरू किया गया है, जो किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं।' भारत के बहुत से लोग संयुक्त अरब अमीरात में काम करते हैं। उन्हें वहां होने वाली आमदनी पर भारत में कर देना पड़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर काफी हो-हल्ला होने के बाद सरकार ने साफ किया कि वह असली कामगारों पर कर नहीं लगाना चाहती है। हालांकि आगे के ब्योरे अभी आने हैं।

डीम्ड निवास के प्रावधान से दोहरे निवास की समस्या पैदा हो सकती है। सिंघानिया ने कहा, 'ऐसे मामलों में दोहरा कराधान निरोधक समझौता (डीटीएए) के तहत आने वाले टाई-ब्रेकर नियमों को व्यक्ति का निवास तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।' टाई ब्रेकर नियम के तहत कुछ अहम मापदंडों में स्थायी घर, व्यापक हितों का केंद्र, आदतन ठिकाना और व्यक्ति की राष्ट्रीयता आदि शामिल हैं।

किसे फायदा, किसे नुकसान

जो लोग कारोबार करते हैं और यह कई देशों में फैला हुआ होता है या काम के सिलसिले में देश के बाहर जाते हैं तो वे एक साल में काफी समय देश के बाहर बिताते हैं। उन्हें भविष्य में अपना कार्यक्रम सोच-समझकर बनाना होगा। बहुत से एनआरआई, विशेष रूप से पुराने एनआरआई जो ऐसे किसी क्षेत्र में रहते हैं, जहां कड़ी ठंड पड़ती है और वे वर्ष का आधा समय भारत में बिताते हैं। अगर वे अपना अनिवासी का दर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें भारत में बिताए गए समय को घटाना होगा।

जब व्यक्ति अपना अनिवासी का दर्जा गंवा देता है तो उसे अपने धन के प्रबंधन में बदलाव करना होता है। प्लान अहेड वेल्थ एडवाइजर्स के मुख्य वित्तीय योजनाकार विशाल धवन ने कहा, 'जब आप निवासी बन जाते हैं तो नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) और फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (एफसीएनआर) खातों पर कर लगने लगता है।' इन खातों को निवासी खातों में तब्दील कर दिया जाएगा।

इसका सकारात्मक पहलू यह है कि अप्रवासियों को नहीं मिलने वाली वित्तीय योजनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 7.75 फीसदी बचत (कर योग्य) बॉन्ड और सार्वजनिक भविष्य निधि (15 साल से अधिक बढ़ाई जा सकती है)।

आयकर दरों में बदलाव व्यक्ति के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो उसके निवास के देश पर निर्भर करता है। धवन ने कहा, 'संयुक्त अरब अमीरात में कोई कर नहीं लगता है, इसलिए भारत में कर की दरें अधिक होंगी। दूसरी ओर कुछ यूरोपीय देशों में कर की दरें भारत से भी अधिक हैं, इसलिए व्यक्ति के भारत का निवासी बनने से फायदा होगा।'

बीमा कंपनियां

प्रायोगिक योजनाओं में पॉलिसी के सटीक दाम

संजय कुमार सिंह

तीन बीमा कंपनियां मोटर फ्लोटर पॉलिसी के लिए प्रायोगिक योजनाएं चलाएंगी

इस समय आप जो स्वास्थ्य या मोटर बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, उनकी कीमत तय करने का कोई सटीक पैमाना नहीं है। उदाहरण के लिए कार का मालिक इस आधार पर प्रीमियम चुकाता है कि उसकी कार किस प्रकार की है और कितनी पुरानी है। स्वास्थ्य बीमा का ग्राहक अपने आयु वर्ग के आधार पर प्रीमियम का भुगतान करता है। लेकिन अब तकनीक की मदद से किसी व्यक्ति के व्यवहार या उसके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर बीमा कवर की कीमत तय करना मुमकिन है।

हाल में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अपने रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत 33 उत्पादों एवं सेवाओं को मंजूरी दी है। कंपनियां इन योजनाओं को प्रायोगिक आधार पर छह महीने के लिए चलाएंगी। अगर वे कारगर रहती हैं तो आईआरडीएआई सभी कंपनियों को इन मापदंडों पर आधारित नियमित पॉलिसी शुरू करने की मंजूरी देगा।

पहला सवाल यह पैदा होता है कि अगर ग्राहक को इन प्रायोगिक योजनाओं की पेशकश की जाती है तो क्या उन्हें इन्हें खरीदना चाहिए। सिक्योर नाऊ इंश्योरेंस ब्रोकर के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक कपिल मेहता ने कहा, 'अगर यह इस मापदंड को छोड़ा भी जाता है तो आपको वे लाभ दिए जाएंगे, जिनका आपको वादा किया गया है।' आपको नो-क्लेम बोनस, छूट या पुरस्कार का लाभ मिलेगा। हालांकि सुरक्षा के लिए पॉलिसी के नियम एवं शर्तों को जांचें। यहां ऐसे कुछ रोचक विचार पेश किए जा रहे हैं, जिनका परीक्षण किया जाएगा।

वाहन बीमा

आठ सामान्य बीमा कंपनियां वाहन के चलने के आधार पर कवर का परीक्षण करेंगी। उदाहरण के लिए एको जनरल इंश्योरेंस ग्राहकों को वाहन के चलने (1,000 से 12,000 किलोमीटर तक का दायरा) के आधार पर मोटर कवर खरीदने का विकल्प देगी। एको जनरल इंश्योरेंस के उत्पाद रणनीति प्रमुख अनीमेश दास ने कहा, 'जो कार मालिक एक साल में अपनी कार बहुत अधिक नहीं चलाते हैं, उन्हें अब से कम प्रीमियम चुकाना पड़ेगा।'

किलोमीटर मापने के अलावा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बीमा योजना में गाड़ी चलाने की गुणवत्ता का भी आकलन किया जाएगा। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख (अंडरराइटिंग, दावे, पुनर्बीमा और एक्चुअरी) संजय दत्ता ने कहा, 'हम गाड़ी चलाने की गुणवत्ता के आकलन में तकनीक इस्तेमाल करेंगे। अच्छे चालकों को बेहतर रेटिंग मिलेगी, जिससे बीमा कवर की लागत में फायदा मिलेगा।' ठीक से गाड़ी नहीं चलाने वाले चालकों को इस बीमा योजना से दूर रहना चाहिए।

आईआरडीएआई ने हाल में अपने रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत 33 उत्पादों एवं सेवाओं को मंजूरी दी

तीन बीमा कंपनियां मोटर फ्लोटर पॉलिसी के लिए प्रायोगिक योजनाएं चलाएंगी।तीन बीमा कंपनियां मोटर फ्लोटर पॉलिसी के लिए प्रायोगिक योजनाएं चलाएंगी। जिस व्यक्ति के पास कई वाहन हैं, वह एक ही पॉलिसी से सभी के लिए कवर ले सकेगा। इस कवर में प्रत्येक वाहन के लिए उप-सीमा होगी। दत्ता ने कहा, 'इससे ग्राहक एक ही तारीख को अपने सभी वाहनों के कवर का नवीनीकरण करा सकेगा।' उन्हें कीमत का लाभ भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य बीमा

दोस्तों का बीमा एक ऐसा अनोखा विचार है, जिसका परीक्षण किया जाएगा। इस समय किसी फ्लोटर कवर में केवल परिवार के सदस्यों को ही शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब दोस्तों को भी शामिल करने की मंजूरी होगी। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ आशीष मेहरोत्रा ने कहा, 'इसमें एक साथ कई लोगों का बीमा होगा, इसलिए प्रीमियम में छूट की पेशकश की जाएगी। इससे यह व्यक्तिगत पॉलिसी की तुलना में सस्ती हो जाएगी।' इस तरह की पॉलिसी के प्रीमियम में 10 फीसदी तक की छूट दी जा सकती है। एक स्वास्थ्य कोच और वियरेबल डिवाइस पैदल चलने के कदमों और सोने के तरीके की निगरानी करेगा। समूह के समग्र स्कोर से रिवॉर्ड या पॉलिसी के नवीनीकरण के समय छूट तय होगी। अपने समूह के सदस्यों को चुनने का अहम मापदंड स्वास्थ्य की स्थिति और व्यायाम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर भी कवर की पेशकश की जाएगी। मौजूदा व्यवस्था में प्रीमियम उम्र पर निर्भर करता है, जिसमें स्वस्थ ग्राहकों को कम स्वस्थ ग्राहकों के लिए अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। मेहरोत्रा ने कहा, 'इस योजना में जिन लोगों का स्कोर बेहतर होगा, उन्हें कम प्रीमियम चुकाना होगा।' जिन लोगों को पहले से कोई शारीरिक परेशानी है, उनके सह भुगतान आधारित योजनाएं एक स्वागत योग्य विचार है। मेहता ने कहा, 'जिन लोगों को कोई शारीरिक परेशानी है, वे कवर नहीं ले पाते हैं। यह योजना उनके लिए कारगर रहेगी।'

ई-वसीयत किफायती विकल्प लेकिन हर किसी की जरूरत नहीं होगी पूरी

यह विशेष स्थितियों या जहां मुकदमेबाजी का जोखिम है, उनमें उपयुक्त नहीं होने के आसार

सर्वजित के सेन

अगर आपके पास संपत्तियां हैं, जिनके आपकी मृत्यु के बाद दावेदार होंगे तो एक वसीयत लिखना जरूरी हो जाता है। वसीयत में लाभार्थियों के नाम दिए जाएं और यह बताया जाए कि संपत्तियों का कैसे बंटवारा होना चाहिए। बहुत से लोग इस प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई के डर से वसीयत लिखने से बचते हैं। हालांकि ई-वसीयत शुरू होने से वसीयत लिखना आसान हो गया है। ई-वसीयत लिखना किफायती और त्वरित विकल्प है, लेकिन इससे हर किसी की जरूरत पूरी नहीं होने के आसार हैं।

ऐसे में किसे ई-वसीयत का विकल्प चुनना चाहिए? यह उस व्यक्ति के लिए है, जिसके लिए वकील ढूंढना आसान नहीं है और उनकी सेवाएं लेना मुश्किल और महंगा है। टेरेंशिया कंसल्टेंट्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक संदीप नेरलेकर ने कहा, 'अगर संपत्तियां साफ-सुथरी हैं, उनमें कोई पेच नहीं है और न ही मुकदमेबाजी का डर है तो व्यक्ति ई-वसीयत के विकल्प के बारे में विचार कर सकता है।

ऐसे कई सेवा प्रदाता हैं, जो ई-वसीयत लिखने की सुविधा देते हैं। इनमें प्रमुख विलजिनी डॉट कॉम, दिलसेविल, माई विल, टेरेंशिया कंसल्टेंट्स, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं। इनहेरिटेंसनीड्स डॉट कॉम के संस्थापक रजत दत्ता ने कहा, 'संभावित वसीयतकर्ता को बुनियादी ब्योरे भरने पड़ते हैं, वसीयत का प्रकार चुनना पड़ता है और अग्रिम फीस का भुगतान करना होता है। ये पोर्टल मानक डेटा या सूचना फॉर्म रखते हैं, जिन्हें संभावित वसीयतकर्ता को भरना पड़ता है। उसके बाद उसे कुछ मानक सवालों का जवाब देना पड़ता है।' इस वसीयत की वकील समीक्षा करते हैं। अगर कोई बदलाव है तो यह वसीयतकर्ता के साथ चर्चा के बाद किया जाता है और फिर अंतिम वसीयत तैयार की जाती है।

अपनी तैयारी करें

ऑनलाइन वसीयत तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती हैं। अपनी सभी संपत्तियों की एक सूची तैयार रखें। इनमें रियल एस्टेट, कीमती चीजें और आभूषण जैसी भौतिक संपत्तियां शामिल होंगी। इसके साथ ही आपकी वित्तीय संपत्तियों की पूरी जानकारी रखें। लाभार्थियों की सूची भी तैयार होनी चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह पता नहीं होगा कि आपके पास क्या है और आप किसे क्या देना चाहते हैं।

इसके अलावा संपत्तियों पर अपने स्वामित्व को लेकर सुनिश्चित रहें। उदाहरण के लिए माना कि आप अपना घर अपने बड़े बेटे को देने का फैसला करते हैं। लेकिन असल में घर पर आपकी पत्नी और आपका स्वामित्व है। उस स्थिति में वसीयत होने के बावजूद घर में आपका हिस्सा ही आपके बड़े बेटे को मिल पाएगा। आप उस चीज को किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, जिस पर आपका मालिकाना हक नहीं है।

वसीयत में एक्जीक्यूटर का नाम लिखा जाना चाहिए। आपने जिस व्यक्ति को चुना है, उसे पहले ही इसके बारे में सूचित करें और उसकी मंजूरी लें। दस्तावेज की एक मुद्रित प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षरों की जरूरत होगी। अगर संभव है तो वसीयत पर अपने चिकित्सक के हस्ताक्षर कराने की कोशिश करें ताकि वसीयत के समय आपकी मनोस्थिति को लेकर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा वसीयत पर हस्ताक्षर करने की वीडियोग्राफी कराएं। वसीयत पर हस्ताक्षर होने के बाद इसे पंजीकृत कराएं। नेरलेकर ने कहा, 'वसीयत पर वसीयतकर्ता और दो गवाहों के हस्ताक्षर होने के बाद आपको इसे पंजीकृत कराना चाहिए। हालांकि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।'

- वसीयत में लाभार्थियों के नाम दिए जाएं और यह बताया जाए कि संपत्तियों का कैसे बंटवारा होना चाहिए
- ई-वसीयत शुरू होने से वसीयत लिखना आसान हो गया है
- ई-वसीयत लिखना किफायती और त्वरित विकल्प है
- विलजिनी डॉट कॉम, दिलसेविल, माई विल, टेरेंशिया कंसल्टेंट्स, एचडीएफसी सिक्योरिटीज और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ऐसे कई सेवा प्रदाता हैं, जो ई-वसीयत लिखने की सुविधा देते हैं
- वसीयत की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए अगर बड़े बदलावों की जरूरत है तो नई वसीयत लिखें

वसीयतकर्ता पर निर्भर

ई-वसीयत जल्द और आसानी से तैयार की जा सकती है, लेकिन इसमें उल्लिखत सूचनाओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए। सेवा प्रदाता को आपकी संपत्तियों के बारे में कुछ नहीं पता है। दत्ता ने कहा, 'सूचना एवं डेटा वसीयतकर्ता भरता और मुहैया करता है। इसमें मुहैया कराई गई सूचनाओं की कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाती है। यह प्रक्रिया वसीयतकर्ता की भावना को पकड़ने के लिहाज से ज्यादा औपचारिक और कम संवादात्मक है। यह प्रारूप मानक वसीयतों का होता है, इसलिए विशेष बच्चों वाले माता-पिता, बिना बच्चों वाले परिजनों या बिना भाई-बहन वाले वसीयतकर्ता जैसी विशेष स्थितियों के लिए प्रावधान नहीं होते हैं।'

जटिलता पर निर्भर शुल्क

ई-वसीयत का शुल्क इस चीज पर निर्भर करता है कि आप सेवा प्रदाता से कितनी विशेषज्ञ मदद लेते हैं। बुनियादी ई-वसीयत 1,500 रुपये से शुरू होती है और यह 50,000 रुपये या उससे भी अधिक हो सकती है। अगर आप कॉल करने पर जानकारी दिए जाने की उम्मीद करते हैं तो लागत अधिक होने के आसार हैं। अगर आप वसीयत ऑफलाइन तैयार करते हैं तो लागत और अधिक हो सकती है। नेरलेकर ने कहा, 'यह निश्चित रूप से एक सस्ता विकल्प है। अगर संपत्तियां अधिक, जटिल और कई खंडों से संबंधित हैं और मुकदमेबाजी के आसार हैं तो व्यक्ति को ऑफलाइन वसीयत के बारे में विचार करना चाहिए। अन्य सभी मामलों में ऑनलाइन वसीयत के बारे में भी विचार किया जा सकता है।' दत्ता का मानना है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन वसीयत में से एक चुनते समय मुख्य मापदंड लागत नहीं होना चाहिए। दत्ता ने कहा, 'वसीयतकर्ता को यह फैसला लेना चाहिए कि क्या कीमत इतनी अहम है कि वह अपने परिवार की विरासत को लेकर कोई दांव लगा सकते हैं।'

वसीयत को करें अद्यतन

कई बार व्यक्ति वसीयत लिखते हैं, लेकिन उसे अद्यतन नहीं करते हैं। किसी भी वसीयत की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। कोडिसिल के जरिये छोटे-मोटे बदलाव किए जा सकते हैं। अगर वसीयत में बड़े बदलावों की जरूरत है तो नई वसीयत लिखें। कई वसीयत होने की स्थिति में सबसे नई वसीयत को वैध माना जाएगा। वसीयत को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वसीयत के ब्योरों के बारे में परिवार के सदस्यों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि यह कहां रखी है।

ट्रंप की यात्रा के लिए तैयार अहमदाबाद

चंद घंटे की इस यात्रा के लिए किए गए काफी बदलाव, स्थानीय होटल उद्योग की बुकिंग में खासी तेजी देखी जा रही है

विनय उमरजी

अहमदाबाद के लिए इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के वाणिज्यिक शहर अहमदाबाद ने इससे पहले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की थी और अब यह अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की आगवानी के लिए तैयार है। सोमवार को अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम में जाने से पहले ट्रंप और मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से 22 किलोमीटर के रोड शो में भाग लेते हुए साबरमती आश्रम तक पहुंचेंगे। इस नवनिर्मित स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हैं जहां 1,10,000 लोगों के बैठने की जगह है। इस स्टेडियम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम 'नमस्ते ट्रंप' का आयोजन किया जाएगा जैसा कि पिछले सितंबर में अमेरिका के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' नाम के इवेंट का आयोजन हुआ था।

अहमदाबाद की सड़कों पर लगे मोदी और ट्रंप के विशाल कटआउट

तैयारी पूरी

अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की यह पहली भारत यात्रा है और अहमदाबाद प्रशासन उन्हें प्रभावित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसी अटकलें हैं कि शायद ट्रंप साबरमती आश्रम न जा पाएं। गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के अधिकारियों का कहना है कि रोड शो के मार्ग में करीब 28 स्टेज बनाए जा रहे हैं जहां गांधी के जीवन और भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि 50,000 पेड़ों और पौधे को करीब 50 लाख रुपये की लागत से खरीदा गया है। निगम में पार्क्स ऐंड गार्डन्स के निदेशक जिग्नेश पटेल कहते हैं, 'ऐसा नहीं है कि ये पौधे केवल इसी इवेंट के लिए लगाए जा रहे हैं। यह हमारी योजना का हिस्सा है हालांकि इसे 24 फरवरी से पहले लगाया जा रहा है।' हालांकि रोड शो वाले ज्यादातर मार्ग में मेट्रो रेल निर्माण कार्य की वजह से बाधाएं हैं। एक निवासी में विट्ठल का कहना है, 'मोदी और ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए कि यह खराब सड़क अब राजमार्ग की तरह दिखता है।'

यहां के स्थानीय होटल उद्योग में बुकिंग में भी तेजी दिख रही है और इस इवेंट से पहले कोई पूछताछ कर रहा है। लक्जरी होटलों मसलन हयात और हिल्टन के डबल ट्री की बुकिंग प्रतिनिधिमंडल और अन्य मेहमानों के लिए की गई है। यहां 21 फरवरी से 24 फरवरी के बीच होटलों की बुकिंग दर 95 फीसदी तक है।

सरकार भी इस अति विशिष्ट यात्रा के लिए सुरक्षा के इंतजाम में कोई कसर नहीं रखना चाहती है। यहां 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों, 25 आईपीएस अधिकारियों, 65 सहायक पुलिस आयुक्तों, 200 पुलिस निरीक्षक और 800 सब-इंस्पेक्टर को शहर में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा त्वरित कार्रवाई बल की दो कंपनियां और राज्य रिजर्व बल की 10 कंपनियां लगाई जा रही हैं। मोटेरा स्टेडियम के भीतर भी 4,500 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।

अतिविशिष्ट मार्गों और स्थलों पर 120 डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। 240 हाथ में पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर्स, 200 क्लोज्ड सर्किट कैमरा और 120 स्कैनिंग मशीन लगी हुई है जिनकी निगरानी 300 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस विशेषज्ञ करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयर फोर्स वन के अलावा एक अन्य विमानन और छह कार्गो प्लेन भी होंगे। बोइंग सी-17 ग्लोबमास्टर 3 पहले ही सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर आ चुका है।

ट्रंप ने दावा किया है कि हवाईअड्डे से स्टेडियम तक उनके रोड शो से 70 लाख लोग जुटेंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि अहमदाबाद की कुल आबादी ही करीब 75 लाख है। एएमसी के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती अनुमान 50,000 लोगों का है और इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। एएमसी ने लघु एवं मध्यम उद्यमों, रियल एस्टेट डेवलपर्स, गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से कहा है कि वे अपने सदस्यों और कर्मचारियों को रोड शो में हिस्सा लेने के लिए कहें।

ट्रंप की यात्रा की पुष्टि होने के बाद से ही स्टेडियम का निर्माण बड़ी तेजी से होने लगा। इस हफ्ते ही स्टेडियम इस्तेमाल का प्रमाणपत्र मिला है। शहर को सुंदर बनाने के लिए 4 फुट ऊंची दीवार झुग्गी झोपड़ियों को ढंकने के लिए बनाई गई। इस दीवार को ढंकने के लिए 150 पौधे भी लगाए गए हैं। यहां के निवासियों का कहना है कि यहां केवल एक संकरा रास्ता है जहां से प्रवेश और निकास करना काफी मुश्किल होता जा रहा है।

मोटेरा के नजदीक दुकान, प्रतिष्ठान और वेंडरों का जीवन और कारोबार भी प्रभावित हो गया है। स्टेडियम तक जाने वाली सड़कों को चौड़ा करने के लिए कुछ दुकानों और मकानों के मुख्य हिस्से को तोड़ दिया गया है। हाल में कैबिनेट बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अधिकारियों को आम नागरिकों को हुई परेशानी से जुड़ी रिपोर्ट मिलने पर फटकार भी लगाई।

मोटेरा में सब्जी बेचने वाले वाडीलाल डाभी का कहना है कि उन्हें और कई दूसरे वेंडरों को 10 दिनों तक के लिए दुकान बंद करने को कहा है। इसकी वजह से उन्हें रोजाना 600 से 800 रुपये का नुकसान हो रहा है। ट्रंप अहमदाबाद में महज कुछ घंटे रहेंगे लेकिन इसके लिए शहर में कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं।

दक्षिण कोरिया में हाई अलर्ट जारी

चीन से बाहर कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने को लेकर रविवार को चिंता बढ़ गई क्योंकि दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान जैसे देशों में संक्रमण के मामले में तेज बढ़ोतरी हुई। संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही दक्षिण कोरिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 600 हो गई जबकि छह लोगों की मौत हो गई। इटली में संक्रमण के मामले बढ़कर 132 हो गए और देश के कई हिस्से में सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। ईरान में संक्रमण के 43 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। चीन में संक्रमण के 648 नए मामले की पुष्टि की गई जबकि हुबेई प्रांत के बाहर महज 18 लोगों के संक्रमित होने के पुष्टि हुई जो वायरस संक्रमण के केंद्र से बाहर संक्रमण की सबसे कम तादाद है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वायरस संक्रमण को रोकने का उपाय प्रभावी रहा है हालांकि इस पर नियंत्रण अब भी नहीं हो सका है। सरकारी चैनल पर लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थलों या किसी पर्यटन स्थल पर मास्क पहने बगैर न इकट्ठा हों।

दक्षिण कोरिया के देगु में कीटाणु-नाशक का छिड़काव करते कर्मचारी

कोरोनावायरस की वजह से चीन में 2,442 लोगों की मौत हो गई है जबकि संक्रमण के 76,936 मामले की पुष्टि हो चुकी है जिससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वायरस का संक्रमण 26 अन्य देशों में भी फैल चुका है और चीन से बाहर मरने वालों की तादाद दो दर्जन हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शनिवार को कहा कि चीन से सीधे संबंध के बगैर भी संक्रमण के मामले की पुष्टि होना भी काफी चिंताजनक है।

चीन के बाहर किसी देश में अगर कोरोनावायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं तो वह दक्षिण कोरिया है। यहां के राष्ट्रपति मून जेई-इन ने कहा कि सरकार विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर अलर्ट को उच्चतम स्तर पर बढ़ाया है और प्रभावित देगु और चेओंगडो शहर में अतिरिक्त संसाधन भेजे जा रहे हैं जिसे विशेष सावधानी वाले क्षेत्र में रखा गया है। डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा है। रविवार को, दक्षिण कोरिया ने दो मौतों के साथ 123 नए मामले सामने आने की जानकारी दी।

जापान में कोरोनावायरस के 750 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 634 मामले डायमंड प्रिंसेस पोत के हैं। यह जहाज योकोहामा में समुद्र तट पर अलग रखा गया है। इस पोत पर चालक दल के चार भारतीय सदस्य कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि इसी के साथ पोत पर सवार संक्रमित भारतीयों की कुल संख्या 12 हो गई है।

इटली यूरोप में पहला देश है जहां शुक्रवार को कोरोनावायरस से उसके एक नागरिक की मौत का मामला सामने आया। इसके बाद करीब 12 शहरों में यात्रा पाबंदियां लगा दी गईं। इन शहरों में इस संक्रामक बीमारी के चपेट में आने के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

एजेंसियां

ट्रंप के लिए खासतौर पर संवर रहा है ताजमहल

डॉनल्ड ट्रंप की बेटी और दामाद भी भारत यात्रा पर आ रहे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं

श्रेया जय

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के स्वागत में आगरा की सड़कों के किनारे सैकड़ों होर्डिंग लगे हैं जो शहर में मिठाई के मशहूर ब्रांड 'पंछी पेठा' के होर्डिंग को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ताजगंज में इसकी एक ब्रांच के मालिक ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अपनी मिठाइयों की नुमाइश नहीं करेंगे। ट्रंप अपनी पत्नी मिलेनिया के साथ सोमवार को ताजमहल को देखने आएंगे और इस दौरान ताज परिसर में मौजूद सभी दुकानें बंद रहेंगी।

ट्रंप की इस संक्षिप्त यात्रा से कारोबार को होने वाले नुकसान के बावजूद आगरा के लोग खुश हैं। ड्वाइट डी आइजनहावर से लेकर बिल क्लिंटन तक, भारत आने वाले सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ताज का दीदार किया और उसकी पृष्ठभूमि में तस्वीरें खिंचवाई। और अब ताजमहल ट्रंप की अगवानी के लिए करीब-करीब तैयार है।

पूरे शहर में लगे होर्डिंग पर लिखे गए संदेशों से तैयारी की थाह मिलती है। इनमें लिखा है, 'राम और कृष्ण की भूमि में आपका स्वागत है', 'उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से आपका अभिनंदन', 'भारी निवेश के अवसरों की भूमि में आपका स्वागत है' आदि। यह अलग बात है कि ट्रंप भारत में साथ व्यापार और कारोबारी समझौतों के बारे में पिछले कुछ दिनों से भ्रामक संकेत दे रहे हैं। एक अच्छे मेजबान की तरह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने मेहमान को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दुनिया में प्यार की अनोखी निशानी माने जाने वाले मुगलकालीन स्मारक ताजमहल के आसपास के इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया गया है।

शनिवार को हमने देखा कि माली से लेकर मिस्त्री तक हर कोई जल्दी से जल्दी काम करने में जुटा है। माली जहां घास को सितारे (मुगल वास्तुकला की एक खूबी) की शक्ल देने में मशगूल थे वहीं मिस्त्री टूटी हुई टाइलों और चू रहे फव्वारों को दुरुस्त करने में व्यस्त थे। कुछ लोग पान की पीक साफ करने में जुटे हुए थे।

रविवार को आगरा के ताजमहल में सुरक्षाकर्मियों की बढ़ गई तादाद

अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के आगरा हवाई अड्डे पहुंचने के बाद उनका काफिला सीधे ताजमहल पहुंचेगा के प्रवेश द्वार पर पहुंचेगा। वहां से बिजली से चलने वाली गोल्फ कार्ट के सुरक्षा घेरे में ट्रंप दंपती सफेद संगमरमर से बने इस अनोखे स्मारक का अवलोकन करेंगे। ट्रंप के भारत दौरे में उनकी बेटी और दामाद भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने करीब 20 इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को अपने पास रख लिया है जिनका इस्तेमाल सोमवार को अति विशिष्ट लोगों को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा। इनके चालकों का चयन परीक्षण के जरिये किए गया है। लेकिन करीब दो दर्जन कार्ट की कमी के कारण ताज का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही है। उन्हें बची खुची कार्ट और ई-बसों से ही गुजारा करना पड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण ताजमहल के परिसर में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी है। इस वजह से राज्य सरकार को पर्यटकों को पार्किंग क्षेत्र से ताजमहल तक लाने ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार्ट और बसें चलानी पड़ी थीं।

ताजमहल के भीतर कुछ अलग ही नजारा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के बदलते कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। एएआई के एक अधिकारी ने कहा, 'पहले वह ओबेरॉय अमरविलास होटल से आ रहे थे। अब हमें बताया गया है कि वह हवाईअड्डे से सीधे ताजमहल पहुंचेंगे।' हालांकि उनका अंतिम कार्यक्रम अब भी तय नहीं है। हालांकि ताज परिसर में दुकानें बंद रहेंगी और पर्यटक केवल दोपहर बाद दो बजे तक की ताजमहल का दीदार कर पाएंगे। इसके बाद परिसर को खाली कर दिया जाएगा। अधिकारी ट्रंप के दौरे के लिए किए जा रहे विशेष इंतजामों के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।

बीएस बातचीत

कारोबारी फैसलों को टाल नहीं पाएगा भारत

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से वास्तविक लाभ होने के आसार कम हैं, लेकिन कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनैशनल पीस के सीनियर फैलो और अमेरिका में राजनीतिक मामलों के अंडरसेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार **एश्ले टेलिस** ने **आदिति फडणीस** को बताया कि भारत लंबे समय तक अमेरिका के साथ अपने अहम कारोबारी और अन्य फैसलों को नहीं टाल पाएगा। बातचीत के संक्षिप्त अंश:

आपके अनुमान से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के क्या नतीजे रहेंगे?

राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को अमेरिकी-भारतीय रणनीतिक साझेदारी की ताकत के रूप में दिखाना चाहते हैं। आम तौर पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा के यही उद्देश्य होते हैं। लेकिन यह यात्रा ट्रंप के कुछ अलग मिजाज का राष्ट्रपति होने और अमेरिका के धनी वर्ग का भारत को लेकर नजरिया बदलने की वजह से विशेष है। ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे से भारत की अमेरिका से अधिक सहयोग की उम्मीदें टूट सकती थीं, लेकिन ट्रंप की इस नीति का भारत पर उतना असर नहीं पड़ा, जितना पड़ सकता था। ऐसे में मोदी इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि उनके ट्रंप के साथ लगातार जुड़ाव का कम से कम अब तक फायदा मिला है। ट्रंप के लिए महत्त्वपूर्ण कारोबारी सौदे पर भारत के सहमत नहीं होने के बावजूद वह भारत आ रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है, 'भारत का हमारे प्रति रुख बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करता हूं।'

ऐसे में क्या ट्रंप की यह यात्रा महज औपचारिकता है?

दोनों नेता अपने-अपने देशों की जनता और अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों को रणनीतिक भागीदारी दिखा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस यात्रा में रणनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा पर जोर दिया जाएगा। मेरा मानना है कि भारत ट्रंप को यह दिखाना चाहेगा कि वह अमेरिकी ऊर्जा की खरीद बढ़ाकर और तीसरी दुनिया के देशों में विकास परियोजनाओं में सहयोगी बनकर अमेरिका का अच्छा आर्थिक साझेदार बनना चाहता है, इसलिए केवल औपचारिकता के बजाय कुछ ठोस नतीजे आएंगे।

भारत सरकार के घरेलू राजनीतिक एजेंडे से भारत-अमेरिका के संबंध कितने प्रभावित हुए हैं?

यह एक जटिल सवाल है क्योंकि मोदी सरकार के एजेंडे में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे शामिल हैं। ऐसा लगता है कि मौजूदा भारत सरकार का विदेशी व्यापार को लेकर रुख आयात के विकल्पों और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है। इससे ट्रंप काफी नाखुश है। मैं इस बात से अचंभित हूं कि ट्रंप यह जानते हुए भी भारत आ रहे हैं कि कारोबारी सौदे को लेकर अनिश्चितता है। ऐसा लगता है कि मोदी के करिश्मे और राजदूत केन जस्टर की वकालत के बाद वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपने लक्ष्यों को नहीं भूले हैं और यदि अमेरिकी प्रशासन जिन छोटे मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, उनका समाधान नहीं हुआ तो यात्रा के बाद की स्थितियां यात्रा जितनी सुखद नहीं होंगी। अगर ट्रंप फिर से चुने जाते हैं तो मोदी सरकार इन मुद्दों के समाधान से बच नहीं पाएगी।

हाल में भारत के घरेलू राजनीतिक घटनाक्रमों से भी अमेरिकी प्रशासन में चिंताएं पैदा हुई हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इसे सार्वजनिक रूप से मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। इस सार्वजनिक चुप्पी को लेकर यह नहीं माना जाना चाहिए कि कोई चिंता नहीं है,

चित्रांकन: बिनय सिन्हा

लेकिन चिंताएं सभी लोगों में अलग-अलग हैं। कांग्रेस, प्रेस और एनजीओ में भारत सरकार की नीतियों को लेकर नाखुशी जाहिर है। लेकिन मैं इन प्रतिक्रियाओं को फिलहाल भारत-अमेरिकी संबंधों में घातक नहीं मानता हूं। लेकिन कार्यपालिका तथा विधायिका और रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट्स के बीच बढ़ती खाई को अगर कम नहीं किया गया तो दोनों देशों के संबंधों में बेहतरी मुश्किल होगी। हमें अमेरिका में भारत के साथ संबंधों को विवाद का एक नया विषय बनाने की जरूरत नहीं है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनाव के बावजूद भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते से पीछे नहीं हटे। क्या आपको लगता है कि उस बड़े राजनीतिक दांव के बाद भारत और अमेरिका को फायदा मिला? आखिर किसने किसे निराश किया?

इस सौदे को पूरा करने से कुछ बुनियादी उद्देश्य पूरे हुए, जिनकी हमने बुश प्रशासन के दौरान योजना बनाई थी। ये उद्देश्य थे- दशकों पुरानी उस सबसे बड़ी बाधा को खत्म करना, जिसने अमेरिका को लेकर भारत के संदेहों को पक्का किया था। भारत को अपने परमाणु हथियारों को त्यागे बिना अप्रसार संधि में शामिल करना था। प्रतिबंधित तकनीकों को ज्यादा उदार तरीके से साझा करने की मंजूरी देना ताकि चीन को संतुलित करने के लिए भारत की ताकत बढ़ाई जा सके। मैं कहना चाहूंगा कि ये सभी उद्देश्य संतोषजनक रहे हैं।

क्या यह सौदा ज्यादा भारत के पक्ष में था?

निश्चित रूप से, लेकिन यह जानबूझकर किया गया। कम से कम अभी तक हम जिस लक्ष्य में कामयाब नहीं हुए, वह अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की भारत को वाणिज्यिक बिक्री है। अमेरिकी प्रशासन में बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी कि भारत बड़ी संख्या में अमेरिकी रिएक्टर खरीदेगा। लेकिन भारत के परमाणु जिम्मेदारी कानून के कुप्रबंधन और फुकुशिमा त्रासदी के बाद यह और मुश्किल हो गया। मेरा अब भी मानना है कि हम भारत को रिएक्टरों की बिक्री करेंगे। जिस चीज में अन्य जगह वर्षों लगते हैं, उसके पूरे होने में भारत में दशकों लगते हैं। लेकिन जब आप अमेरिकी-भारतीय संबंधों पर असर को देखते हैं तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे मुख्य उद्देश्य पूरे हो गए। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करने, रक्षा व्यापार में बढ़ोतरी, हिंद महासागर में दोनों देशों के सक्रिय गठजोड़ जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ना उस फैसले को सही साबित करता है।

भारत-अमेरिका के बीच कारोबारी सौदा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत पहले ही आरसेप से बाहर हो चुका है। भविष्य में कारोबारी सौदा होने की कितनी संभावनाएं हैं और क्या इसका हमेशा अमेरिका फर्स्ट से टकराव नहीं होगा?

मोदी सरकार का अमेरिकी प्रशासन के साथ कारोबारी विवादों का समाधान नहीं कर पाना निराशाजनक है। यह भारत को महंगा पड़ सकता है। यह ट्रंप प्रशासन के तहत अप्रत्याशित सफल रणनीतिक साझेदारी के तहत एक नकारात्मक पहलू है। अन्य मामलों में ट्रंप ने अमेरिकी कारोबारी संतुलन को सही करने पर ध्यान दिया है। लेकिन इससे इतर ट्रंप ने भारत के साथ जिन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है, वे बहुत कम हैं और इन्हें मोदी के वृहद उद्देश्यों पर बड़े असर के बिना हल किया जा सकता है। लेकिन आर्थिक मंदी, मोदी सरकार के संरक्षणवादी पहलों और आत्मनिर्भरता के महत्त्वाकांक्षा की तरफ लौटने से भारत संतोषजनक समाधान नहीं ढूंढ पाया है। ई-कॉमर्स और डेटा को स्थानीय स्तर पर भंडारित करने जैसे बड़े मुद्दे भी सामने आ सकते हैं।